निदेशक मंडल

(यथा 30 जून 2005 को स्थिति)

श्री एस. एन. मेनन
सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री ए. के. झा
सचिव, औद्योगिक
नीति एवं संवर्धन विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

डॉ. अशोक के. लाहिरी
मुख्य आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

श्रीमती सूर्यकांति त्रिपाठी
अपर सचिव (ई आर)
विदेश मंत्रालय

श्री अमिताभ वर्मा
संयुक्त सचिव
बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय

श्रीमती के. जे. उदेशी
उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री वी. पी. शेट्टी
अध्यक्ष
इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि.

श्री पी. के. दाश
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

श्री ए. के. पुरवार
अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक

श्री के. चेरियन वर्गीज़
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

डॉ. विनयशील गौतम
प्रोफेसर
प्रबंधन अध्ययन विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नई दिल्ली

श्री एस. पी. ओसवाल
चेअरमैन
वर्धमान ग्रुप
लुधियाना

श्रीमती किरन मज़ूमदार शॉ
चेअरमैन एण्ड मैनेजिंग डायरेक्टर
बायोकॉन लि.
बैंगलोर

श्री ए. वेल्लयन
वाइस चेअरमैन
ई आइ डी पैरी (इंडिया) लि.
चेन्नै

गत दशक

(रुपये मिलियन में)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	संचयी (1995-2005)	वार्षिक औसत संवृद्धि %
ऋण												
मंजूरियाँ	24657	12421	18406	18380	28318	21743	42407	78283	92657	158535	495807	28
संवितरण	21300	12566	13704	12707	17296	18964	34529	53203	69575	114352	368196	27
ऋण आस्तियाँ [1]	29302	34513	38248	42641	50833	56443	68260	87736	107751	134104		18
गारंटियाँ												
मंजूर की गईं गारंटियां	2027	1365	4024	2633	4404	2118	5450	9328	10792	15887	58028	63
जारी की गईं गारंटियां	1731	1481	1912	2474	3017	1741	4164	7275	5743	16602	46140	51
गारंटी संविभाग	9081	10215	12094	10553	11147	10740	11273	16133	15769	23727		15
संसाधन												
प्रदत्त पूँजी	5000	5000	5000	5000	5500	5500	6500	6500	6500	8500		
आरक्षित राशियाँ	3997	5445	7058	8352	9584	10664	12026	13171	14933	16625		
अपरक्राम्य वचनपत्र, बाँड और डिबेंचर	8861	9165	8267	12850	20944	22915	33158	64902	76701	98972		
जमा राशियाँ	1404	660	371	104	2617	2797	3416	9121	20922	22023		
अन्य उधार राशियाँ	13346	20352	21808	21285	20354	20255	16619	16467	21583	21064		
कुल संसाधन	39694	49329	51201	56665	70264	73981	82734	123189	155192	184273		
निष्पादन												
कर पूर्व लाभ	1100	1516	2017	2400	2273	2047	2212	2686	3042	3144	22437	16
करोत्तर लाभ	1100	1516	2017	1650	1651	1541	1712	2066	2292	2579	18124	
लाभांश	200	310	410	330	350	380	420	450	470	654	3974	17
स्टाफ़ (संख्या) [2]	116	126	136	147	150	154	163	167	190	193		
अनुपात												
जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी अनुपात (%)	31.9	31.7	30.5	26.6	24.4	23.8	33.1	26.9	23.5	21.6		
पूँजी पर कर पूर्व लाभ (%)	23.4	30.3	40.3	48.0	43.3	37.2	36.9	41.3	46.8	41.9		
निवल संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%)	13.3	15.6	17.9	18.9	16.0	13.1	12.8	14.1	14.2	13.5		
आस्तियों पर कर पूर्व लाभ (%)	2.9	3.4	4.0	4.4	3.6	2.8	2.8	2.6	2.2	1.9		
प्रति कर्मचारी कर पूर्व लाभ (रुपये मिलियन में)	10.0	12.5	15.4	17.0	15.3	13.5	14.0	16.3	17.0	16.4		

1 ऋण आस्तियां भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी लि. द्वारा निपटाये गये दावों को घटाकर हैं तथा 1997-98 से प्रभावी हैं।

2 यह एक्ज़िम बैंक की सेवा में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है।

टिप्पणी : ये आँकड़े सामान्य निधि से संबंधित हैं।

अध्यक्ष का वक्तव्य

वर्ष 2004-05 की एक प्रमुख विशेषता उत्साहजनक निर्यात निष्पादन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में ज़ोरदार तेज़ी की प्रवृत्ति थी जो इसकी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और नीतिगत दिशा को दर्शाता है । निर्यात में वृद्धि, वैश्विक व्यापार में वृद्धि के अनुरूप रही है और यह वैश्विक बाज़ारों में भारतीय निर्यात की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता तथा निर्यात बाज़ारों में इसके विविधीकरण को दर्शाती है ।

लगातार वैश्वीकृत तथा उदारीकृत व्यापारिक वातावरण में उत्पन्न अवसरों के अनुरूप एक्ज़िम बैंक ने भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए तत्परतापूर्वक प्रयास किये हैं और साथ ही यह सुनिश्चित करने के प्रयास किये हैं कि बैंक के कार्यकलाप तथा वित्तपोषण पहल कार्य उद्योग और व्यापार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

व्यावसायिक पहलें

बाज़ार प्रवेश और साथ ही भारतीय निर्यात के विविधीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने भारत की परियोजनाओं, माल, तथा सेवाओं के निर्यात में सहायता देने के लिए कुल 423 मिलियन यू एस डॉलर की 16 ऋण-व्यवस्थायें प्रदान की हैं । इनमें भारत से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के वित्तपोषण के लिए सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को प्रदान की गई 150 मिलियन यू एस डॉलर की एक उत्पाद विशिष्ट ऋण-व्यवस्था शामिल है। बैंक के पास इस समय उपयोग के लिए कुल 953 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-वचनबद्धताओं के साथ एशिया, अफ्रीका, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, लैटिन अमेरिका तथा यूरोप में 68 देशों को शामिल करते हुए 44 ऋण-व्यवस्थाएँ प्रवर्तनशील हैं। कई अन्य ऋण-व्यवस्थाओं के बातचीत के विभिन्न चरणों में होने से बैंक ने भारत सरकार के बाज़ार विविधीकरण और वैश्विक व्यापार में वर्धित हिस्से के उद्देश्य के अनुरूप ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अंतर्गत भौगोलिक पहुँच तथा मात्रा को आक्रामक रूप से विस्तारित किया है ।

भारत से परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण तथा सुगमीकरण में एक प्रमुख संवाहक के रूप में एक्ज़िम बैंक ने वर्ष के दौरान 198 भारतीय निर्यातकों को 64 देशों में कुल 79.5 बिलियन रुपये मूल्य की 570 निर्यात संविदाएं प्राप्त करने में सहायता दी है । इन संविदाओं में परियोजना तथा सेवा निर्यात की संपूर्ण शृंखला जैसे सिविल निर्माण, टर्नकी, परामर्शी आदि और व्यापार वित्त उन्मुख आपूर्ति संविदाएं शामिल हैं । यह भारतीय परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं और संविदाकारों की चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी संविदाओं को निष्पादित करने की बढ़ती क्षमता का द्योतक है ।

बैंक ने परियोजना वित्त और ट्रेज़री परिचालनों के हिस्से के रूप में ईक्विटी संबंद्ध उत्पाद प्रदान करना शुरू किया है ।

भारतीय बाह्य निवेश में सहायता देने के बैंक के प्रयास के अनुरूप 11 कंपनियों को सात देशों में उनके समुद्रपारीय निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल 5.5 बिलियन रुपये की निधिक तथा गैर निधिक सहायता मंजूर की गई । अब तक बैंक ने 43 देशों में 100 से अधिक कंपनियों द्वारा स्थापित 122 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है ।

लघु एवं मध्यम आकार उद्यमों के निर्यातकों पर विशेष ध्यान देते हुए बैंक ने एक लघु एवं मध्यम आकार उद्यम समूह स्थापित करने की पहल की है । इसका उद्देश्य बैंक के लिए निर्यात उन्मुख लघु एवं मध्यम आकार उद्यमों के ग्राहकों का एक पोर्टफोलियो विकसित करना है ताकि इन ग्राहकों को ऋण की निर्बाध सुपुर्दगी की जा सके। वर्ष के दौरान बैंक ने इस पहल के अंतर्गत निर्यात उन्मुख लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को 1.3 बिलियन रुपये की ऋण सुविधायें मंजूर कीं जिनमें वस्त्र उद्योग, रेडीमेड वस्त्र, रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पुर्जे तथा इंजीनियरी माल जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं ।

लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को उनके भूमंडलीकरण प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के उद्यम प्रबंध विकास सेवा (ई एम डी एस) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आइ टी सी) के साथ एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए । आइ टी सी के साथ सहयोग व्यवस्था के हिस्से के रूप में एक्ज़िम के एक अधिकारी को लघु एवं मध्यम आकार उद्यमों को सहायता करने के लिए विशेष विपणन कौशल हासिल करने के लिए जिनेवा में आइ टी सी के मुख्यालय में ''एक्सपर्ट इन रेज़िडेन्स'' के रूप में तैनात किया गया है । ये दोनों पहलें आइ टी सी द्वारा किसी भी देश में पहली बार शुरू की गई हैं ।

मनोरंजन उद्योग के वित्तपोषण में अपने प्रवेश को और आगे बढ़ाते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान सात फिल्मों का वित्तपोषण किया है। फिल्म वित्तपोषण के प्रति बैंक का दृष्टिकोण विदेशी मुद्रा अर्जन परियोजनाओं पर और पिछले अच्छे रिकार्ड वाले चुनिंदा उधारकर्ताओं पर विशेष ध्यान देना है । वर्ष के दौरान वित्तपोषित अन्य सेवा क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, आतिथ्य और नौवहन शामिल हैं । कृषि निर्यात पर विशेष ज़ोर दिया गया है, जिसकी झलक वर्ष के दौरान कृषि व्यवसाय समूह द्वारा खाद्य प्रसंस्करण, पुष्पकृषि, फलों तथा सब्ज़ियों और संविदा कृषि क्षेत्रों के लिए सावधि वित्त सहित 5.8 बिलियन रुपये राशि की मंजूरियों में मिलती है । 'ताज़ा फल सब्जियाँ तथा डेरी उत्पाद : अन्य एशियाई देशों को निर्यात के लिए भारत की संभाव्यता' पर बैंक का प्रासंगिक आलेख इस क्षेत्र के आकार तथा विविधता पर विचार करते हुए उपयोग न की गई इसकी संभाव्यता को उजागर करता है ।

वर्ष के दौरान प्रकाशित शोध अध्ययनों में जैव प्रौद्योगिकी में भारत के लिए उभरते अवसरों, भारतीय बागवानी क्षेत्र की निर्यात संभाव्यता और एसियान देशों के साथ भारत की व्यापार तथा निवेश संभाव्यता पर फ़ोकस किया गया है । इसके अलावा निर्यातकों की रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों पर कार्यकारी आलेख प्रकाशित किये गये जिनमें बहु रेशा व्यवस्था पश्चात के परिदृश्य में भारत के वस्त्र निर्यात के लिए अवसर तथा चुनौतियाँ : भारतीय सिरामिक उद्योग की निर्यात संभाव्यता और मध्य एशियाई गणराज्यों अफ़गानिस्तान तथा पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (साकु) सदस्य देशों के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंध जैसे विषयों पर कार्यकारी पत्र शामिल हैं ।

अफ्रीकी क्षेत्र के साथ व्यापार तथा निवेश में रुचि रखने वाली कंपनियों की व्यावसायिक सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान 'इंडो अफ्रीकन बिज़नेस' शीर्षक से एक त्रैमासिक द्विभाषिक (अंग्रेजी, फ्रेंच) पत्रिका शुरू की है । डिवेलपमेंट बैंक ऑफ ज़ांबिया और वेस्ट अफ्रीकन डिवेलपमेंट बैंक (बी ओ ए डी) में ईक्विटी सहभागिता अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों को सुगम बनाने तथा बढ़ाने में बैंक के कार्यकलापों में सहायक होगी । इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रकाशित 'मार्केट मेकर : टेक्नोलोजी एडेड बिज़नेस सोल्यूशन्स' शीर्षक बैंक का प्रकाशन अफ्रीका तथा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल क्षेत्र में लघु आकार की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है । इसमें केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी एफ टी आर आइ) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में परियोजना प्रोफाइल निहित हैं ।

संस्था के संबंधों से प्राप्त तालमेल के माध्यम से एक समर्थकारी वातावरण के निर्माण करने की दिशा में बैंक के प्रयास को बोस्निया की निवेश गारंटी एजेंसी (आइ जी ए), बहरीन किंगडम के आर्थिक विकास बोर्ड, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ स्लोवाक रिपब्लिक (एक्ज़िमबैंका एस आर), तथा बी एन पी परीबास के साथ हस्ताक्षरित सहयोग-ज्ञापन से मज़बूती मिली है । बैंक ने अंकटाड के तत्वावधान में एक्ज़िम बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं के एक वैश्विक नेटवर्क के निर्माण के समर्थन में अफ्रीकन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एंडियन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन और एक्ज़िम बैंक ऑफ मलेशिया के

साथ एक सहमति-ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये हैं।

अंकटाड के पूर्व महासचिव श्री रूबिंस रिकोपेरो द्वारा दिया गया वर्ष 2005 के लिए बैंक का स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान वर्ष की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । इस व्याख्यान में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाहों की स्थिरता की आवश्यकता पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा बैंक को 'ट्रेड डिवेलपमेंट अवार्ड' 2005 से सम्मानित किया गया है । यह अवार्ड बैंक के निर्यात विपणन सेवा कार्यक्रम की स्वीकृति में है जो बैंक के गहन संस्थागत तथा व्यापार संबंधों तथा बैंक के समुद्रपारीय कार्यालयों की सेवाओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करते हुए चुनिंदा भारतीय कंपनियों के विपणन संस्था के रूप में कार्य करने की दिशा में इसकी पहुँच तथा विश्वसनीयता पर नये भौगोलिक क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय फर्मों के लिए सक्रिय रूप से एक समर्थकारी वातावरण सृजित करता है । बैंक को वर्ष 2002 तथा 2004 में भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था ।

बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली निर्यात संबद्ध सलाहकारी तथा संवर्धनात्मक सेवाओं को वर्ष के दौरान सुदृढ़ तथा मज़बूत बनाया गया । साथ ही वर्धित क्षेत्रीय व्यापार प्रवाहों को पोषित करने में लगी अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों के साथ संबंधों को भी मज़बूत बनाया गया। बैंक ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन सहित बहुपक्षीय एजेंसी के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखा है ।

कारोबार परिणाम

वर्ष के दौरान बैंक का कारोबार प्रदर्शन भारत के निर्यात में लगातार तेज़ी के अनुरूप रहा है। ऋण मंजूरियाँ कुल 158.5 बिलियन रुपये की थीं इनमें, गत वर्ष के मुकाबले 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । संवितरण 114.4 बिलियन रुपये के थे जो गत वर्ष के मुकाबले 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं । ऋण आस्तियाँ यथा 31मार्च 2005 को 24 प्रतिशत बढ़कर 134 .1 बिलियन रुपये हो गयीं ।

कर पश्चात लाभ गत वर्ष के 2.29 बिलियन रुपये की तुलना में 2.58 बिलियन रुपये रहा जिसमें 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। बैंक ने यूरोडॉलर बांड निर्गम के जरिये 250 मिलियन यू एस डॉलर तथा यूरोयेन फ्लोटिंग रेट नोट (एफ आर एन) निर्गम, जो किसी भारतीय निर्गमकर्ता द्वारा हाल के वर्ष में अपने किस्म का पहला निर्गम है, के जरिये 50 मिलियन यू एस डॉलर की समतुल्य राशि जुटायी है । बैंक को उसके समुद्रपारीय बांड निर्गम के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात मूडीज़ (बी ए ए 3), फिच (बी बी+) तथा एस एण्ड पी (बी बी+) एजेंसियों से सॉवरिन रेटिंग के समतुल्य रेटिंग प्राप्त है । बैंक ने निर्यात उन्मुख इकाइयों की पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदान-पश्चात ऋण आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए 200 मिलियन यू एस डॉलर राशि के अल्पावधि यू एस डॉलर संसाधन भी जुटाये हैं ।

संस्थागत संबद्धताएं

समर्थकारी वातावरण सृजित करने के बैंक के प्रयासों में व्यापार तथा निवेश के संवर्धन में लगी एजेंसियों तथा संस्थाओं के साथ विकसित संस्थागत संबंधों द्वारा औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूपों में सहायता मिली है । सी आइ आइ, फिक्की, एसोचेम, नैसकॉम, एफ आइ ई ओ, ई ई पी सी, पी ई पी सी, आइ सी सी, निर्यात संवर्धन परिषदें, भारत-यूरोपीय संघ वाणिज्य मंडल, अन्य वाणिज्य मंडल और विभिन्न केंद्रों में आर्थिक शोध संस्थाएं ज्ञान तथा बैंक के कार्य में सहायता का मूल्यवान स्रोत रही हैं । बैंक को निर्यात को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उसके प्रयासों में उद्योग, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि., भारत सरकार के मंत्रालयों

विशेषकर मूल वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ परस्पर संवाद से भी शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त हुआ है । बैंक ने निर्यात संवर्धन के अपने प्रयास में बहुपक्षीय एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समुदाय और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को मज़बूत किया है ।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन हुआ है । श्री एस.एन.मेनन, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री ए. के. झा, सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्रीमती सूर्यकांति त्रिपाठी, अपर सचिव (आर्थिक संबंध), भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्री अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग; श्री पी.के.दाश, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. और श्रीमती के.जे.उदेशी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, को मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री दीपक चटर्जी, सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री लक्ष्मी चंद, सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग; वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्री राजीव सिकरी, सचिव (पूर्व), भारत सरकार, विदेश मंत्रालय; श्री एम. दामोदरन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि.; श्री पी.एम.ए. हकीम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.; श्री आर. वी. शास्त्री, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, केनरा बैंक और श्री एस. सी. बसु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना कार्यकाल पूरा होने या कार्यालय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अपने-अपने निदेशक पद से त्याग पत्र दे दिये हैं । बैंक निदेशकों के रूप में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार मानता है ।

बैंक के स्टाफ़ ने उत्कृष्टता और कारोबार वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सतत समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है । बैंक के मिशन को आगे बढ़ाने और उसके द्वारा कॉर्पोरेट तथा व्यक्तिगत आत्मसम्मान को सुदृढ़ करने में उनका विशेष योगदान रहा है । बैंक की सहभागी तथा व्यावसायिक कार्य संस्कृति बैंक के लिए निरंतर शक्ति का एक स्रोत रही है ।

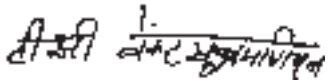

(टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन)

23 अप्रैल, 2005

आर्थिक परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों में वर्धित आर्थिक कार्यकलापों को प्रतिबिंबित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2004 के दौरान तीव्र सुधार आया है । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पत्रिका वर्ल्ड ईकोनोमिक आउटलुक अप्रैल 2005 के अनुसार वैश्विक उत्पादन 2003 में 4.0 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 5.1 प्रतिशत हो गया और 2005 में इस तीव्र वृद्धि के जारी रहने का अनुमान है । वैश्विक उत्पादन में वृद्धि, यू एस में लगातार वृद्धि, जापान तथा नई औद्योगिकीकृत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक कार्यकलाप तेज़ी द्वारा संचालित हैं और इसे एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ज़ोरदार निष्पादन से भी सहायता मिली है । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष के 2.0 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 3.4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि दर दर्ज की गई है । जबकि विकसित देशों तथा उभरते बाज़ारों ने गत वर्ष के दौरान 6.4 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 7.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है ।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2003 के 3.0 प्रतिशत की तुलना में 2004 में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 4.4 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है जो अन्य बातों के साथ-साथ वर्धित व्यवसाय निवेश तथा सुदृढ़ लाभप्रदता और वर्धित श्रम उत्पादकता दर्शाती है । हालांकि अमेरिका में तीव्र वृद्धि ने वैश्विक उत्पादन में सुधार को मज़बूती प्रदान की है, फिर भी अमेरिका का लगातार चालू खाता घाटा चिंता का विषय बना रहा । केनेडा में आर्थिक विस्तार को गति मिली और वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 2.0 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2004 में 2.8 प्रतिशत हो गयी । वर्धित रोज़गार तथा निजी खपत, उत्साहजनक व्यवसाय निवेश तथा शानदार लाभप्रदता और तीव्र निर्यात ने वर्ष 2004 के दौरान शानदार समग्र आर्थिक कार्यकलाप में योगदान दिया है ।

यूरो क्षेत्र में भी 2003 में 0.5 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 2.0 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि के साथ एक व्यापक सुधार देखा गया, यद्यपि यह सुधार विदेशी मांग पर अत्यधिक निर्भर रहा है । तथापि 2004 की दूसरी छमाही के दौरान देशी मांग में मंदी रही, जबकि यूरो की तेज़ी का निर्यात वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है । फ्रांस तथा स्पेन में घरेलू माल में तेज़ी रही है, यद्यपि इटली तथा जर्मनी में यह मांग कमज़ोर रही है । यूरो क्षेत्र में इस सुधार को बनाये रखना दस नई अनुवृद्धिशील अर्थव्यवस्थाओं के यूरोपीय संघ के साझा बाज़ार में एकीकरण की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षेत्र की क्षमता पर निर्भर करेगा । यूरो क्षेत्र से बाहर मज़दूरी में वृद्धि तथा जोरदार कॉर्पोरेट लाभ का प्रतिबिम्बित करते हुए युनाइटेड किंगडम में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 2.2 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 3.1 प्रतिशत थी ।

जापान में आइ टी उत्पादों की कमज़ोर वैश्विक मांग, जिसका निर्यात पर प्रभाव पड़ा और निजी क्षेत्र के निवेश में कम वृद्धि के कारण 2004 की अंतिम तीन तिमाहियों में वृद्धि की धीमी गति के बावजूद वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष के 1.4 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल के वर्षों में आर्थिक स्थितियों में सुधार हुआ है जो अन्य के साथ-साथ मज़बूत कॉर्पोरेट लाभप्रदता और बैंकिंग

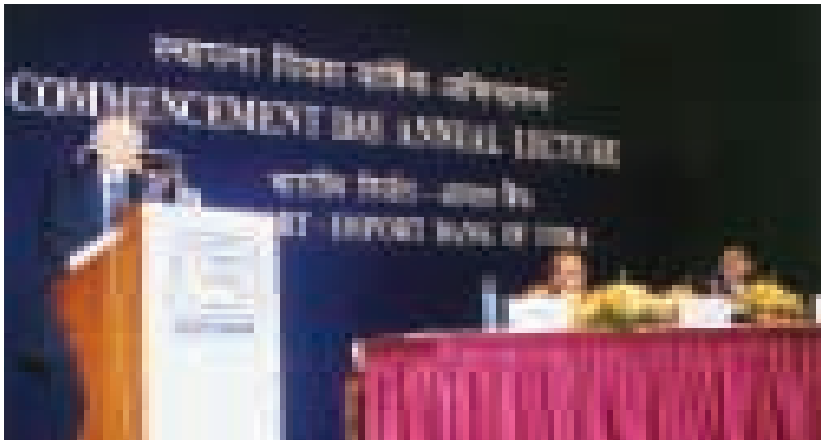

एक्ज़िम बैंक का 20 वां वार्षिक स्थापना दिवस व्याख्यान देते हुए श्री रूबिंस रिकोपेरो, अंकटाड के पूर्व महासचिव ने "व्यापार तथा विकास : विकासशील देशों के लिए चुनौतियाँ" विषय पर अपने विचार व्यक्त किए । श्री तरुण दास, मुख्य परामर्शदाता, भारतीय उद्योग परिसंघ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की ।

क्षेत्र की मज़बूत वित्तीय स्थिति में दिखाई देता है । मध्यावधियों में वृद्धि की संभावनायें कॉर्पोरेट तथा बैंकिंग क्षेत्रों में वित्तीय अतिसंवेदनशीलता को कम करने में सतत प्रगति द्वारा मज़बूती आई है ।

एशियाई क्षेत्र में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के दौरान 7.4 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 7.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही । इसे चीन, एसियान क्षेत्र तथा दक्षिण एशिया में ज़ोरदार आर्थिक कार्यकलापों से मज़बूती मिली है । दूसरी तिमाही में नियत निवेश में मंदी के बावज़ूद चीन में आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी रही है और वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 9.3 प्रतिशत की तुलना में

अर्ध जलमग्न फ्लोटिंग उत्पादन ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट का एक दृश्य जिसे वर्तमान में एबैन लायड चाइल्स ऑफशोर लि. (ऐलकोल) द्वारा वर्तमान में भारत के पूर्वी-समुद्री तट पर लगाया गया है । ऐलकोल जो अपतटीय खोज के लिए तेल क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करने और हाइड्रोकार्बन का उत्पादन करने के लिए भारत-अमेरिका संयुक्त उद्यम है, निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनी है । ऐलकोल को हाल ही में ईरान में एक परियोजना के लिए एक रिग के चार्टर किराये के लिए एक संविदा प्राप्त हुई है, जिसके लिए एक्ज़िम बैंक ने गारंटी और वित्त प्रदान किए हैं ।

2004 में 9.5 प्रतिशत रही है। चीन में लगातार तीव्र वृद्धि से पूर्व एशिया के शेष देशों में आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी आई है । यद्यपि सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दरें देशी मांग के आधार पर देशों में अलग-अलग हैं । एसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया, थाइलैंड, फिलिपीन्स तथा मलेशिया ने 2003 में 5.4 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 5.8 प्रतिशत की संयुक्त वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर्ज की है। नये औद्योगिकीकृत एशियाई देशों अर्थात कोरिया गणराज्य, हांगकांग, सिंगापोर तथा ताइवान में भी आर्थिक कार्यकलापों में सुधार दर्ज किया है और संयुक्त वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 3.1 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 5.5 प्रतिशत दर्ज की गई है । वैश्विक विस्तार तथा समर्थनकारी मौद्रिक स्थितियों की बदौलत भारत में तीव्र वृद्धि, पाकिस्तान में स्थूल आर्थिक निष्पादन में सुधार आया है जिससे बाह्य संवदेनशीलताओं में कमी आई है और बांग्लादेश में तीव्र वृद्धि से दक्षिण एशिया में आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी आई है ।

अफ्रीका में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2003 के 4.6 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 5.1 प्रतिशत रही है। इस वृद्धि में तेल तथा वस्तुओं की ऊँची कीमतों, उन्नत स्थूल आर्थिक नीतियों और संरचनागत सुधारों में प्रगति सहित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की मज़बूती से सहायता मिली है । इसके अतिरिक्त विशिष्ट देशों के घटनाक्रमों से भी तेल उत्पादन में भारी वृद्धि (अंगोला, चाड तथा एक्वाटोरियल गीनिया), कृषि उत्पादन में सुधार (इथियोपिया तथा

भारत के पण्य व्यापार की प्रवृत्तियां

(बिलियन रुपये)

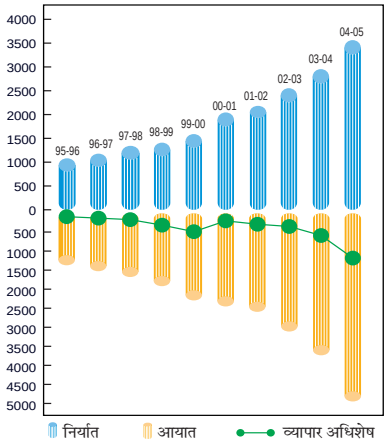

भारत के सेवा व्यापार की प्रवृत्तियां

(बिलियन रुपये)

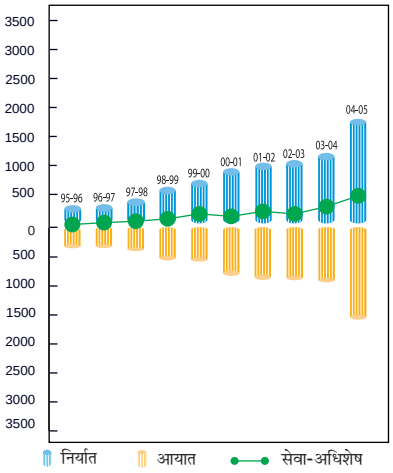

रवांडा) सहित समग्र वृद्धि में तेज़ी आई है । मुद्रास्फीति के मोर्चे पर, उन्नत स्थूल आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दरें अपेक्षाकृत सामान्य रही हैं, सिवाय ज़िम्बाब्वे के, जहाँ मुद्रास्फीति की दरें चिंता का विषय बनी हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में गत वर्ष की 2.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2004 में 3.7 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर दर्ज की गई जिसका

प्रमुख कारण देशीय मांग में भारी वृद्धि तथा राजकोषीय नीति का विस्तारीकरण रहा है ।

मध्य पूर्व में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर पिछले वर्ष की 5.8 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 5.5 प्रतिशत रही जो निर्यात आय में वृद्धि दर्शाता है और जिसमें स्वस्थ वित्तीय नीतियों और संरचनात्मक सुधारों में प्रगति से सहायता मिली है । इसे प्रतिबिंबित करते हुए क्षेत्र ने भारी चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। क्षेत्र में गैर-तेल उत्पादक देशों में वृद्धि दर तेज़ रही जिस पर देशी सुधारों के सकारात्मक प्रभाव और तेल उत्पादक देशों में तीव्र वृद्धि का प्रभाव पड़ा है । सउदी अरब में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2004 में 5.3 प्रतिशत रही जबकि कुवैत में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 रही। ईरान में उच्च तेल कीमतों, सुधारों, जिन्होंने गैर तेल क्षेत्र में भारी वृद्धि की थी और मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों को बढ़ाया था, के समर्थन से वर्ष 2004 में 6.6 प्रतिशत की वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर दर्ज की है । मिस्र में ज़ोरदार निर्यात निष्पादन और देशी खपत में पुनरुत्थान को प्रतिबिंबित करते हुए वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि दर गत वर्ष के 3.1 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 4.1 प्रतिशत रही । इज़राइल का वास्तविक सकल देशी उत्पाद गत वर्ष के 1.3 प्रतिशत की वृद्धि से बहुत तेज़ी से बढ़कर 2004 में 4.3 प्रतिशत हो गया जिसमें अनुकूल वैश्विक वातावरण और सुरक्षा स्थितियों में सुधार का योगदान रहा है ।

लैटिन अमेरिका में वर्ष 2004 में स्थूल आर्थिक नीतियों और संरचनागत सुधार, अनुकूल विदेशी वातावरण, बढ़ी हुई देशी मांग और निजी खपत में वृद्धि तथा कारोबार निवेश में वृद्धि के समर्थन से आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी आई है । इन्हें प्रतिबिंबित करते हुए क्षेत्र के वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 2.2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2004 में 5.7 प्रतिशत रही । मर्कोसुर क्षेत्र में अर्जेंटीना ने वास्तविक देशी उत्पाद में गत वर्ष के 8.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2004 में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है । जबकि ब्राज़ील ने गत वर्ष के 0.5 प्रतिशत की तुलना में वास्तविक सकल देशी उत्पाद में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है । एंडियन क्षेत्र में आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी आई है और समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2003 के 1.4 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 7.3 प्रतिशत रही है । एंडियन क्षेत्र में आर्थिक कार्यकलापों में उछाल को वेनेज़्युएला में तीव्र सुधारों से मज़बूती मिली है जिसने गत वर्ष में 7.7 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में 2004 में 17.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है । मेक्सिको में आर्थिक कार्यकलापों में 2004 में तेज़ी आई और वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर 2003 के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2004 में 4.4 प्रतिशत हो गयी, जिसमें समर्थनकारी मौद्रिक दशाओं और संयुक्त राज्य से मांग में तेज़ी का योगदान रहा है ।

स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल देशों में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष 7.9 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 8.2 प्रतिशत के प्रभावशाली स्तर पर बनी रही । विश्व भर में तेल की ऊँची कीमतें और अपरिष्कृत तेल तथा धातुओं की मांग ने क्षेत्र में मज़बूत वृद्धि गति में योगदान दिया है । उत्साही निर्यात वृद्धि को विनिर्माण तथा निर्माण क्षेत्रों में बढ़े हुए कार्यकलापों के साथ भारी देशी मांग से सहायता मिली है । रूस में आर्थिक कार्यकलापों में तेज़ी रही और बढ़ते हुए निर्यात से देश की बाह्य स्थिति को मज़बूती मिली है और वास्तविक सकल

मॉरीशस सरकार को 10 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की गई । श्री ए. आर. गुप्तार, वित्त सचिव, वित्त एवं आर्थिक विकास मंत्रालय, मॉरीशस सरकार ने भारत के माननीय प्रधान मंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और मॉरीशस के प्रधान मंत्री माननीय श्री पॉल बिरेंजर की उपस्थिति में पोर्ट लुइस में एक्ज़िम बैंक के साथ करार का आदान-प्रदान किया ।

देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 7.3 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 7.1 प्रतिशत रही । उक्रेन में, वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर गत वर्ष के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 12.1 प्रतिशत रही जो मुख्यत: धातु की कीमतों में वृद्धि और निर्यात में तेज़ी सहित अनुकूल बाह्य कारकों को प्रतिबिंबित करती है । मज़बूत क्षेत्रीय वृद्धि गति ने अन्य स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल देशों में वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर बढ़ाने में योगदान दिया है ।

विश्व व्यापार

वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों में तीव्र सुधार दर्शाते हुए और पण्य मूल्यों में तेज़ी के कारण वर्ष 2004 में वैश्विक निर्यात 8902 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के थे, इनमें 21.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है । तेल तथा गैर-ईंधन प्राथमिक वस्तुओं के विश्व मूल्यों में वर्ष 2004 में भी लगातार तेज़ी बनी रही है। जबकि विनिर्मित वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई है। तेल के मामले में विश्व कीमतों में गत वर्ष के 15.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2004 में 30.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई, जबकि गैर-ईंधन प्राथमिक वस्तुओं के मूल्यों में भी 2003 के 7.1 प्रतिशत की तुलना में 2004 में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । विनिर्मित वस्तुओं के मामले में विश्व मूल्यों में गत वर्ष के दौरान 13.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की तुलना में 2004 में 8.8 प्रतिशत की कमतर वृद्धि दर्ज की गई ।

मात्रा की दृष्टि से विश्व व्यापार में गत वर्ष के दौरान 5.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2004 में 10.7 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई । उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरते बाज़ारों दोनों ने व्यापार की मात्रा में वृद्धि दर्ज की है । निर्यात के मामले में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने 2003 में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2004 में निर्यात की मात्रा में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है । जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरते बाज़ारों ने गत वर्ष के दौरान 10.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2004 में निर्यात की मात्रा में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है । 2005 के दौरान विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि 7.9 प्रतिशत के स्तर पर बने रहने का अनुमान है।

जहाँ तक आयात की मात्रा का संबंध है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने निर्यात मात्रा में 2003 में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2004 में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है जबकि विकासशील देशों और उभरते बाज़ारों ने निर्यात की मात्रा में गत वर्ष के दौरान 10.3 प्रतिशत की तुलना में 2004 के दौरान आयातों की मात्रा में 16.9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की है ।

भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा एक्ज़िम बैंक के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित 'भारत अफ्रीका सम्मेलन' में माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ई.वी.के.एस. एलांगोवैन और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के वाइस प्रेसिडेंट महामहिम श्री जीन पियरी बेम्बा के साथ माननीय विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह । भारत-अफ्रीकी व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक्ज़िम बैंक के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित इस उच्चस्तरीय सम्मेलन में चाड के उप प्रधान मंत्री सहित 24 अफ्रीकी राष्ट्रों से 230 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

निजी पूँजी प्रवाह, चालू खाता शेष एवं विदेशी ऋण

उभरते बाज़ारों का निवल निजी पूँजी प्रवाह 2003 के 207.6 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2004 में 303.4 बिलियन यू एस डॉलर हो जाने का अनुमान है । 2005 के दौरान उभरते बाज़ारों को निवल निजी पूँजी प्रवाह और बढ़कर 310.7 बिलियन यू एस डॉलर हो जाने की आशा है ।
निवल प्रवाह की वृद्धि में प्रत्यक्ष ईक्विटी निवेश और वाणिज्यिक बैंक उधार में तीव्र वृद्धि का सर्वाधिक हिस्सा है ।

एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में उभरते बाज़ारों में निजी पूँजी प्रवाह 2003 के

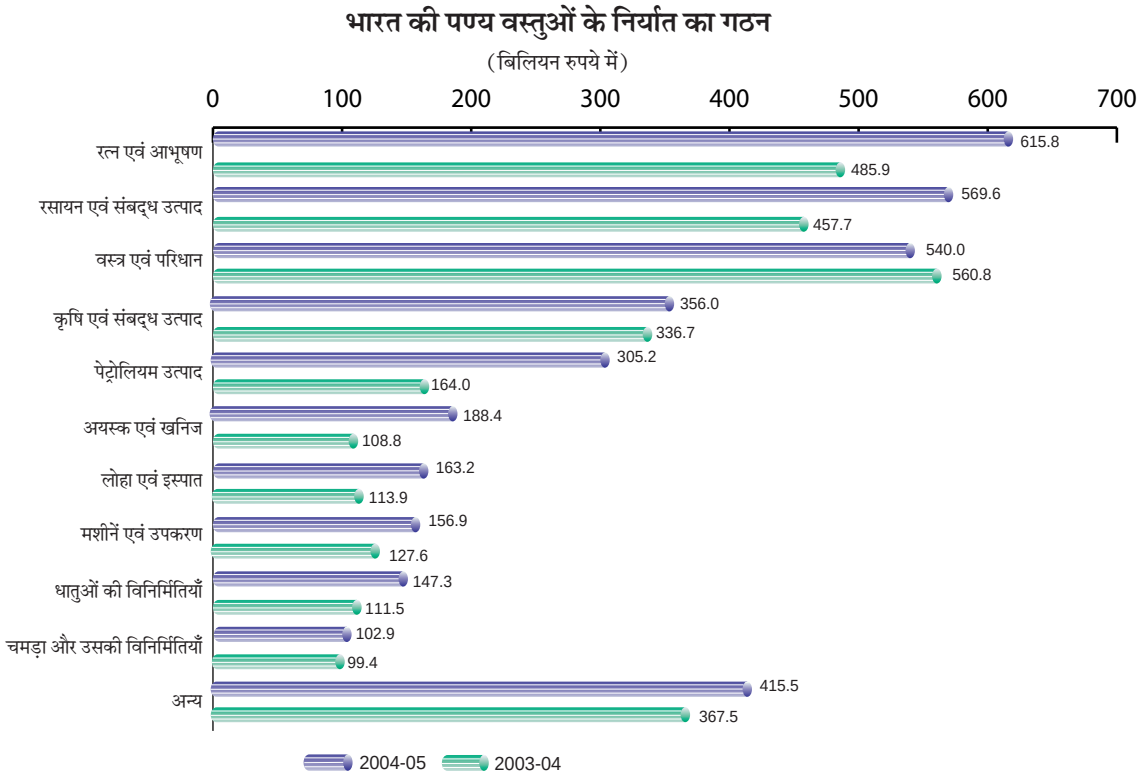

116.8 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2004 में 156.0 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । जबकि यूरोप में उभरते बाज़ारों में निजी पूँजी प्रवाह भी इसी अवधि के दौरान 62.5 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 107.3 बिलियन यू एस डॉलर हो गया। लैटिन अमेरिका के उभरते बाज़ारों के मामले में निजी पूँजी प्रवाह 2003 के 23.9 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2004 में 29.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया जबकि इस अवधि में अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के उभरते बाज़ारों का निजी पूँजी प्रवाह भी 4.4 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 10.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गया ।

वर्ष 2004 के दौरान उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं का संयुक्त चालू खाता अधिशेष गत वर्ष के 119.6 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 169.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । इसका श्रेय एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों में चालू खाता अधिशेष में तीव्र वृद्धि को जाता है जो 2003 के 100.3 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2004 में 130.4 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के देशों के मामले में चालू खाता अधिशेष 2003 के 10.5 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2004 में 23.9 बिलियन यू एस डॉलर हो गया, जबकि अफ्रीका तथा मध्य पूर्व के देशों के लिए भी चालू खाता अधिशेष इसी अवधि के दौरान 10.2 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 10.3 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । यूरोप के देशों के मामले में चालू खाते में गत वर्ष के दौरान 1.4 बिलियन यू एस डॉलर के घाटे के विपरीत 2004 में 5.3 बिलियन यू एस डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया है ।

विकासशील देशों तथा उभरते बाज़ारों के लिए माल एवं सेवाओं के निर्यात के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण 2003 के 112.6 प्रतिशत से घटकर 2004 में 92.7 प्रतिशत हो गया । लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के विकासशील देशों तथा उभरते बाज़ारों के लिए माल एवं सेवाओं के निर्यात के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण 2004 में 166.9 प्रतिशत के स्तर पर सर्वाधिक था, उसके बाद अफ्रीका (116.2 प्रतिशत), मध्य तथा पूर्वी यूरोप (106.0 प्रतिशत), स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल (81.0 प्रतिशत), मध्य पूर्व (75.3 प्रतिशत) तथा एशिया (63.3 प्रतिशत) का स्थान था । विकासशील देशों तथा उभरते बाज़ारों के लिए ऋण शोधन भुगतान 2003 के 17.9 प्रतिशत से घटकर 2004 में 14.0 प्रतिशत रह गया ।

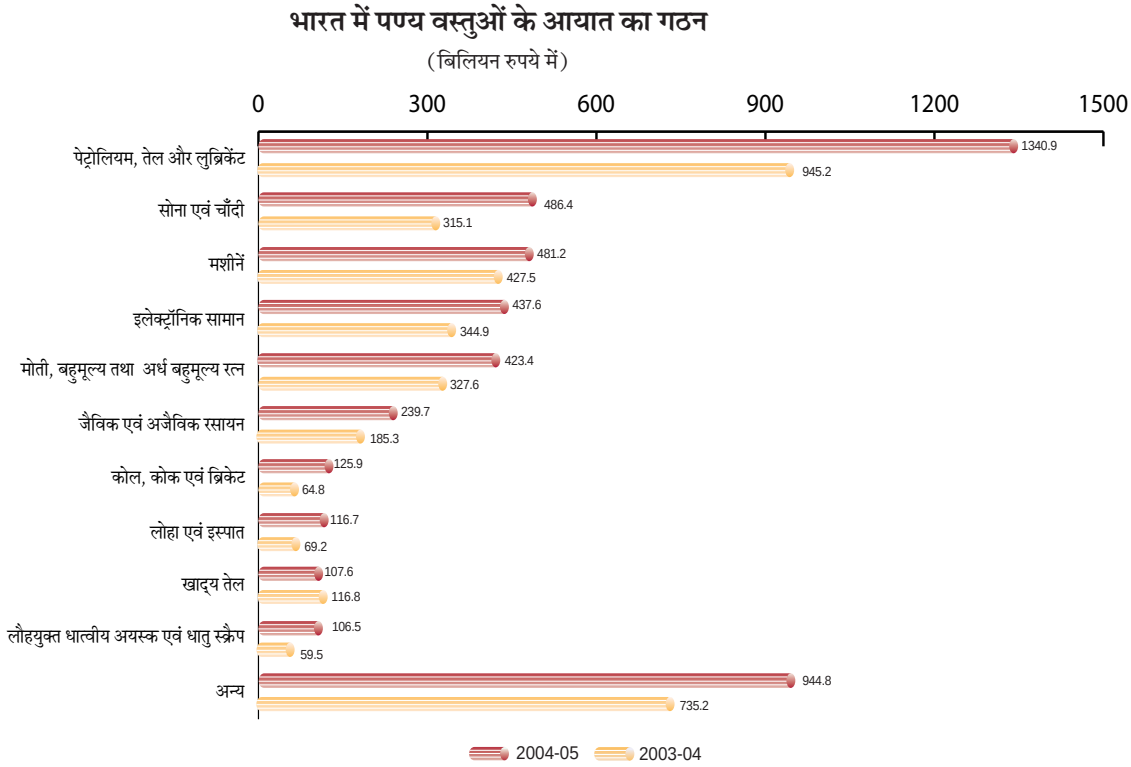

भारत में पण्य वस्तुओं के आयात का गठन

(बिलियन रुपये में)

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2004-05* के दौरान, आर्थिक कार्यकलापों में सतत वृद्धि की गति दर्शाते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था में गत वर्ष के दौरान दर्ज़ की गई 8.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.9 प्रतिशत वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है । विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में ज़ोरदार कार्यकलापों से वर्ष 2004-05 के दौरान समग्र वृद्धि में तेज़ी आई है ।

कृषि

वर्ष 2003-04 के दौरान 9.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज करने के बाद कृषि क्षेत्र में 2004-05 के दौरान 1.1 प्रतिशत की मंद वृद्धि दर्ज की गई । इसका मुख्य कारण दक्षिण-पश्चिम मानसून में कमी और परिणामस्वरूप समग्र खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट था । तथापि गैर-खाद्यान्न क्षेत्र ने वर्ष के दौरान प्रभावशाली निष्पादन दर्ज किया है । खाद्यान्न का उत्पादन गत वर्ष के दौरान 212.4 मिलियन टन की तुलना में 2004-05 के दौरान घटकर 206.4 मिलियन टन होने का अनुमान है ।

उद्योग

औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 2004-05 के दौरान 8.0 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। इसी अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान 7.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 8.8 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि से औद्योगिक क्षेत्र में शानदार निष्पादन में सहायता मिली है । बिजली क्षेत्र में भी वर्ष 2004-05 के दौरान 5.2 प्रतिशत की उच्चतर वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान यह वृद्धि 5.1 प्रतिशत थी । तथापि खनन क्षेत्र में गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 4.3 प्रतिशत की थोड़ी कम वृद्धि दर्ज की गई ।

उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार पूँजीगत माल क्षेत्र ने वर्ष 2004-05 के दौरान 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ तेज़ी प्रदर्शित की है, जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान यह वृद्धि 13.6 प्रतिशत थी । टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र ने भी वर्ष 2004-05 के दौरान 14.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की है, इसके बाद गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु

* इस खंड में दिये गये आंकड़े भारतीय राजकोषीय वर्ष के अनुरूप हैं जो अप्रैल से अगले वर्ष के मार्च तक होता है।

क्षेत्र (10.4 प्रतिशत), मध्यवर्ती माल क्षेत्र (5.8 प्रतिशत) और मूल वस्तु क्षेत्र (5.5 प्रतिशत) का स्थान रहा है।

विनिर्माण क्षेत्र के 17 उप क्षेत्रों में से पाँच क्षेत्रों में 2004-05 के दौरान 10 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इन क्षेत्रों में पेय पदार्थ तथा तंबाकू, वस्त्र उत्पाद, मूल रसायन तथा रासायनिक उत्पाद, मशीनें और परिवहन उपकरण से भिन्न उपकरण तथा अन्य विनिर्माण उद्योग शामिल हैं । दो क्षेत्रों अर्थात खाद्य उत्पाद और लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद में वर्ष के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई ।

बुनियादी क्षेत्र

छह प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण उद्योगों अर्थात सीमेंट, बिजली, पेट्रोलियम शोधन उत्पाद, कोयला, तैयार इस्पात और अपरिष्कृत पेट्रोलियम, ने 2004-05 में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि गत वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान यह वृद्धि 6.2 प्रतिशत थी । 2004-05 के दौरान सीमेंट, बिजली, पेट्रोलियम शोधन उत्पाद, कोयला, तैयार इस्पात और अपरिष्कृत पेट्रोलियम ने गत वर्ष की तुलना में क्रमश: 6.6 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत, 3.9 प्रतिशत, 3.7 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है ।

पूँजी बाज़ार

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवल निवेश 2003-04 के दौरान 9.95 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2004-05 के दौरान 10.17 बिलियन यू एस डॉलर रहा । प्राथमिक बाज़ार से जुटायी गई पूँजी 2003-04 में 57 निर्गमों से 232.72 बिलियन रुपये की तुलना में 2004-05 के दौरान 60 निर्गमों से 282.56 बिलियन रुपये थी ।

मुद्रास्फीति

थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित बिंदु-दर-बिंदु आधार पर मुद्रास्फीति की दर मार्च 2004 के अंत में 4.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2005 के अंत में 5.0 प्रतिशत थी । मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में वृद्धि दर 2003-04 के दौरान 16.9 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 के दौरान 12.8 प्रतिशत थी ।

माननीय वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम एक्ज़िम बैंक के प्रधान कार्यालय में पधारे । श्री चिदंबरम ने बैंक के एक्ज़िमिअस प्रदर्शनी केंद्र का अवलोकन किया जिसमें एक्ज़िम बैंक की सहायता से भारतीय कंपनियों द्वारा विनिर्मित तथा निर्यात किये जानेवाले उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई है।

विदेश व्यापार तथा भुगतान संतुलन

वर्ष 2004-05 के दौरान पण्य निर्यात में यू एस डॉलर की मूल्य की दृष्टि से 24.1 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है । मूल्य की दृष्टि से पण्य निर्यात 2004-05 के दौरान 79.2 बिलियन यू एस डॉलर रहा जो वर्ष 2003-04 के दौरान 63.8 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर से अधिक था । इसमें सॉफ्टवेयर निर्यात शामिल नहीं है जो 2003-04 के 12.8 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर 2004-05 के दौरान 17.2 बिलियन यू एस डॉलर हो गया । यह 34.4 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। निर्यातों में इस तेज़ी का श्रेय वैश्विक आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि और भारतीय निर्यात की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को जाता है । निर्यात मदें जिनमें 2004-05 के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज की गई है उसमें लौह अयस्क, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबंद्ध उत्पाद, परिवहन उपकरण, लौह एवं इस्पात, धातु निर्मित वस्तुएं तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं ।

वर्ष 2004-05 के दौरान आयातों में 37.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई और ये गत वर्ष के 78.1 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में बढ़कर 107.1 बिलियन यू एस डॉलर हो गये। तेल तथा गैर तेल आयातों दोनों में तीव्र वृद्धि के कारण समग्र आयात में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004-05 के दौरान तेल आयात 29.8 बिलियन यू एस डॉलर रहा जिसमें गत वर्ष के

16.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 45.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । देशी विनिर्माण कार्यकलापों में तेज़ी को दर्शाते हुए गैर तेल आयातों में 2004-05 के दौरान 34.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और ये बढ़कर 77.2 बिलियन यू एस डॉलर मूल्य के हो गये हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान उच्च वृद्धि दर्ज करने वाली आयात मदों में धात्विक अयस्क तथा धातु स्क्रैप, उर्वरक, इलेक्ट्रिकल तथा गैर-इलेक्ट्रिकल मशीनें, कोयला, कोक एवं ब्रिकेट कार्बनिक एवं अकार्बनिक रसायन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, सोना और चांदी शामिल हैं । व्यापार घाटा गत वर्ष के 14.3 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 2004-05 के दौरान 27.8 बिलियन यू एस डॉलर के उच्च स्तर पर था ।

भारत में पण्य वस्तुओं के व्यापार की दिशा

(बिलियन रुपये में)

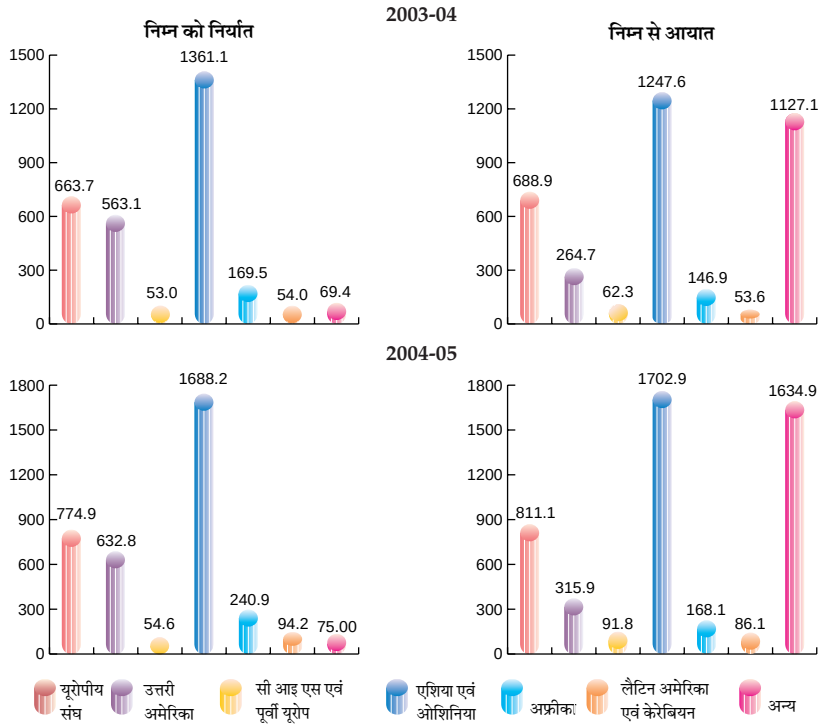

वर्ष 2004-05 (अप्रैल-दिसंबर) में अदृश्य मदों का निवल प्रवाह वर्ष 2003-04 के 26.0 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 21.0 बिलियन यू एस डॉलर था। चालू खाता शेष, जिसमें वर्ष 2003-04 के 10.6 बिलियन यू एस डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया था, वर्ष 2004-05 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 7.4 बिलियन यू एस डॉलर का घाटा दर्शाता है ।

माननीया सुश्री मर्षा थॉमसन, आइ सी टी मंत्री, विक्टोरिया राज्य, ऑस्ट्रेलिया ने क्षेत्र में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए आइ सी टी कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया । एक्जिम बैंक विदेशों में भारतीय निवेश में सहायता देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाता है और विश्व भर में कई निवेश संवर्धन एजेंसियों के साथ कार्य करता है । बैंक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है ।

वर्ष 2004-05 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर्वाह गत वर्ष के 4.7 बिलियन यू एस डॉलर की तुलना में 4.5 बिलियन यू एस डॉलर था । मार्च 2005 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार 140.9 बिलियन यू एस डॉलर था जो लगभग 16 महीने के आयात के लिए कवर का प्रतिनिधित्व करता है ।

भारत का कुल विदेशी ऋण यथा मार्च 2003 के अंत में 104.9 बिलियन यू एस डॉलर से बढ़कर यथा मार्च 2004 के अंत में 111.7 बिलियन यू एस डॉलर और आगे दिसंबर 2004 के अंत में 120.9 बिलियन यू एस डॉलर का हो गया । कुल विदेशी ऋण के अनुपात में अल्पावधि का

ऋण अनुपात यथा मार्च 2003 के अंत में 4.4 प्रतिशत से यथा दिसंबर 2004 के अंत में बढ़कर 5.7 प्रतिशत होने से पूर्व मार्च 2004 के अंत में 4.0 प्रतिशत हो गया था ।

चुनिंदा क्षेत्रों के लिए भावी संभावनाएं

वस्त्र एवं परिधान

वस्त्र एवं परिधान उद्योग उत्पादन, विदेशी मुद्रा आय और रोज़गार निर्माण की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है । कोटा प्रतिबंधों के समाप्त हो जाने से भारतीय वस्त्र एवं परिधान उद्योग को भारी लाभ होने की संभावना है ।

एक्ज़िम बैंक के शोध आलेख ने अनुमान लगाया है कि वस्त्र एवं परिधान का विश्व निर्यात 2014 तक 800 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर को पार कर जायेगा और भारत को 3 प्रतिशत (12.5 बिलियन यू एस डॉलर) के वर्तमान स्तर से लगभग 9 प्रतिशत (70 बिलियन यू एस डॉलर) का बाज़ार हिस्सा प्राप्त होने की आशा है । हालांकि चीन को कोटा पश्चात व्यवस्था में प्रमुख लाभार्थी माना जा रहा है, डिज़ाइन तथा फैशन कौशल की दृष्टि से भारतीय क्षमता इस क्षेत्र को उच्च मूल्य के सूती वस्त्र खंड में सुखद स्थिति में रखेगी ।

औषध एवं औषधियाँ

भारत विश्व में बल्क ड्रग्स का शीर्ष विनिर्माता और शीर्ष 20 औषधि निर्यातकों में से एक है । यह उद्योग उपचारात्मक उत्पादों की लगभग पूरी शृंखला का विनिर्माण करता है और मूलभूत चरण से बल्क ड्रग्स की एक व्यापक शृंखला विनिर्मित करने के लिए कच्चा माल तैयार करने की स्थिति में है । यह उद्योग अपनी अंतर्निहित शक्तियों जैसे लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, अनुसंधान एवं विकास लागत, मज़बूत विनिर्माण आधार, आर एंड डी सुविधाओं से युक्त प्रयोगशालाओं के सुस्थापित नेटवर्क, मज़बूत विपणन तथा वितरण नेटवर्क और रसायन तथा प्रक्रिया विकास में क्षमता पर विकास कर रहा है ।

नई पेटेंट व्यवस्था लागू हो जाने से भारतीय औषधि कंपनियाँ प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अंतरराष्ट्रीय विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के अतिरिक्त अपनी विनिर्माण सुविधाओं को उन्नत करने की प्रक्रिया में हैं ।

वर्ष 2004 में औषधियों की वैश्विक बिक्री 550 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है । यह भी अनुमान है कि जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का सक्रिय अनुसंधान तथा विकास प्रक्रिया में 27 प्रतिशत हिस्सा रहा और 2004 में वैश्विक बिक्री में 10 प्रतिशत हिस्सा रहा । जैव प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषण से नए अवसर उभरेंगे । अपने बढ़ते जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ भारत के पास निकट भविष्य में बायो फार्मास्यूटिकल की लहर में आगे बढ़ने की संभाव्यता है ।

ऑटो-पुर्जे

भारतीय ऑटो-पुर्जा क्षेत्र एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में विकसित हुआ है । उदारीकरण के बाद भारत में बहुराष्ट्रीय ऑटो कंपनियों के प्रवेश ने उद्योग को अत्यधिक कौशल गहन और गुणवत्ता

कोपेनहैगेन में मार्सिंग एंड कंपनी ए/एस, डेनमार्क (मार्सिंग), फार्मास्युटिकल उत्पादों की एक व्यापारिक और विनिर्माणकर्ता कंपनी का कार्यालय भवन । मुंबई आधारित रसायन तथा फार्मा कंपनी हीकेल लि. ने एक्जिम बैंक की वित्तीय सहायता से हीकल इंटरनैशनल बी वी नीदरलैंड की अपनी पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के जरिए मार्सिंग में 50.1% की हिस्सेदारी अर्जित की है ।

सचेत बना दिया है । भारत को अब ऑटो-पुर्जा डिज़ाइनिंग, विनिर्माण तथा आउटसोर्सिंग के लिए एक केंद्र के रूप में स्वीकार किया जा रहा है ।

यह उद्योग लागत तथा गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से तेज़ी से वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त कर रहा है । ऐसा अनुमान है कि भारत में ऑटो डिज़ाइन की लागत यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में उसकी लागत के 1/12 से भी कम होगी । इसी प्रकार विनिर्माण की लागत भी यू एस ए में उसकी लागत के 1/10 से कम होने की आशा है ।

ऐसा अनुमान है कि विश्व ऑटो पुर्जा उद्योग 2015 तक 1.9 ट्रिलियन यू एस डॉलर के स्तर तक पहुँच जायेगा जिसमें से लगभग 40 प्रतिशत (700 बिलियन यू एस डॉलर) भारत जैसे विकासशील देशों से आउटसोर्स किए जाने की संभावना है। एक अध्ययन के अनुसार भारतीय ऑटो पुर्जा उद्योग में उच्च वृद्धि दर दर्ज होने की संभावना है और यह लगभग 7 बिलियन यू एस डॉलर के वर्तमान स्तर से बढ़कर 2015 तक 40 बिलियन यू एस डॉलर के स्तर पर पहुँच जायेगा । एक अन्य अध्ययन ने इस क्षेत्र का मूल्यांकन किया है और भारत की गुणवत्ता उत्पादों की दृष्टि से एक प्रमुख स्थान के रूप में पहचान की है ।

पारंपरिक औषधियाँ तथा औषधीय पौधे

वैश्विक हर्बल बाज़ार 80 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक होने का अनुमान है और यह प्रतिवर्ष लगभग 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है । विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वैश्विक हर्बल बाज़ार 2050 तक 5 ट्रिलियन यू एस डॉलर के स्तर तक पहुँच जायेगा । विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह भी अनुमान है कि एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के लिए पारंपरिक औषधियों का इस्तेमाल करती है । अधिकांश विकसित देशों में भी पूरक या वैकल्पिक औषधियों का प्रयोग बढ़ रहा है ।

भारत इस क्षेत्र में बढ़ते अवसर को प्राप्त करने के लिए लाभकर स्थिति में है । इसका पहला कारण, गहन जैव विविधता के साथ भारत के पास पौधों की लगभग 8000 प्रजातियाँ है जिनका स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं में उपयोग होता है । औषधीय पौधों के निर्यात की दृष्टि से भारत वैश्विक मानचित्र में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है । दूसरा, भारत 5000 वर्षों से अधिक समय से स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र में अपनी प्रचुर जैव विविधता का प्रयोग कर रहा है और भारतीय औषधीय प्रणाली समय की कसौटी पर खरी उतरी है । तीसरा कारण, चीन की तरह भारत ने भी औषध की पारंपरिक प्रणालियों को दस्तावेज़ीकृत किया है और इसके पास मूल्य योजित उत्पादों के विनिर्माण के लिए वनस्पतियों की प्रचुर देशी आपूर्ति है । ये सभी कारक भारत को इस क्षेत्र में उपलब्ध वैश्विक अवसर प्राप्त करने में तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति में रखते हैं ।

कागज़ उत्पादों के विनिर्माण में लगी महिला शिल्पकार । हैंडमेड पेपर एंड बोर्ड इंडस्ट्रीज, जयपुर एक 100% निर्यात उन्मुख इकाई है जो नितांत रूप से हस्त निर्मित कागज़ उत्पादों का विनिर्माण करती है । एक्ज़िम बैंक ने फर्म के समुद्रपारीय परिचालनों को सहायता देने के लिए निर्यात वित्त प्रदान किया है ।

नीतिगत परिवेश

सरकार द्वारा अगस्त 2004 में घोषित की गई वर्ष 2004-2009 की अवधि के लिए नई विदेश व्यापार नीति (विदेश व्यापार नीति 2004-2009), भारत के विदेशी

व्यापार के समग्र विकास का एक एकीकृत दृष्टिकोण लेती है और क्षेत्र के विकास के लिए रूप रेखा प्रस्तुत करती है । विदेश व्यापार नीति 2004-2009 दो प्रमुख उद्देश्यों पर बनी हुई है: अगले पाँच वर्षों के भीतर वैश्विक पण्य व्यापार में भारत के प्रतिशत हिस्से को दुगुना करना और रोज़गार निर्माण पर ज़ोर देते हुए आर्थिक विकास के एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करना ।

विदेश व्यापार नीति 2004-2009 द्वारा अभिकल्पित मुख्य रणनीतियों में शामिल हैं : विश्वास तथा पारदर्शिता का एक वातावरण सृजित करना; प्रक्रियाओं को सरल बनाना और लेन-देन लागत को कम करना ; विनिर्माण, व्यापार तथा सेवाओं के लिए एक वैश्विक केन्द्र के रूप में भारत के विकास को सुगम बनाना; रोज़गार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए विशेष संकेन्द्रण केन्द्रों की पहचान करना और उन्हें संपोषित करना; मूल्य योजन तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का प्रौद्योगिकीय संरचनागत उन्नयन सुगम बनाना; संपूर्ण विदेश व्यापार शृंखला से संबद्ध संरचनागत नेटवर्क का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन करना । अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति के अनुरूप, अप्रैल 2005 में घोषित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के वार्षिक पूरक में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने तथा उसे बढ़ाने के उद्देश्य से अतिरिक्त नीति पहलें तथा प्रक्रियात्मक सरलीकरण शामिल हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए कई उपाय लागू किये गये जिनमें शामिल हैं: ''हवाई परिवहन सेवा (देशी एयरलाइन्स)'' में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा में स्वत: अनुमोदित मार्ग के माध्यम से 49 प्रतिशत तक और स्वत: अनुमोदित मार्ग के माध्यम से अनिवासी भारतीयों द्वारा 100 प्रतिशत तक वृद्धि; कुछ सेवाओं (जैसे बेसिक, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेस, ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन सर्विसेज़ तथा अन्य मूल्य योजित सेवाएं) में दूर संचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत की वृद्धि । टाउनशिप, गृह निर्माण निर्मित बुनियादी क्षेत्र तथा निर्माण विकास परियोजनाओं में कुछ शर्तों के अधीन स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है ।

इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेश / तकनीकी सहयोग के लिए ऐसे नये प्रस्तावों पर, जहाँ विदेशी निवेशक कोई पूर्व संयुक्त उद्यम रखता था अथवा रखता है अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण/ट्रेड मार्क करार, के मामलों में कतिपय क्षेत्रगत शर्तों के अधीन स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी ।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश सहित स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74 प्रतिशत तक बढ़ाकर बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को और उदार बनाया गया है । सभी स्रोतों से किसी एक निजी बैंक के कुल विदेशी निवेश बैंक की कुल चुकता पूँजी का अधिकतम 74 प्रतिशत होगा और हमेशा कम से कम 26 प्रतिशत चुकता पूँजी निवासियों द्वारा धारित की जाएगी, सिवाय इसके कि निजी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था के संबंध

डॉ. किरीट पारिख, सदस्य-योजना आयोग, भारत सरकार, एक्ज़िम बैंक के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार 2003 को प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में अध्यक्षीय भाषण देते हुए । 1989 में संस्थापित यह वार्षिक पुरस्कार भारतीय / विदेशों के विश्व विद्यालयों में किसी भारतीय विद्यार्थी द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार एवं विकास और संबद्ध वित्तपोषण विषय पर उत्कृष्ट डॉक्टरीय शोध प्रबंध पर प्रदान किया जाता है ।

में । इसके अलावा विदेशी बैंकों को या तो शाखाएं खोलने या सहायक संस्थायें खोलने की अनुमति दी गई है । गृह देश में बैंकिंग प्राधिकार द्वारा विनियमित और रिज़र्व बैंक के लाइसेंस मानदंड को पूरा करने वाले विदेशी बैंकों को 100 प्रतिशत चुकता पूँजी धारित करने की अनुमति दी जायेगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना कर सके ।

इसके अलावा, भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए एक रोडमैप भी जारी किया गया है जिसे दो चरणों में बाँटा गया है - चरण एक, मार्च 2005 तथा मार्च 2009 के बीच जिसके दौरान विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं की स्थापना कर या मौज़ूदा शाखाओं के पूर्ण स्वामित्ववाली संस्था के रूप में परिवर्तन के द्वारा उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी । चरण दो, अप्रैल 2009 में प्रारंभ, प्राप्त अनुभवों की समीक्षा के बाद और बैंकिंग क्षेत्र में सभी अंश धारकों के साथ उचित परामर्श के बाद ।

सीमा-शुल्क ढांचे को पूर्व एशियाई देशों के सीमा-शुल्क ढांचों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2005-06 के लिए केन्द्रीय बजट में गैर-कृषि उत्पादों के लिए सीमा-शुल्क की अधिकतम दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है । निवेश को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा पूँजीगत माल तथा पुर्जों पर सीमा-शुल्क कुछ मामलों में 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत और अन्य मामलों में 5 प्रतिशत कर दिया गया है । औषधि तथा बायोटेक क्षेत्रों में प्रयुक्त मशीनों पर सीमा-शुल्क भी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है । इसके अलावा, वस्त्र मशीनों तथा प्रशीतलित वाहनों पर सीमा-शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है ।

लार्सन एण्ड टूब्रो लि. (एल एंड टी), भारत की एक सबसे बड़ी टेक्नोलोजी संचालित कंपनी, एक अग्रणी परियोजना निर्यातक भी है और विश्व बाज़ारों में एकीकृत सेवाएं प्रदान करती है । विश्व बैंक और यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्तपोषित तंज़ानिया में सोंगो-सोंगो गैस इलेक्ट्रिसिटी परियोजना का दृश्य । इसका निष्पादन लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड द्वारा सोंगैस लि., तंज़ानिया के लिए किया जा रहा है । परियोजना का वित्तपोषण विश्व बैंक, यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक आदि ने किया था । एक्ज़िम बैंक ने एल एण्ड टी को बोली मध्यस्थता सहायता तथा ऋण और गारंटियाँ उपलब्ध करायी थीं ।

सांविधिक चल निधि अनुपात (एस एल आर) के निर्धारित सीमाओं को हटाने और विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करने के लिए रिज़र्व बैंक को लचीलापन प्रदान करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन लाया जाएगा । नगदी प्रारक्षित अनुपात (सी आर आर) की सीमाओं को हटाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में भी संशोधन किये जाएंगे जिससे मौद्रिक नीति को अधिक लचीले ढंग से संचालित किया जा सके।

कृषि तथा लघु उद्योग क्षेत्रों को ऋण बढ़ाने के लिए वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति की छमाही समीक्षा में बैंकों द्वारा मार्च 2007 तक विशेष कृषि ऋण-योजना के अंतर्गत अपने प्रत्यक्ष अग्रिमों का 40 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को संवितरित करने, 2005-06 से निजी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजनाओं के निर्माण और लघु उद्योग उद्यमियों के लिए संमिश्र ऋण सीमा को 5 मिलियन रुपये से बढ़ाकर 10 मिलियन रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है ।

100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों तथा बायोटेक्नोलॉजी पार्कों में स्थित इकाइयों को 12 महीने की अवधि के भीतर निर्यात आय का पूरा मूल्य प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी गई है ।

भारत : द्रुतगामी प्रगति

(2004-05 में प्रमुख नीतिगत परिवर्तन)

ऋण नीति

- बैंक मार्च 2007 तक विशेष कृषि ऋण योजनाओं के अंतर्गत अपने अग्रिमों का 40 प्रतिशत तक छोटे तथा सीमांत किसानों को संवितरित करें ।
- 2005-06 से निजी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा विशेष कृषि ऋण योजनाएं तैयार करना ।
- लघु उद्योग उद्यमियों के लिए बैंक की संमिश्र ऋण सीमा में 5 मिलियन रुपये से 10 मिलियन रुपये की वृद्धि ।

व्यापार नीति

- नई विदेश व्यापार नीति 2004-2009 की घोषणा की गई जिसमें अगले पांच वर्षों के भीतर वैश्विक पण्य व्यापार में भारत के प्रतिशत हिस्से को दुगुना करना शामिल है।
- गैर कृषि उत्पादों पर सीमा शुल्क की अधिकतम दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गयी ।
- चुनिंदा पूंजीगत माल तथा पुर्जों, वस्त्र मशीनों और फार्मा एवं बायोटेक क्षेत्रों में निर्दिष्ट मशीनों पर सीमा शुल्क कम किया गया ।

निवेश नीति

- ''हवाई परिवहन सेवाओं (देशी एयरलाइन्स)'' में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा में स्वत: अनुमोदित मार्ग के माध्यम से 49 प्रतिशत तक और स्वत: अनुमोदित मार्ग के माध्यम से अनिवासी भारतीयों द्वारा 100 प्रतिशत तक वृद्धि ।
- कतिपय शर्तों के अधीन टाउनशिप, गृहनिर्माण, निर्मित बुनियादी सुविधा तथा निर्माण-विकास परियोजनाओं में स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति ।
- विदेशी निवेश / तकनीकी सहयोग, जहां विदेशी निवेशक कोई पूर्व संयुक्त उद्यम रखता है या रखता था, के लिए नये प्रस्ताव अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण / ट्रेडमार्क करार की कुछ शर्तों के अधीन स्वत: अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत अनुमति है ।
- बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी निवेश को और उदार बनाया गया, भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के लिए रोडमैप जारी किया गया ।

विदेशी मुद्रा नीति

- 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर-टेक्नोलॉजी पार्कों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों, बायो-टेक्नोलॉजी पार्कों में स्थित इकाइयों को 12 महीने की अवधि के भीतर निर्यात आय का पूर्ण मूल्य प्रत्यावर्तित करने की अनुमति है ।

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लेखों के साथ, इस बैंक द्वारा निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है ।

परिचालनों की समीक्षा

2004-05 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, बैंक ने अपने विभिन्न उधारदात्री कार्यक्रमों के अंतर्गत 158.53 बिलियन रुपये की राशि मंजूर की है जो 2003-04 (अप्रैल-मार्च) में मंजूर की गई 92.66 बिलियन रुपये की राशि के मुकाबले 71.1 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संवितरण 2003-04 के 69.57 बिलियन रुपये की तुलना में 114.35 बिलियन रुपये के थे, इस प्रकार गत वर्ष की तुलना इसमें 64.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 31 मार्च 2005 को ऋण-आस्तियाँ 134.10 बिलियन रुपये की थीं । इनमें गत वर्ष के मुकाबले 24.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है । बैंक ने 2003-04 के 10.79 बिलियन रुपये की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 15.89 बिलियन रुपये की गारंटियाँ मंजूर की हैं । 2003-04 में जारी की गई 5.74 बिलियन रुपये की गारंटियों की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में 16.60 बिलियन रुपये की गारंटियाँ जारी की गयी थीं । 31 मार्च 2005 को बैंक की बहियों में बकाया गारंटियाँ 31 मार्च 2004 के 15.77 बिलियन रुपये की तुलना में 23.73 बिलियन रुपये की थी। यथा 31 मार्च 2005 को कुल ऋण आस्तियों में रुपया ऋणों तथा अग्रिमों का 57.2 प्रतिशत हिस्सा रहा जबकि शेष 42.8 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के ऋण थे । कुल ऋणों तथा अग्रिमों में अल्पावधि-ऋण का हिस्सा 22.4 प्रतिशत था । बैंक ने वर्ष 2003-04 के लिए 3.04 बिलियन रुपये के लाभ की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य निधि लेखे में 3.14 बिलियन रुपये का कर पूर्व लाभ दर्ज किया है । 564 मिलियन रुपये का आय कर का प्रावधान करने के बाद 2004-05 के दौरान कर पश्चात लाभ की राशि 2.58 बिलियन रुपये रही जबकि 2003-04 में यह 2.29 बिलियन रुपये थी। इस लाभ में से 654.4 मिलियन रुपये की राशि भारत सरकार को लाभांश के रूप में अदा की जायेगी । लाभांश के जरिए वितरित लाभ पर कर के लिए 85.5 मिलियन रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है । 1.19 बिलियन रुपये की राशि आरक्षित निधि में अंतरित कर दी गई है । इसके अतिरिक्त बैंक ने निवेश घट-बढ़ आरक्षित निधि लेखे में 150 मिलियन रुपये, ऋण शोधन निधि में 100 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में 400 मिलियन रुपये अंतरित किये हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान निर्यात विकास निधि का कर पूर्व लाभ 17.1 मिलियन रुपये है जबकि 2003-04 में यह 20.9 मिलियन रुपये था । 6.3 मिलियन रुपये का कर प्रावधान करने के बाद कर पश्चात लाभ की राशि 10.8 मिलियन रुपये होती है जबकि वर्ष 2003-04 के दौरान यह राशि 14.7 मिलियन रुपये थी । 10.8 मिलियन रुपये का लाभ अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया गया है ।

वर्ष के वित्तीय परिणाम का अनुमोदन करने के लिए बैंक के निदेशक मंडल की बैठक

व्यवसाय परिचालन

बैंक के व्यवसाय परिचालनों की समीक्षा निम्नलिखित शीर्षों के अधीन प्रस्तुत की गई है :

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

III. नयी पहलें

IV. वित्तीय निष्पादन

V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

VI. संवर्धनात्मक कार्यक्रम

VII. सूचना प्रौद्योगिकी

VIII. शोध एवं विश्लेषण

IX. मानव संसाधन प्रबंधन

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

I. परियोजना, उत्पाद और सेवा निर्यात

निर्यात संविदाएं

वर्ष के दौरान 79.45 बिलियन रुपये की पाँच सौ सत्तर संविदाएँ एक्ज़िम बैंक की सहायता से एक सौ अट्ठानवे भारतीय निर्यातकों ने चौंसठ देशों के लिए प्राप्त कीं, जबकि पिछले वर्ष के दौरान छियानवे भारतीय निर्यातकों द्वारा अड़तालीस देशों के लिए एक सौ चौसठ संविदाएँ प्राप्त की गयी थीं जो 75.43 बिलियन रुपये मूल्य की थीं । एक्ज़िम बैंक / कार्यकारी दल * इस प्रकार की निर्यात संविदाओं को स्वीकृति प्रदान करता है ।

एक्ज़िम बैंक के समर्थन से इस वर्ष के दौरान प्राप्त की गयीं संविदाओं में 23.40 बिलियन रुपये मूल्य की बाईस टर्नकी संविदाएं, 14.90 बिलियन रुपये मूल्य

बैंक के प्रमुख कार्यक्रम

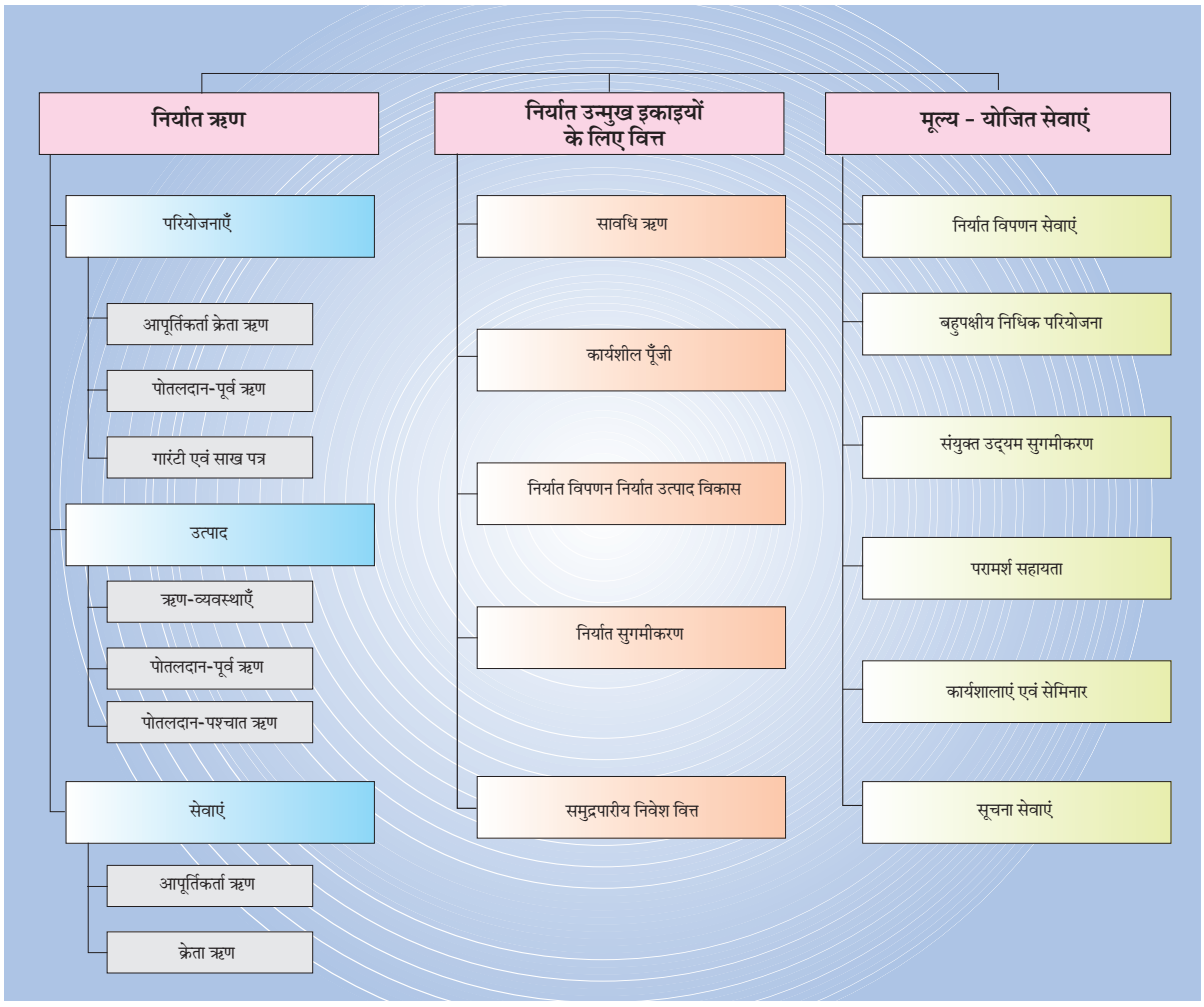

* कार्यकारी दल एक अंतर संस्थागत व्यवस्था है जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम लि., भारत सरकार तथा वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं । यह एक्ज़िम बैंक के तत्वावधान में कार्य करता है ।

की ग्यारह निर्माण संविदाएं, 38.52 बिलियन रुपये मूल्य की पांच सौ छब्बीस आपूर्ति संविदाएं और 2.63 बिलियन रुपये मूल्य की ग्यारह परामर्शदात्री संविदाएं शामिल हैं।

इस वर्ष प्राप्त की गयीं कुछ बड़ी टर्नकी संविदाओं में सूडान में मल्टी-प्राडॅक्ट पाइप लाइन की संविदा, इथियोपिया, इराक, लीबिया, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट; क़तार में खेल और मनोरंजन केंद्र में इलेक्ट्रो - मेकेनिकल कार्य, कोलंबिया में इथेनॉल प्लांट और ताइवान में जल अखनिजीकरण संयंत्र के निर्माण शामिल हैं ।

निर्माण संविदाओं में, ओमान में वॉटर ट्रांसमिशन सिस्टम; अफ़गानिस्तान में सड़कों की पुनर्स्थापना; सउदी अरब में सीवरेज़ लाइन डालना; क़तार में कोफर डैम का निर्माण; बांग्लादेश में गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट और गीनिया के भूमध्य में फैब्रिकेटेड एल एन जी पोत (वेसेल्स) के निर्माण शामिल हैं ।

समीक्षा वर्ष के दौरान प्राप्त प्रमुख आपूर्ति संविदाओं में अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को फार्मास्युटिकल, वस्त्र, रत्न और आभूषण तथा परिष्कृत रसायन का निर्यात, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों को ऑटोमोबाइल्स और ऑटो अनुषंगी, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप देशों को बॉक्साइट तथा पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कृषि उत्पादों के निर्यात शामिल हैं ।

कतिपय प्रमुख तकनीकी परामर्शदात्री और सेवा संविदाओं में ईरान में रिग का चार्टर हायर करना, सउदी अरब में सीमेंट संयंत्रों का प्रबंधन और कुवैत में बहि:स्राव अभिक्रिया के लिए भंडारण टंकियों तथा पानी निपटान संयंत्रों की स्थापना, ग्याना में प्रापण प्रशासन को सुदृढ़ करना तथा क़तार में फ्लोटिंग रूफ गैसोलिन भंडारण टंकियों के लिए इंजीनियरी संबंधी परामर्श देना शामिल हैं ।

निर्यात ऋण और गारंटियाँ

समीक्षा वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और वित्त के जरिये बैंक ने परियोजना निर्यातों के लिए 62.14 बिलियन रुपये मंजूर किये जबकि गत वर्ष में यह मंजूरियाँ 45.58 बिलियन रुपये की थीं। इस प्रकार वर्ष के दौरान मंजूरियों में 36 प्रतिशत वृद्धि का पता चलता है । समीक्षाधीन वर्ष में किये गये संवितरणों की राशि 53.45 बिलियन रुपये थी जो कि पिछले वर्ष के दौरान किये गये संवितरणों की राशि 41.01 बिलियन रुपये की तुलना में है। इनमें 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

मंजूर की गई गारंटियों की राशि गत वर्ष 10.79 बिलियन रुपये की राशि की तुलना में 15.89 बिलियन रुपये थी । ये गारंटियाँ समुद्रपारीय परियोजना क्षेत्र के लिए जैसे कि बिजली उत्पादन, संचारण और वितरण, आधारभूत संरचना विकास और निर्यात बाध्यता गारंटियों से संबंधित थीं ।

ऋण-व्यवस्थाएँ

बैंक ने लघु और मध्यम आकार के उद्यमों पर विशेष फ़ोकस के साथ प्रभावी बाज़ार प्रवेश तंत्र के रूप में ऋण-व्यवस्थाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया है ।

उत्पाद और सेवाओं की श्रेणी

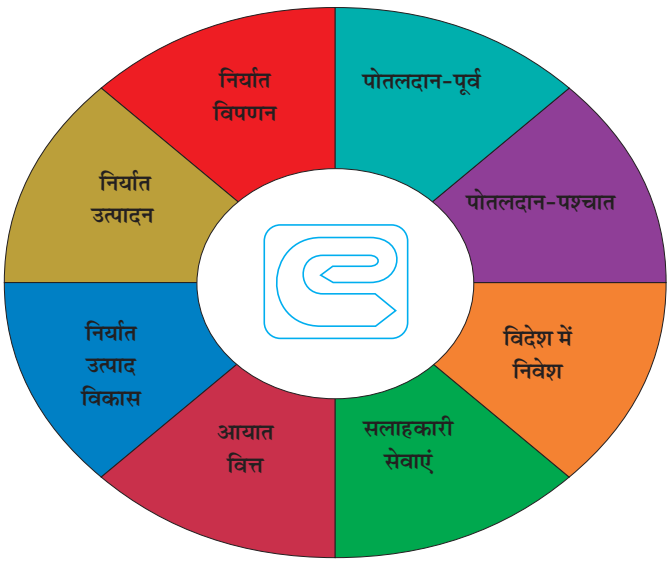

एक्ज़िम बैंक समुद्रपारीय वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, प्रभुता-संपन्न सरकारों और अन्य समुद्रपारीय सत्ताओं को ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान करता है ताकि इन देशों के क्रेता आस्थागित भुगतान शर्तों पर भारत से माल तथा सेवाओं का आयात कर सकें । भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेज़ों के परक्रामण पर किसी दायित्व के बिना एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं । ऋण-व्यवस्था एक ऐसी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों को, विशेषकर लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को वित्तपोषण के विकल्पों का सहारा लेने का एक सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराता है और प्रभावी बाज़ार प्रवेश माध्यम के रूप में कार्य करता है । वृद्धिशील प्रतिस्पर्धी परिवेश होने के कारण एक्ज़िम बैंक अपने ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के अधीन तत्परतापूर्वक इसकी भौगोलिक पहुँच और मात्रा में विस्तार करना चाहता है ।

समुद्रपारीय संस्थाओं को अपनी स्वयं की ऋण-व्यवस्थाओं के अलावा एक्ज़िम बैंक वर्ष 2003-04 से भारत सरकार के अनुरोध पर तथा की सहायता से विकासशील विश्व में चुनिंदा देशों को भी ऋण-व्यवस्थायें प्रदान करता है तथा परिचालित करता है ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने भारत से परियोजनाओं तथा माल सेवाओं के निर्यात में सहायता देने के लिए 423 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य की सोलह ऋण-व्यवस्थाएँ प्रदान की हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रदान की गईं ऋण-व्यवस्थाओं में, यूनीबैंकों ब्राज़ील, म्यांमा फॉरेन ट्रेड बैंक, म्यांमार; पी टी ए बैंक, अफ्रीका; अंगोला सरकार, ग्याना सरकार, लेसेथो सरकार, मॉरिशस सरकार, मोज़ाम्बिक सरकार, सूरीनाम सरकार, वियतनाम सरकार तथा छह ईरानी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण-व्यवस्थायें प्रदान करना शामिल है। भारत से पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के वित्तपोषण के लिए सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, श्रीलंका को 150 मिलियन यू एस डॉलर की एक ऋण-व्यवस्था प्रवर्तनशील है । कुल 953 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-वचनबद्धता के साथ अड़सठ देशों को शामिल करते हुए चवालीस ऋण-व्यवस्थायें इस समय उपयोग के लिए उपलब्ध हैं और कई ऋण-व्यवस्थायें बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं ।

II. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का सृजन

बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में अभिवृद्धि करने के लिए उद्दिष्ट वित्तपोषण कार्यक्रमों की

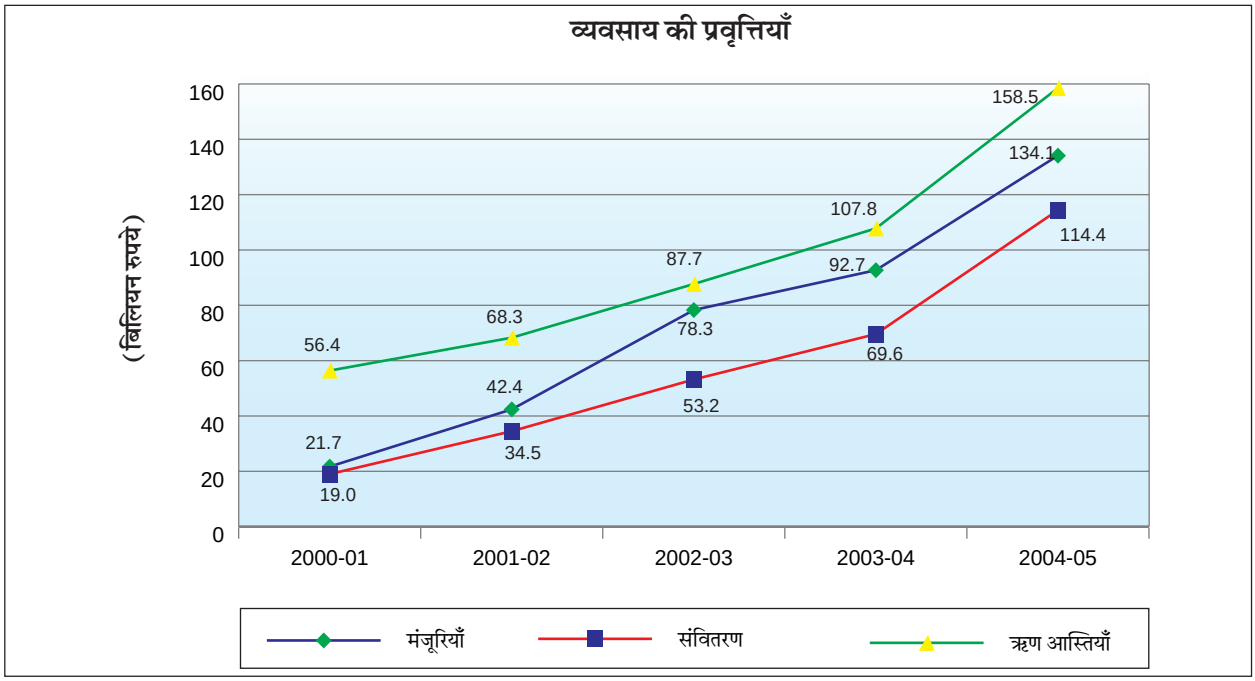

एक शृंखला परिचालित करता है । बैंक ने 2004-05 के दौरान निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में अभिवृद्धि करने के कार्यक्रम के अधीन कुल मिलाकर 83.95 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं । इन कार्यक्रमों के अधीन कुल 57.02 बिलियन रुपये की राशि संवितरित की गयी है ।

निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने उनहत्तर निर्यात उन्मुख इकाइयों को 21.14 बिलियन रुपये के सावधि ऋण मंजूर किये हैं । संवितरणों की राशि 16.31 बिलियन रुपये है ।

उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अधीन अट्ठाईस निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों की प्राप्ति के वित्तपोषण के लिए 7.24 बिलियन रुपये मंजूर किये गये थे। इस कार्यक्रम के अधीन संवितरणों की राशि 4.76 बिलियन रुपये है ।

पैंतालीस कंपनियों को कुल मिलाकर 19.27 बिलियन रुपये के कार्यशील पूँजी ऋण मंजूर किये गये हैं । उक्त कंपनियों को किये गये संवितरणों की राशि 15.97 बिलियन रुपये है ।

बैंक द्वारा वित्तपोषित निर्यात उन्मुख इकाइयों के अंतर्गत वस्त्र, औषधियाँ, रसायन, इंजीनियरी माल, धातु और धातु प्रसंस्करण, उपभोक्ता वस्तुएँ, कागज़, प्लास्टिक और पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर, ऑटो अनुषंगी, नौवहन, बिजली तथा औद्योगिक उपकरण और कृषि आधारित उत्पाद जैसे क्षेत्रों की व्यापक श्रेणी शामिल है ।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

इस बैंक ने भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वस्त्र और पटसन (जूट) उद्योग की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अधीन प्राथमिक उधारदात्री संस्था के रूप में सत्ताईस कंपनियों को कुल मिलाकर 6.69 बिलियन रुपये के ऋण मंजूर किये हैं । संवितरणों की कुल राशि 2.28 बिलियन रुपये है ।

बैंक ने राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन, और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. के साथ लघु व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मकता विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम को सह-प्रायोजित किया । इस कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल के देशों के लिए प्रतिस्पर्धी लघु व्यवसाय नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से संस्थागत क्षमता के निर्माण पर ज़ोर दिया गया । छोटे तथा मध्यम आकार के उद्यमों के निर्यातक ग्राहकों के एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य समूह हैं और बैंक का एस एम ई समूह इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित रूप से देखने का प्रयास करता है । लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्री माननीय श्री महावीर प्रसाद ने पाँच दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया जिसमें 33 राष्ट्रमंडल देशों से 57 सहभागियों ने भाग लिया ।

समुद्रपारीय निवेश वित्त कार्यक्रम

बैंक के पास भारतीय बाह्य निवेश में सहायता देने के लिए ईक्विटी वित्त, ऋण, गारंटियों तथा सलाहकारी सेवाओं की दृष्टि से एक व्यापक कार्यक्रम है । चुनिंदा मामलों में बैंक भारतीय प्रवर्तक के साथ ईक्विटी हिस्सा लेता है ।
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ग्यारह कंपनियों को सात देशों में उनके समुद्रपारीय आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल 5.48 बिलियन रुपये की निधिक तथा गैर-निधिक सहायता मंजूर की गयी । एक्ज़िम बैंक ने अब तक 43 देशों में 100 से अधिक कंपनियों द्वारा स्थापित 122 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है । समुद्रपारीय निवेश के लिए प्रदान की गई कुल सहायता राशि 18.88 बिलियन रुपये रही । वर्ष के दौरान बैंक द्वारा वित्तपोषित समुद्रपारीय निवेशों में ऋण तथा ईक्विटी सहायता दोनों के माध्यम से इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील प्लांट का अधिग्रहण, संयुक्त राज्य अमेरिका में बी पी ओ सेवा कंपनी का अधिग्रहण, डेनमार्क में एक फार्मास्युटिकल कंपनी का अधिग्रहण, ट्रान्सफार्मर का विनिर्माण करनेवाली एक इंजीनियरी कंपनी, जिसका मुख्यालय बेल्जियम में है और फैक्टरियाँ पाँच देशों में स्थित हैं, का अधिग्रहण, यू के में एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का डीलर नेटवर्क की स्थापना करने के लिए वित्त, ब्राज़ील,संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी के जरिये निधिक / गैर निधिक सहायता,

संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ऑटो अनुषंगी इकाई का अधिग्रहण जिसमें ऋण और ईक्विटी सहायता दोनों शामिल हैं ।

निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 4.48 बिलियन रुपये की राशि मशीन टूल्स उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के लिए मंजूर की । कुल संवितरण 3.15 बिलियन रुपये के थीं।

आयात के लिए वित्त

थोक आयात वित्त

थोक आयात वित्त कार्यक्रम के अधीन मंजूरियों और संवितरणों की राशि क्रमश: 12.37 बिलियन रुपये और 7.39 बिलियन रुपये थी ।

आयात वित्त कार्यक्रम

आयात वित्त कार्यक्रम के अधीन आठ कंपनियों को 11.63 बिलियन रुपये के सावधि ऋण मंजूर किये गये । संवितरणों की राशि 3.43 बिलियन रुपये थी ।

ऋण वसूली समूह

बैंक के भीतर एक सुस्थापित ऋण निगरानी वसूली नीति के साथ एक ऋण वसूली समूह कार्यरत है । प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की प्रणाली और विधिवत गठित समिति द्वारा कमज़ोर (स्ट्रेस) आस्तियों की मासिक समीक्षा के साथ ऋण खातों के ए बी सी वर्गीकरण की एक प्रणाली के माध्यम से मानक आस्तियों के अवमानक आस्तियों की श्रेणी में जाने से रोकने के लिए तत्परतापूर्वक कदम उठाये जाते हैं । एकबारीय निपटान (ओ टी एस) प्रस्तावों की जाँच करने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और विधि तथा बैंकिंग के क्षेत्रों में गहन अनुभव रखने वाले दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से युक्त एक स्वतंत्र जाँच समिति का गठन किया गया है। यह समिति बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है ।

स्ट्राइड्स एर्कोलैब लि., बैंगलोर के समुद्रपारीय उद्यम सेलोफार्म लि., ब्राज़ील, जिसे एक्ज़िम बैंक ने विदेशी निवेश वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी है, में भारत से निर्यात किये गये जिनरिक्स से फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए उत्पादन लाइन । सेलोफार्म लि. फार्मास्युटिकल फार्मूलेशनों के विनिर्माण तथा विपणन में लगी है और मुख्यतः ब्राज़ील में अस्पतालों तथा निजी आपूर्तिकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करती है ।

III. नयी पहलें

लघु एवं मध्यम उद्यम समूह

बैंक ग्राहकों के एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य समूह के रूप में लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों पर विशेष ध्यान दे रहा है । चूंकि उधारकर्ताओं की एक श्रेणी के रूप में लघु एवं मध्यम उद्यमों की ऋण ज़रूरतें तथा अन्य सहायता आवश्यकताएं होती हैं जो बड़ी कंपनियों की आवश्यकताओं से सुस्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं अत: बैंक ने एक संकेंद्रित तरीके से इस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए एक लघु एवं मध्यम उद्यम समूह की स्थापना करने की पहल की है। समूह 750 मिलियन रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों / फर्मों के प्रस्तावों पर कार्रवाई करता है । समूह का प्राथमिक उद्देश्य बैंक के विदेशोन्मुख लघु एवं मध्यम उद्यम ग्राहकों का एक संविभाग विकसित करना और इन ग्राहकों को निर्बाध ऋण वितरण सुनिश्चित करना है ।

लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बैंक की सहायता में नई परियोजनाओं की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार के लिए सावधि ऋण तथा उपकरण वित्त और कार्यशील पूँजी सावधि ऋणों सहित पोतलदान-पूर्व / पोतलदान-पश्चात ऋण के जरिए निर्यात ऋण शामिल हैं । वर्ष के दौरान वस्त्र, सिले-सिलाये वस्त्र, रसायन, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल, ऑटो-पुर्जे तथा इंजीनियरी माल जैसे विभिन्न क्षेत्रों से समूचे देश में लघु एवं मध्यम

उद्यमों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया गया है । वर्ष के दौरान बैंक ने 1.34 बिलियन रुपये की ऋण सुविधांए मंजूर की थीं ।

कृषि व्यापार समूह

एक्ज़िम बैंक ने कृषि निर्यात की एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की है और एक 'कृषि व्यापार समूह' की स्थापना की है जिसका उद्देश्य निर्यात संभावना रखनेवाले कृषि व्यापार को सुगम बनाना, संवर्धित तथा वित्तपोषित करना है । वर्ष 2004-05 के दौरान कृषि व्यापार समूह की मंजूरियाँ तथा संवितरण क्रमश: 5.82 बिलियन रुपये तथा 4.95 बिलियन रुपये के थे । वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को बैंक द्वारा प्रदान किए गए सावधि वित्त में खाद्य प्रसंस्करण, पुष्पकृषि, फल तथा सब्जी और संविदा कृषि क्षेत्रों के लिए सावधि वित्त शामिल था । बासमती चावल, गेहूँ, चीनी, कॉफी, मक्का, पशुचारा, सींगदाना, हर्बल अर्क, काजू, तिल, मशरूम, खीरा तथा ताज़ा फल व सब्जियाँ जैसे विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों के निर्यात का वित्तपोषण करने के लिए पोतलदान-पूर्व तथा पोतलदान-पश्चात ऋण भी मंजूर किये गये । इन उत्पादों के लिए निर्यात बाज़ारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कोरिया गणराज्य, सिंगापोर, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं ।

बैंक का द्विमासिक प्रकाशन 'कृषि निर्यात लाभ' अंग्रेजी, हिंदी और दस प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है । यह पत्रिका विश्व व्यापार संगठन संबद्ध मुद्दों, कृषि आधारित उत्पादों के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं / सहायता, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की नवीनतम जानकारी प्रदान करती है । इस पत्रिका में

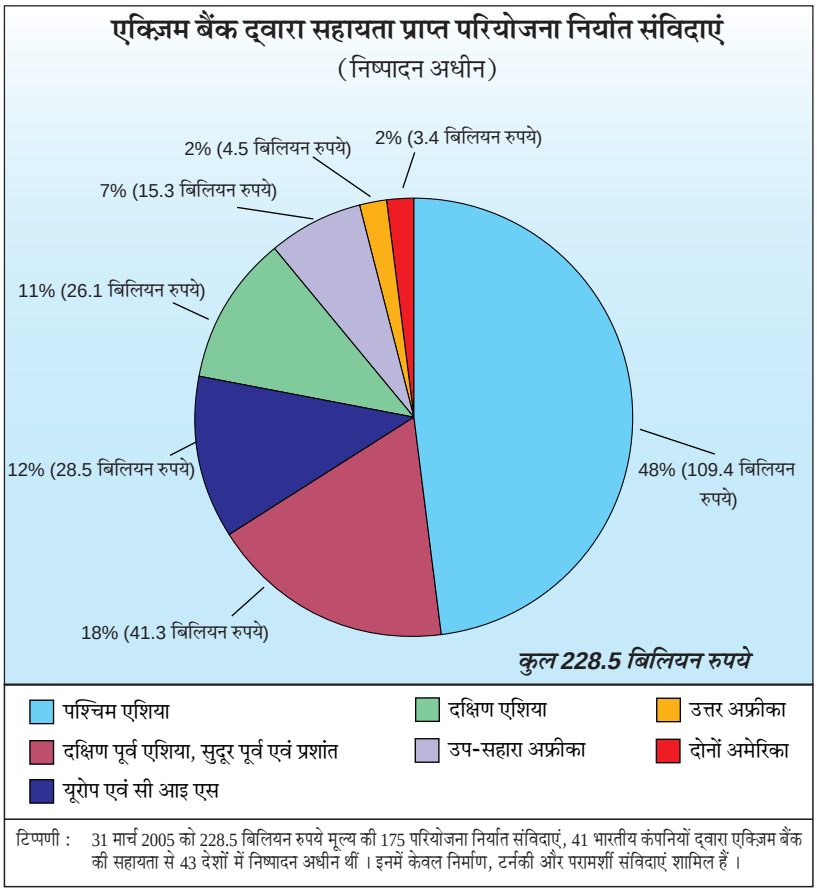

एक्ज़िम बैंक, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ई सी जी सी) और विश्व बैंक की बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एम आइ जी ए) ने एक साझेदारी का गठन किया है जो सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करेगा जिसमें विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों की जोखिम में कमी के साथ प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तपोषण शामिल हैं । इसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों के बाह्य विस्तार में सहायता देना है क्योंकि भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश के अवसरों की लगातार तलाश में रहती हैं । भारतीय कंपनियों द्वारा जावक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिवर्ष लगभग 1 बिलियन यू एस डॉलर है और यह बढ़ रहा है ।

विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार विश्लेषण तथा उच्च निर्यात संभाव्यता रखनेवाले कृषि उत्पादों पर जानकारी भी निहित होती है ।

बैंक का कृषि पोर्टल (www.eximbankagro.com), एक इनहाउस आइ टी पहल, निर्यात बाज़ारों पर उत्पादवार सूचना तथा सलाहकारी सेवाएं, मूल्य प्रवृत्तियों, मौसम की जानकारी, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित जानकारी, जैव प्रौद्योगिकी पर जानकारी, प्रमाणन, पेटेंट, नीतियां, प्रकरण अध्ययन, बेंचमार्किंग और गुणवत्ता संबंधी जानकारी तथा बैंक से संबंधित घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है । इसकी विशेषताओं में संतुलित संदेश बोर्ड, बातचीत सुविधा और क्रय-विक्रय मंच भी उपलब्ध हैं ।

बैंक ने इस क्षेत्र से संबद्ध संगठनों जैसे नाबार्ड, अपेडा, कृषि वित्त निगम लिमिटेड, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और लघु कृषक कृषि व्यवसाय सहायता संघ के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किया है जो भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात को और बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी संबंधित शक्तियों को बढ़ाने में सहायता करता है ।

खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर प्रकाशन

बैंक ने विशेषकर अफ्रीका तथा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल क्षेत्र में छोटे पैमाने की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सी एफ टी आर आइ) के साथ एक सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं । वर्ष के दौरान बैंक ने 'मार्केट मेकर : टेक्नोलॉजी एडेड बिज़नेस सोल्यूशन्स' शीर्षक प्रकाशन प्रकाशित किया है जिसमें सी एफ टी आर आइ प्रौद्योगिकियों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में परियोजना प्रोफाइल निहित है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल), जो विश्व में विद्युत संयंत्र उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में एक स्थान रखती है, ऊर्जा बुनियादी क्षेत्र में भारत से इंजीनियरी उत्पादों तथा सेवाओं का एक सबसे बड़ा टर्न-की निर्यातक है । लीबिया की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के लिए लीबिया में भेल द्वारा निष्पादित की जा रही गैस टर्बाइन आधारित बिजली परियोजना (वेस्ट माउंटेन गैस पॉवर प्रोजेक्ट) 4 X 156.1 मे.वा. अल-जबल अल-घार्बी का एक दृश्य । एक्ज़िम बैंक ने कंपनी को गारंटी तथा ऋण प्रदान किये हैं ।

अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग

बैंक ने 2004-05 के दौरान अपने सबसे पहले विदेशी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय बांड निर्गम के लिए अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों से ऋण रेटिंग प्राप्त की है । इस निर्गम को देश की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य मूडीज़ द्वारा बी ए ए 3, फिच द्वारा बी बी + तथा एस एण्ड पी द्वारा बी बी (बाद में संप्रभु रेटिंग के उन्नयन पर एस एण्ड पी ने इसे बढ़ाकर बी बी + किया) प्रदान की गई । जुलाई 2004 में अंतरराष्ट्रीय ऋण पूंजी बाज़ार में बैंक के 250 मिलियन यू एस डॉलर के सबसे पहले निर्गम को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से अच्छा प्रतिसाद मिला है।

सेवा क्षेत्र का वित्तपोषण

वर्ष के दौरान वित्तपोषित सेवा क्षेत्र में मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, आतिथ्य और नौवहन शामिल हैं। वर्ष के दौरान मनोरंजन उद्योग में फिल्म उत्पादन में लगी तीन कंपनियों को ऋण प्रदान किये गये । वर्ष के दौरान बैंक द्वारा वित्तपोषित सात फिल्मों (छह हिंदी, एक तमिल) में से रिलीज की गई सभी तीनों हिंदी फिल्में भारत तथा विदेशों में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं और समुद्रपारीय बाज़ारों में डी वी डी / वी सी डी / केबल अधिकार की बिक्री से आय को छोड़कर 8 मिलियन यू एस डॉलर से अधिक की

विदेशी मुद्रा आय हुई है । तीन अन्य हिन्दी फ़िल्में शीघ्र ही रिलीज़ होने वाली हैं । बैंक ने अत्यधिक चुनिंदा आधार पर फिल्म वित्तपोषण के कारोबार में प्रवेश किया है। फिल्म वित्तपोषण के प्रति बैंक का दृष्टिकोण विदेशी मुद्रा आय अर्जित करनेवाली परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देना है और पिछले अच्छे रिकार्ड वाले उधारकर्ताओं का चयन करना है ।

ईक्विटी तथा अन्य संरचित वित्त उत्पाद

एक्ज़िम बैंक ने परियोजना वित्त और ट्रेज़री परिचालनों के हिस्से के रूप में ईक्विटी संबद्ध उत्पाद उपलब्ध कराना भी शुरू किया है । वर्ष के दौरान बैंक 100 मिलियन यू एस डॉलर से अधिक राशि के कई नवोन्मेषी संरचित वित्त लेन-देनों में शामिल था । इनमें शामिल हैं: एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु कंपनी के अंतरराष्ट्रीय परिचालनों के लिए वित्त, तेल तथा गैस की खोज, ड्रिलिंग और उत्पादन के लिए वित्त, दूरसंचार उपकरण के आयात तथा आपूर्ति के लिए प्राप्यों के प्रतिभूतिकरण के प्रति वित्त और इस्पात क्षेत्र में एक कंपनी की ओर से निष्पादन गारंटी जिससे वह अंतरराष्ट्रीय वित्त प्राप्त कर सके ।

डिवेलपमेंट बैंक ऑफ ज़ांबिया तथा वेस्ट अफ्रीकन डिवेलपमेंट बैंक (बी ओ ए डी) में निवेश

बैंक ने 2004-05 में डिवेलपमेंट बैंक ऑफ ज़ांबिया में ईक्विटी सहभागिता की है । डिवेलपमेंट बैंक ऑफ ज़ांबिया एक विकास वित्त संस्था है जिसे ज़ांबिया के आर्थिक विकास के संवर्धन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए पुनर्संरचित किया गया है । एक्ज़िम बैंक ने भारतीय फर्मों के लिए निर्यात तथा निवेश अवसर को मज़बूत करने के लिए डिवेलपमेंट बैंक ऑफ ज़ांबिया के साथ एक रणनीतिक साझेदारी व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये हैं । एक्ज़िम बैंक ने वेस्ट अफ्रीकन डिवेलपमेंट बैंक (बी ओ ए डी), जिसका मुख्यालय अफ्रीका में टोगो की राजधानी लोम में स्थित है, में भी ईक्विटी हिस्सा लिया है । भारतीय एक्ज़िम बैंक बी ओ ए डी के शेयरधारक के रूप में शामिल की जानेवाली पहली गैर-क्षेत्रीय तथा गैर-यूरोपीय संस्था है । बी ओ ए डी भारत से पश्चिम अफ्रीका को व्यापार, निवेश तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय एक्ज़िम बैंक के साथ संस्थागत संबंधों को सदृढ़ करने का इच्छुक है । इन दोनों संस्थाओं में बैंक का बोर्ड स्तर पर प्रतिनिधित्व है ।

पी टी जिंदल स्टेनलेस इंडोनेशिया (पी टी जे एस), जो जिंदल स्टेनलेस लि. (जे एस एल), नई दिल्ली के पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कंपनी हैं, के शॉप फ्लोर का एक दृश्य । एक्ज़िम बैंक के समुद्रपारीय निवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सावधि ऋण सहायता से जे एस एल द्वारा 50,000 टन प्रति वर्ष कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉयल और शीटों का विनिर्माण करने के लिए समुद्रपारीय सुविधा का अर्जन किया गया था । बैंक ने भारत से हॉट रोल्ड शीट के आयात के लिए पी टी जे एस को क्रेता ऋण भी प्रदान किया है ।

भारत अफ्रीका व्यवसाय पर तिमाही प्रकाशन

'इंडो अफ्रीकन बिज़नेस' शीर्षक से एक तिमाही द्विभाषी पत्रिका अगस्त 2004 में शुरू की गई । यह पत्रिका भारत तथा अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश पर फ़ोकस करती है । यह पत्रिका, जो एक्ज़िम बैंक की एक पहल है, उन कंपनियों की व्यावसायिक सूचना आवश्यकताओं को पूरा करती है जो अफ्रीकी क्षेत्र के साथ व्यापार तथा निवेश में रुचि रखती हैं । यह पत्रिका भारत तथा अफ्रीकी क्षेत्र में प्रमुख ग्राहकों और दूतावासों में व्यापक रूप से वितरित की जाती है । यह एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रकाशित दूसरी क्षेत्र विशिष्ट पत्रिका है, अन्य पत्रिका 'इंडो लैक बिज़नेस' तिमाही द्विभाषी पत्रिका लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसे ग्राहकों ने खूब पसंद किया है ।

विदेशी व्यापार मेलों में सहभागिता

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक संबंधों को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से बैंक ने भारतीय इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अलमाटी, कज़ाखिस्तान में आयोजित ''मेड इन इंडिया शो'' में भाग लिया और अपने उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदर्शित किया ।

सेमिनार तथा कार्यशालाएं

बैंक ने कई क्षेत्रों में अपनी पहलों की प्रमुख विशेषताओं को प्रदर्शित करने, अपने ग्राहकों को घटनाक्रमों से अवगत कराने और व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक सुगमकारी वातावरण बनाने के लिए कई संकेन्द्रित सेमिनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया । आयोजित किये गये मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

'परियोजना निर्यात' - भारतीय संभाव्यता को समझना विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन तथा 'भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी 2005' पर सेमिनार, दोनों भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किये गये । इस उच्च स्तरीय सेमिनार में विभिन्न अफ्रीकी देशों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा उद्योग से प्रतिनिधियों के अलावा कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के वाइस प्रेसिडेंट, चाड के उप प्रधान मंत्री तथा कैबिनेट मंत्रियों सहित 24 अफ्रीकी देशों से 230 प्रतिनिधियों ने भाग लिया ; 'अफ्रीकी विकास बैंक निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय के अवसर' विषय पर सेमिनार अफ्रीकी विकास बैंक के विशेषज्ञ संकाय की सहायता से नई दिल्ली, मुंबई तथा बैंगलोर में आयोजित किये गये । नई दिल्ली सेमिनार की एक प्रमुख विशेषता अफ्रीकी विकास बैंक के प्रेसिडेंट श्री ऊमर कब्बाज की उपस्थिति थी । एशियाई

यथा 31 मार्च 2005 को परिचालन गत ऋण-व्यवस्थाएं

(मिलियन यू एस डॉलर में)

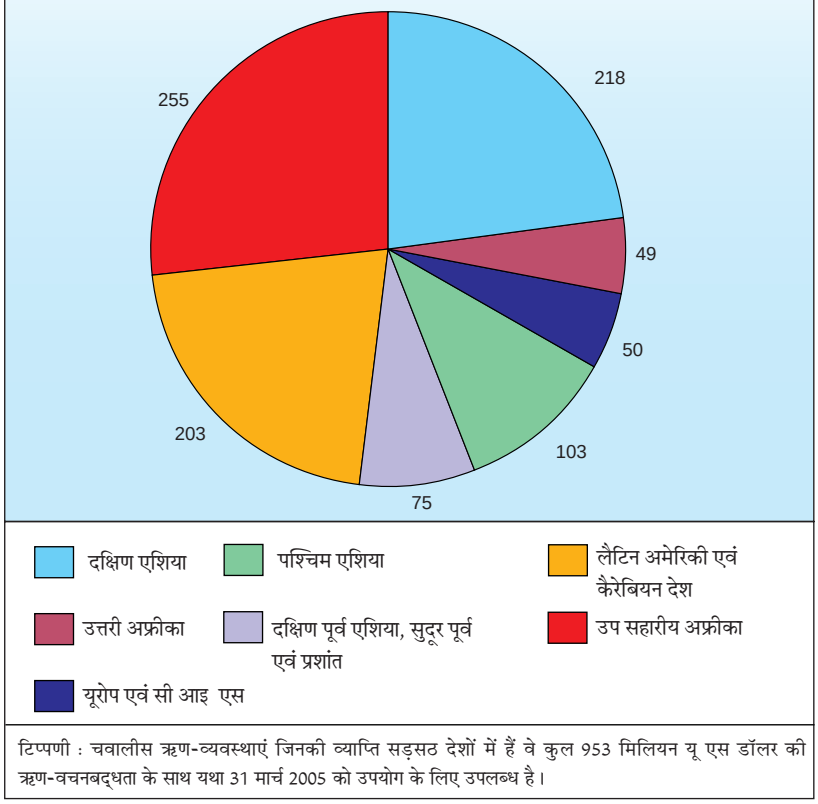

टिप्पणी : चवालीस ऋण-व्यवस्थाएं जिनकी व्याप्ति सड़सठ देशों में हैं वे कुल 953 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-वचनबद्धता के साथ यथा 31 मार्च 2005 को उपयोग के लिए उपलब्ध है।

के ई सी इंटरनेशनल लि. (के ई सी) विश्व में एक सबसे बड़ी विद्युत पारेषण टर्न-की संविदाकार है और इसने विश्वभर में ३५,००० किमी से अधिक पारेषण लाइनों का निर्माण किया है । ऊपर का चित्र के ई सी द्वारा इंडोनेशिया में कार्यान्वित की जा रही पारेषण लाइन परियोजना का है । एक्जिम बैंक ने के ई सी को गारंटी तथा ऋण प्रदान किये हैं ।

विकास बैंक तथा परामर्शदात्री विकास केन्द्र के सहयोग से नई दिल्ली तथा मुंबई में 'देशी परामर्शी सेवाओं का विकास' विषय पर सेमिनार आयोजित किए गए। इसके लिए एशियाई विकास बैंक से विशेषज्ञ संकाय का सहयोग मिला । एक्ज़िम बैंक - बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (विश्व बैंक समूह की) - भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम साझेदारी कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया जो बाह्य निवेश को सहायता देने के लिए वित्तपोषण तथा बीमा समाधान प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की व्यवस्था करता है । बैंगलोर में 'यूरोप में भारतीय फर्मों के लिए बाज़ार प्रवेश तथा बाज़ार पहुँच रणनीतियाँ' तथा मुंबई में 'यूरोपीय देशों में बाज़ार पहुँच तथा तकनीकी आवश्यकता' विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं । ये कार्यशालाएं विकासशील देशों से आयात संवर्धन हेतु केन्द्र, नीदरलैंड के सहयोग से आयोजित की गईं । अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान, वाशिंग्टन डी.सी. के सहयोग से मुंबई में 'दक्षिण एशिया में निवेश, संवृद्धि तथा सुधार को बढ़ावा देना' विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया । स्वैच्छिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास समिति, चैन्नई के सहयोग से नई दिल्ली में इंटरनैशनल हेल्थ केयर एण्ड हर्बल एक्सपो का आयोजन किया गया ।

संयुक्त उद्यम

एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड (जी टी एफ), वेस्टडयूश लैंडेस बैंक गिरोज़ेनट्रेल (वेस्ट एल बी), जर्मनी और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वांशिग्टन डी. सी. का संयुक्त उपक्रम है । इसने वित्त वर्ष 2004-05 में 19 बिलियन रुपये का टर्नओवर और 61.2 मिलियन रुपये का निवल लाभ दर्ज किया । एफ आइ एम बैंक, माल्टा ने अब समुद्रपारीय साझेदार के रूप में वेस्ट एल बी को प्रतिस्थापित किया है । जी टी एफ लगातार विश्व व्यापार के बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कार्यरत छोटे और मध्यम भारतीय निर्यातकों के लिए बाज़ार आधारित वित्तपोषण की समस्याओं का समाधान निकालता है । जी टी एफ भारत में पहली बार ज़रूरत के मुताबिक विदेश व्यापार वित्तपोषण उत्पादों जैसे फॉरफेटिंग और फैक्टरिंग सेवाएं प्रदान करता है ।

बैंक के दूसरे संयुक्त उद्यम, ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट्स लि. (जी पी सी एल) ने लाभप्रद परिचालनों का एक और वर्ष पूरा किया । कंपनी ने वित्त वर्ष 2004-05 में 15.38 मिलियन रुपये की परामर्शी आय और 4.68 मिलियन रुपये का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया । जी पी सी एल ने यूगांडा, मालवी, नाइजीरिया, एरिट्रिया, घाना तथा रुमानिया में विश्व बैंक द्वारा निधिक स्वतंत्र प्रापण समीक्षा नियत कार्य सहित कई नियत कार्य प्राप्त किये हैं । जी पी सी एल एक्ज़िम बैंक और विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली 13 अन्य प्रतिष्ठित निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है । जी पी सी एल विभिन्न विकासशील देशों में बहुपक्षीय निधीयन एजेंसियों द्वारा निधिक परियोजनाओं के लिए प्रापण संबंधी सलाहकारी तथा लेखा परीक्षा सेवाएँ प्रदान करता है ।

पी एल ई आइ यूनिवर्सिटी, मेक्सिको के प्रबंध छात्रों ने भारत में अपने अध्ययन दौरे के एक हिस्से के रूप में बैंक का दौरा किया । एक्ज़िम बैंक अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंधों को मज़बूत बनाने के लिए एजेंसियों / संस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ता है । बैंक ने बैंकोमेक्स्ट, मेक्सिको को 10 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था प्रदान की है ।

उद्योग के साथ परस्पर संपर्क

एक्ज़िम बैंक उद्योग जगत के साथ नियमित रूप से परस्पर संवाद और विचारों का आदान-प्रदान करता है और

सहक्रियात्मक वेबसाइट के माध्यम से विशेषज्ञों तथा चुनिंदा निर्यातक कंपनियों के साथ निरन्तर संपर्क बनाये हुए है ।

IV. वित्तीय निष्पादन

संसाधन

31 मार्च 2005 को 8.50 बिलियन रुपये की चुकता पूँजी तथा 16.62 बिलियन रुपये की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन 184.27 बिलियन रुपये के थे । बैंक के संसाधन आधार में बांड, जमा - प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा राशियाँ / उधार राशियाँ / दीर्घावधि स्वैप शामिल हैं ।

इस बैंक ने अल्पकालिक नकदी निधि प्रबंधन के हिस्से के रूप में 17.05 बिलियन रुपये अंकित मूल्य के वाणिज्यिक पत्र जारी किये हैं । वर्ष के दौरान, बैंक ने 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए बांडों के निजी विनियोजन के जरिए 9.55 बिलियन रुपये की राशि जुटायी है । बैंक ने बैंकों से 5.25 बिलियन रुपये के सावधि ऋण भी प्राप्त किये हैं ।

बैंक की ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों, क्रिसिल तथा इक्रा से उच्चतम रेटिंग अर्थात 'ए ए ए' प्राप्त है । 31 मार्च 2005 को बांडों तथा वाणिज्यिक पत्रों सहित रुपया उधार 93.18 बिलियन रुपये का था ।

बैंक के यूरो डॉलर बांडों / अस्थिर दर वाले नोटों के जरिए 300 मिलियन यू एस डॉलर तथा वाणिज्यिक बैंकों की तटीय निधियों में से उधार / पारस्परिक सावधि जमाराशियों के जरिए 50 मिलियन यू एस डॉलर जुटाये हैं । वर्ष के दौरान बैंक ने निर्यात ऋण के जरिए वित्त प्रदान करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। बैंक ने वर्ष 2004-05 के दौरान रुपये/यू एस डॉलर मध्यावधि स्वैप के जरिए 100 मिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा विनिमय भी किये ।

दक्षिण भारत में कर्नाटक में घेरकिन (पिकलिंग कुकम्बर) का दृश्य । कर्नाटक के होस्कोट तालुका में ओबलापुरा में स्थित एक 100% निर्यात इकाई ग्लोबल ग्रीन कंपनी लि. (जी जी सी एल) के संयंत्र में प्रसंस्करण के लिए लगभग 10,000 मीट्रिक टन खीरा पैदा किया जाता है । जी जी सी एल के निर्यातों से 10,000 से अधिक छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित हुए हैं ।

31 मार्च 2005 को बैंक के पास 1.40 बिलियन यू एस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन का भंडार था ।

आय / व्यय

2004-05 के दौरान बैंक का कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश : 3.14 बिलियन रुपये और 2.58 बिलियन रुपये रहा जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमश: 3.04 बिलियन रुपये और 2.29 बिलियन रुपये थे । ब्याज, बट्टा, विनिमय, कमीशन, दलाली और शुल्क से युक्त कारोबार आय वर्ष 2003-04 के दौरान 9.11 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2004-05 में 10.81 बिलियन रुपये रही । निवेश आय 2003-04 के 3.26 बिलियन रुपये की तुलना में वर्ष 2004-05 में 3.79 बिलियन रुपये थी । वर्ष 2004-05 में ब्याज व्यय 7.42 बिलियन रुपये था जो ऋण की अधिकता के कारण 1.17 बिलियन रुपये से उच्चतर है । गैर ब्याज खर्च 2003-04 के 6.47 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 के दौरान कुल व्यय का 6.13 प्रतिशत बनता है। उधार राशियों की औसत लागत (औसत उधार राशियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज व्यय) 31 मार्च 2004 में 5.96 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2005 को 5.68 प्रतिशत रह गयी ।

पूँजी पर्याप्तता

जोखिम आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सी आर ए आर) भारतीय रिज़र्व

बैंक द्वारा नियत 9 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2004 के 23.48 प्रतिशत के मुकाबले 31 मार्च 2005 को 21.58 प्रतिशत रहा। 31 मार्च 2005 को ऋण ईक्विटी अनुपात 5.43:1 रहा जबकि 31 मार्च 2004 को यह 5.30:1 था ।

ऋण सहायता (एक्सपोज़र) के मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए 31 मार्च 2002 से एक उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों का 15 प्रतिशत और समूह उधारकर्ताओं के लिए 40 प्रतिशत की ऋण सहायता सीमा निर्धारित की है । बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विशेष मामलों में 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण सहायता (अर्थात एकल उधारकर्ता के लिए वित्तीय संस्था की पूँजी निधियों के 20 प्रतिशत और उधारकर्ता समूह के लिए पूँजी निधियों के 45 प्रतिशत तक कुल ऋण सहायता) दी जा सकती है । वैयक्तिक उधारकर्ताओं तथा उधारकर्ता समूहों की ऋण सहायता सीमा को क्रमश: अतिरिक्त 5 प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल पूँजी निधियों का 5 प्रतिशत) और 10 प्रतिशत बिंदु (अर्थात कुल पूँजी निधियों का 10 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है (क्रमश: 20 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत अधिकतम सीमाओं के अलावा), बशर्ते अतिरिक्त ऋण सहायता बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए हो ।

यथा 31 मार्च 2005 को ऋणों का क्षेत्रवार वितरण

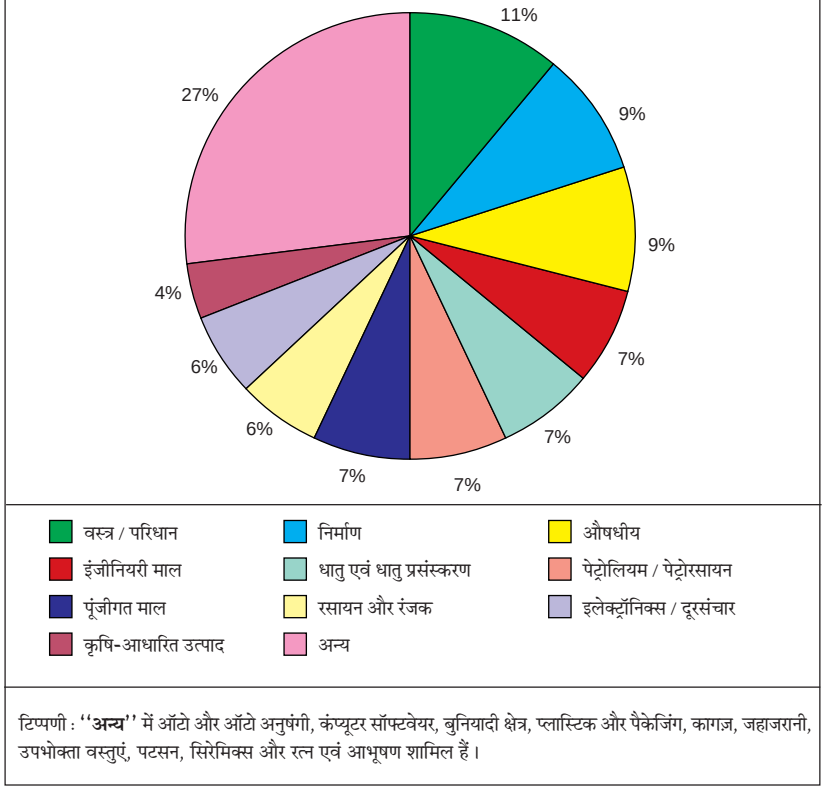

टिप्पणी : ''**अन्य**'' में ऑटो और ऑटो अनुषंगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बुनियादी क्षेत्र, प्लास्टिक और पैकेजिंग, कागज़, जहाजरानी, उपभोक्ता वस्तुएं, पटसन, सिरेमिक्स और रत्न एवं आभूषण शामिल हैं।

31 मार्च 2005 को एकल तथा समूह उधारकर्ताओं को बैंक की वित्तीय सहायता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत पूँजी निधियों की सीमा के भीतर थी । भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं को यह भी सूचित किया है कि वे विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों को ऋण-सहायता के लिए आंतरिक सीमाएं अपनायें ताकि विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का समान रूप से फैलाव हो । बैंक

लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके भूमंडलीकरण प्रयासों में समर्थन देने के लिए नवोन्मेषी उद्यम प्रबंधन विकास सेवा (ई एम डी एस) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र जिनेवा के साथ सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर । यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा किसी देश में पहली बार शुरू किया गया है और आइ टी सी के एक साझेदार के रूप में एक्ज़िम बैंक की भूमिका इस सक्रिय क्षेत्र को समर्थन देने के लिए एक समर्पित लघु एवं मध्यम उद्यम समूह की स्थापना करने में बैंक की पहल के साथ अच्छा मेल खाता है ।

के लिए उद्योग सहायता सीमाएं कुल ऋण संविभाग का 15 प्रतिशत है, सिवाय इसके कि वस्त्र उद्योग के मामले में यह 20 प्रतिशत है । 31 मार्च 2005 को किसी एकल उद्योग को बैंक की कुल ऋण सहायता 11 प्रतिशत से अधिक नहीं थी ।

राजकोष

बैंक के पास एक एकीकृत राजकोष है और सभी राजकोषीय कार्य अर्थात् दोनों निधियों (रुपया तथा विदेशी मुद्रा) का प्रबंधन, मुद्रा बाज़ार परिचालन, प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग, विदेशी मुद्रा सौदे आधुनिकतम डीलिंग रूम के माध्यम से किये जाते हैं । बैंक के राजकोष द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों में नकदी / टॉम / हाजिर / वायदा / विदेशी मुद्रा सौदे, ब्याज दर स्वैप / वायदा कर करार / अस्थिर दर ऋण, साख पत्र / गारंटियाँ जारी करना आदि शामिल हैं । बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इंफिनेट) का एक सदस्य है और इसे बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आइ डी आर बी टी) से पंजीकरण प्राधिकारी की हैसियत प्राप्त है । बैंक के पास भारतीय रिज़र्व बैंक की निर्धारित लेन-देन 'प्रणाली के माध्यम से सौदा' करने के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र है, जो भारत सरकार की प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन का एक मंच प्रदान करता है । बैंक की प्रतिभूतियाँ तथा विदेशी मुद्रा लेन-देन मुख्यत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सी सी आइ एल) द्वारा प्रदान की गई गारंटित निपटान सुविधा के जरिए किये जाते हैं ।

बैंक सी सी आइ एल के संपार्श्विकीकृत उधार लेने और उधार देने संबंधित दायित्व खंड का भी एक सदस्य है ।

आस्ति-देयता प्रबंधन

बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति नकदी / ब्याज दरों के जोखिमों की समीक्षा करने तथा उनके सुधारात्मक उपायों पर विचार करने के प्रयोजन से महीने में कम से कम दो बार बैठक आयोजित करती है । बैंक की व्यवसाय / संसाधन योजना वर्ष के प्रारंभ में तैयार की जाती है और वर्ष के दौरान उधार राशियाँ हिस्सों में जुटायी जाती हैं । आस्ति देयता प्रोफाइल में सभी समय खंडों में अंतरों के लिए विवेकपूर्ण सीमायें निर्धारित की गई हैं । बैंक ने एक व्यापक आस्ति देयता प्रबंधन नीति तैयार की है जो बाज़ार जोखिमों के मुख्य तत्वों अर्थात चल निधि, ब्याज दर तथा मुद्रा जोखिमों के प्रबंधन को देखती है । चल निधि जोखिम का प्रबंधन चल निधि नीति

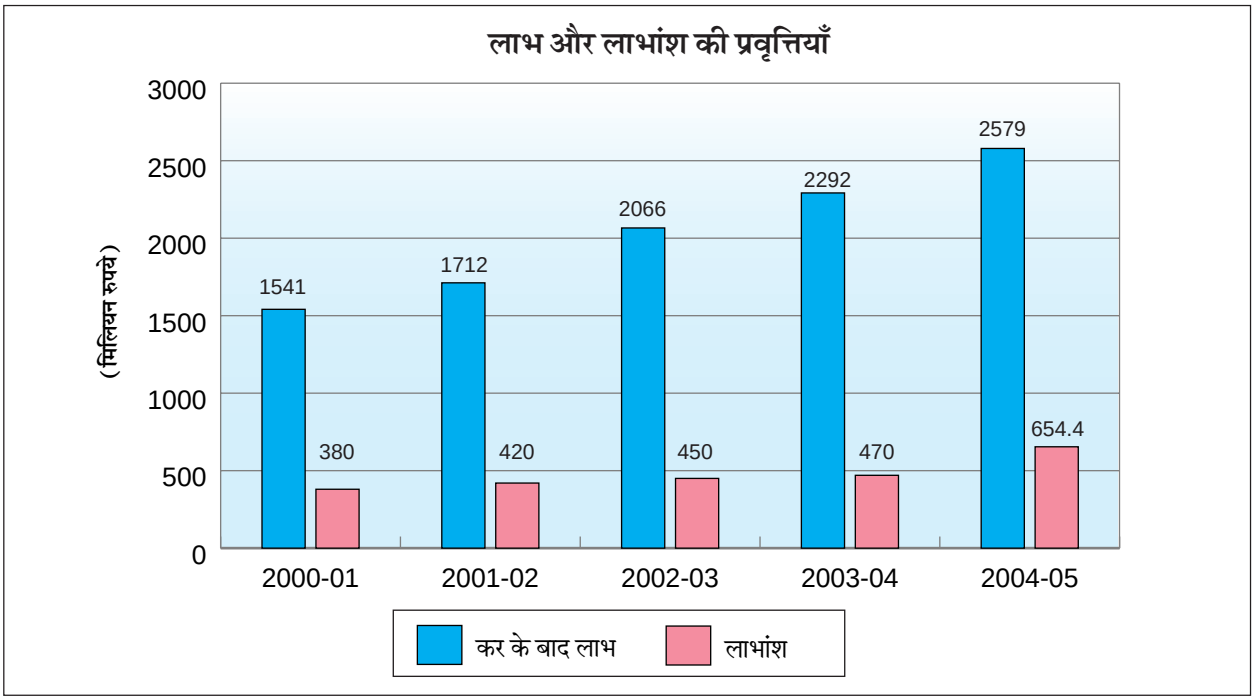

के भीतर किया जाता है जिसमें निधि योजना और आवधिक तनाव परीक्षण शामिल हैं । ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निवल ब्याज आय स्थिरता दृष्टिकोण और अवधि विश्लेषण दृष्टिकोण अपनाए गये हैं । लेखा परीक्षा समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्य की समीक्षा करती है और निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति भी आस्ति देयता प्रबंधन समिति के कार्य का निरीक्षण करती है ।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जो परिचालन समूहों से स्वतंत्र है और यह सीधे शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करती है । एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति विभिन्न जोखिमों (संविभाग, चलनिधि, ब्याज दर, तुलन पत्र से इतर और परिचालन जोखिम), निवेश नीतियों एवं उनसे संबंधित विनियामक तथा अनुपालन मुद्दों के संबंध में बैंक की जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करती है । एकीकृत जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति तथा ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति के परिचालनों का निरीक्षण करती है जिनमें से दोनों के परस्पर कार्यात्मक प्रतिनिधित्व होते हैं । आस्ति देयता प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं से संबधित मुददों को देखती है और बैंक के समग्र बाज़ार जोखिम (चलनिधि, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम) का विश्लेषण करती है, जबकि ऋण जोखिम प्रबंधन समिति ऋण नीति और प्रक्रियाओं को देखती हैं और बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का नियंत्रण करती है ।

आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उस ऋण / कर्ज़ सुविधा को गैर निष्पादक आस्तियों (एन पी ए) के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 180 दिनों से अधिक समय से बकाया है । बैंक की गैर निष्पादक आस्तियाँ (प्रावधान घटाकर) गत वर्ष के 1.26 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2005 को इसके ऋण तथा अग्रिमों (प्रावधान घटाकर) का 0.85 प्रतिशत रहीं हैं ।

माननीय सांसद श्री ए विजयराघवन के नेतृत्व में राज्यसभा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने एक्ज़िम बैंक के साथ चर्चा की ।

आस्ति वर्गीकरण

'अवमानक आस्तियाँ' वे आस्तियाँ होती हैं जिनके ब्याज और / अथवा जिनके मूलधन की किस्तें 180 दिनों से अधिक अतिदेय होती हैं । तथापि जहाँ अवमानक आस्ति 12 माह से अधिक अवधि से गैर निष्पादक संपत्ति के रूप में होती हैं, ऐसी आस्तियों को ''संदिग्ध आस्तियों'' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । ''हानि की आस्तियाँ'' वे होती हैं जो वसूली के योग्य नहीं समझी जातीं । यथा 31 मार्च 2005 को निवल ऋणों तथा अग्रिमों के 0.85 प्रतिशत के स्तर पर निवल गैर निष्पादक आस्तियों में से अवमानक तथा संदिग्ध आस्तियाँ क्रमश: 0.37 तथा 0.48 प्रतिशत आती है और हानि आस्तियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की देखरेख निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है । इस लेखा परीक्षा समिति की एक वर्ष में कम-से-कम छह बैठकें होती हैं । बैंक की लेखा परीक्षा समिति का उद्देश्य बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य की देखरेख करना तथा उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि प्रबंधन के एक माध्यम के रूप में उसकी

प्रभावशालिता में वृद्धि हो और वह सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्टों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाये गये सभी मुद्दों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करे ।

V. सूचना और सलाहकारी सेवाएँ

बैंक सूचना, सलाहकारी और सहायता की ऐसी सेवाओं की एक व्यापक श्रेणी प्रदान करता है जो उसके वित्तपोषण कार्यक्रमों को संपूर्ण बनाती है । ये सेवाएं भारतीय कंपनियों और समुद्रपारीय संस्थाओं को शुल्क के आधार पर प्रदान की जाती हैं । इन सेवाओं के दायरे में बाज़ारों से संबंधित सूचना, क्षेत्र और व्यवहार्यता अध्ययन, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, भागीदारों की खोज, निवेश सुगमीकरण तथा भारत और विदेश दोनों में ही संयुक्त उद्यमों का विकास करना शामिल है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय कंपनियों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान की हैं। दक्षिण अफ्रीका में वॉटर फिल्टरों/ प्यूरीफायर्स तथा वैक्यूम क्लिनर्स के डीलरों तथा / आयातकों पर जानकारी, बहरीन के साथ भारत के व्यापार पर सांख्यकीय आंकड़े और संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के निर्यात संबंधी आंकड़ें निर्यातकों को प्रदान किये गये हैं।

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान

एक्ज़िम बैंक स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान शृंखला, जिसकी शुरुआत बैंक के कारोबार के प्रारंभ के उपलक्ष्य में की गयी थी, को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले समसामयिक व्यापार तथा विकास मुद्दों पर बहस तथा चर्चा करने में एक महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में ख्याति मिली है । श्री रूबिंस रिकोपेरो, पूर्व महासचिव, व्यापार तथा निवेश पर संयुक्त राष्ट्र संघ (अंकटाड) ने ''व्यापार और विकास : विकासशील देशों के लिए चुनौतियाँ'' विषय पर वर्ष 2005 के लिए स्थापना दिवस वार्षिक व्याख्यान दिया ।

भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से बैंक ने भारतीय कंपनियों द्वारा सर्वोत्कृष्ट पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता हेतु एक वार्षिक पुरस्कार शुरू किया है । बैंगलोर में आयोजित सी आइ आइ गुणवत्ता बैठक में 2004 में सात कंपनियों की व्यवसाय उत्कृष्टता की दिशा में उनकी महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सराहना की गई ।

समुद्रपारीय बहुपक्षीय निधिक परियोजनायें (एम एफ पी ओ)

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक तथा यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक द्वारा निधिक परियोजनाओं का व्यवसाय प्राप्त करने की भारतीय कंपनियों की संभावनाओं में वृद्धि करने के संबंध में सहायता करने के लिए बैंक इन कंपनियों को सूचना और सहायता सेवा का पैकेज प्रदान करता है । बैंक ने भारतीय कंपनियों में समुद्रपारीय व्यवसाय के असंख्य अवसरों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार किया है ।

एक परामर्शदाता के रूप में बैंक

विकासशील देश के संदर्भ में एक निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को सहायता देने वाली एक संस्था के रूप में बैंक का अनुभव अन्य विकासशील देशों में विशेष रूप से प्रासंगिक है । बैंक परामर्शी कार्यों को हाथ में लेकर अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता का आदान-प्रदान कर रहा है । बैंक को मॉरिशस सरकार द्वारा 'भारतीय फर्मों के लिए निवेश केन्द्र के रूप में मॉरिशस को प्रक्षेपित करना' पर एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था । यह एक व्यापक आर्थिक सहयोग तथा साझीदारी करार करने पर विचार करने के लिए भारत सरकार तथा मॉरिशस सरकार द्वारा गठित संयुक्त अध्ययन समूह की पृष्ठभूमि में था । बैंक

की रिपोर्ट की खूब सराहना की गई है और सिफारिशों को संयुक्त अध्ययन समूह की रिपोर्ट में शामिल किया गया है । रिज़र्व बैंक ऑफ ज़िम्बाब्वे (आर बी जेड) एक निर्यात-आयात बैंक की स्थापना के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश के लिए जिम्बाब्वे में एक सहायता संरचना निर्मित करने का दायित्व बैंक को सौंपा है । पहले भी बैंक ने ज़िम्बाब्वे में एक निर्यात ऋण गारंटी कंपनी (ई सी जी सी) की स्थापना करने में रिज़र्व बैंक ऑफ ज़िम्बाब्वे को परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं ।

भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात विपणन सेवा

बैंक ने कई भारतीय कंपनियों को विदेशों में अपने उत्पादों को प्रतिष्ठित करने और नये बाज़ारों में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की है । कंपनियों को भावी व्यावसायिक साझेदार की पहचान से लेकर अंतिम आर्डर देने के कार्य को सुगम बनाने तक मार्गदर्शन दिया गया । जिन बाज़ारों में ऐसी सेवाएं प्रदान की गयीं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

हंगरी : बैंक ने मध्यम आकार की एक भारतीय फर्म की ओर से प्राकृतिक पत्थर के उत्पादों के लिए एक प्रतिष्ठित हंगेरीयन कंपनी से आर्डर प्राप्त किये हैं। इस कारोबार के दीर्घकालिक आधार पर काम बढ़ने की संभावना है । उसी उत्पाद शृंखला के लिए एक अन्य सुप्रसिद्ध हंगेरीयन कंपनी के साथ बातचीत प्रगति पर है ।

दक्षिण अफ्रीका : बैंक ने दक्षिण अफ्रीका में एक प्रतिष्ठित वस्त्र विनिर्माता के साथ अपने कार्य को मज़बूत बनाया। निर्माता ने मध्यम आकार की भारतीय कंपनी को सूती वस्त्र के लिए अब तक कई आर्डर दिये हैं और इस प्रकार इसे एक नियमित स्रोत आधार बनाया है । विस्तार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में दक्षिण अफ्रीकी कंपनी ने अब भारत से प्रीमियम क्वालिटी की रेडीमेड शर्टों के आयात में बैंक की सहायता मांगी है । बैंक एक अग्रणी दक्षिण अफ्रीकी समुद्रीय आहार रेस्टारंट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करता रहा है जो एक मध्यम आकार के भारतीय समुद्रीय आहार निर्यातक से आपूर्तियों द्वारा पूरी की जा रही है ।

दो दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों की क्रमश: इलेक्ट्रिकल एप्लायनसेंज तथा बिस्कुटों की ज़रूरतों को प्रतिष्ठित भारतीय विनिर्माताओं से पूरा करने के लिए बैंक के माध्यम से बातचीत प्रगति पर है ।

ब्राज़ील : लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को उपलब्ध अवसरों पर ज़ोर देते हुए बैंक ने एक ऑटो मोबाइल (दुपहिया) निर्माता को सीधे ब्राज़ीलियाई बाज़ार में अपने उत्पादों के लाँच करने में कंपनी की सहायता करने के लिए एक विधिक अभिमत अध्ययन करने में सहायता प्रदान की है ।

संस्थागत संबंद्ध

बैंक ने व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्थकारी वातावरण सृजित करने में सहायता के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों, निर्यात ऋण एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं, व्यापार संवर्धन निकायों तथा निवेश संवर्धन बोर्डों के साथ गठबंधन तथा संस्थागत संबंधों का एक नेटवर्क विकसित किया है ।

बैंक ने बोस्निया की निवेश गारंटी एजेंसी (आइ जी ए) तथा बहरीन साम्राज्य के आर्थिक विकास बोर्ड (ई डी बी) के साथ एक सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं । यह सहयोग-ज्ञापन पूरक शक्तियों को सुदृढ़ बनाने और भारतीय फर्मों द्वारा बाह्य निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास करता है ।

बैंक ने स्लोवॉक गणराज्य के निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िमबंका एस आर) तथा बी एन पी परिबास, निर्यात वित्त के लिए समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय बैंक, के साथ भी सहयोग-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं । सहयोग-ज्ञापन कई क्षेत्रों में दोनों संगठनों के बीच सहयोग तथा कारोबारी संबंध को बढ़ावा देने का प्रयास करता है । इनमें अन्य देश में परियोजना के एक हिस्से के रूप में भारत से निर्यात किये जाने वाले माल तथा सेवाओं के लिए सह-वित्तपोषण सहायता प्रदान करना तथा / या उसके लिए वित्त व्यवस्था करना शामिल है ।

अंकटाड के तत्वावधान में एक्ज़िम बैंकों तथा विकास वित्त संस्थाओं का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने में सहायता करने के लिए बैंक ने अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक, एंडियन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन तथा एक्ज़िम बैंक ऑफ मलेशिया के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। इस नेटवर्क के व्यापक उद्देश्यों में सहयोग को बढ़ावा देना, देश तथा क्षेत्र विशिष्ट अनुभव का आदान प्रदान, सूचना प्रवाह

को सुगम बनाना, तकनीकी सहायता प्राप्त करना और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण शामिल हैं ।

लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों को उनके भूमंडलीकरण प्रयासों में सहायता देने के लिए बैंक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र के उद्यम प्रबंध विकास सेवा (ई डी एम एस) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए बैंक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आइ टी सी), जिनेवा के बीच एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए ।

आइ टी सी के साथ सहयोग व्यवस्था के हिस्से के रूप में एक्ज़िम के अधिकारी को लघु एवं मध्यम आकार उद्यमों को सहायता करने के लिए विशेष विपणन कौशल हासिल करने के लिए जिनेवा में आइ टी सी के मुख्यालय में 'एक्सपर्ट इन रेजिडेन्स' के रूप में तैनात किया गया है । ये दोनों आइ टी सी द्वारा किसी भी देश में पहली बार शुरू की गई हैं ।

एडफिएप डिवेलपमेंट अवार्ड

एशिया तथा प्रशांत में विकास वित्तपोषण संस्थाओं का संघ (एडफिएप) डिवेलपमेंट अवार्ड ऐसी सदस्य संस्थाओं को सम्मानित करता है, जिन्होंने ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है जिनसे उनके संबंधित देशों में एक विकासात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है । ये अवार्ड उन सदस्य संस्थाओं को दिये जाते हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय तथा नवोन्मेषी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित या प्रवर्धित किया है ।

बैंक को 'ट्रेड डिवेलपमेंट अवार्ड 2005' से सम्मानित किया गया है । यह अवार्ड बैंक के निर्यात विपणन सेवा कार्यक्रम की स्वीकृति में है जो बैंक के गहन संस्थागत तथा व्यापार संबंधों तथा बैंक के समुद्रपारीय कार्यालयों की सेवाओं का प्रभावकारी ढंग से उपयोग करते हुए चुनिंदा भारतीय कंपनियों के विपणन संस्था के रूप में कार्य करने की दिशा में इसकी पहुँच तथा विश्वसनीयता पर नये भौगोलिक क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय फर्मों के लिए एक समर्थकारी वातावरण सक्रिय रूप से सृजित करता है । बैंक को वर्ष 2002 तथा 2004 में भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था ।

इस वर्ष एडफिएप अवार्ड बोर्ड ने एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को बैंक को विश्व के साथ भारत के व्यापार में योगदान देने वाले एक गतिशील तथा नवोन्मेषी संगठन में रूपांतरित करने में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका के लिए उन्हें एक विशेष 'प्लेक ऑफ मेरिट' से भी सम्मानित किया है ।

बैंक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निर्यात ऋण एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देता है । एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की 10 वीं वार्षिक बैठक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना की मेज़बानी में मई 2004 में बीजिंग में आयोजित की गई । फोरम ने एशिया के लिए एक क्षेत्रीय निर्यात ऋण एजेंसी की स्थापना की आवश्यकता पर और भारी मूल्य की सीमा-पार संविदा परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की । चीन, जापान, भारत, कोरिया, फिलिपीन्स, थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा आस्ट्रेलिया के एक्जिम बैंकों के मुख्य कार्यपालकों तथा एशियाई विकास बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बैठक में भाग लिया । भारतीय एक्ज़िम बैंक द्वारा इस पहल की शुरुआत एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के लिए 1996 में की गई थी ।

निर्यात ऋण एजेंसियों का फोरम

एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की दसवीं वार्षिक बैठक मई 2004 में बीजिंग, चीन में आयोजित की गयी । फोरम ने अधिक जागरुकता के माध्यम से सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया । फोरम ने क्षेत्र में कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं को उनकी चलनिधि बढ़ाने और ऋण संवृद्धि सुगम बनाने के लिए एशिया के लिए एक क्षेत्रीय निर्यात ऋण एजेंसी की स्थापना पर चर्चा की। यह सुझाव दिया गया कि एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों को बड़े पैमाने की सीमापार संविदा परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण करने, संयुक्त अनुसंधान की संभावनाओं का पता लगाने, सूचना के नियमित आदान-प्रदान करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने पारस्परिक दौरे बढ़ाने और जोखिम बचाव व्यवस्था, कार्मिक प्रबंधन, व्यवसाय उन्नयन तथा प्रशासन सुधार के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के क्षेत्र में सहयोग देना चाहिए । इस वार्षिक बैठक में भारत, आस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया,जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, फिलिपीन्स तथा थाइलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसके अलावा एशियाई विकास बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे ।

एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की ग्यारहवीं वार्षिक बैठक अक्तूबर 2005 में गोवा में आयोजित की जायेगी जिसकी मेज़बानी भारतीय एक्ज़िम बैंक करेगा । इस वार्षिक बैठक की परंपरा के रूप में बैंक ने जनवरी 2005 में नई दिल्ली में तकनीकी कार्यदल की एक बैठक आयोजित की । बैठक में चर्चा किये गये मुद्दे आगामी वार्षिक बैठक में विचार-विमर्श के लिए आधार होंगे ।

एक सुव्यवस्थित तरीके से सूचना के विनियम तथा विचारों के आदान-प्रदान के लिए एशियाई निर्यात ऋण एजेंसियों की वार्षिक बैठक के आयोजन की पहल मूलत: भारतीय एक्ज़िम बैंक द्वारा की गई थी जिसने भारत में फरवरी 1996 में मुंबई में पहली दो बैठकों का आयोजन भी किया था । तभी से यह अब एक वार्षिक आयोजन बन गया है, जिसका आयोजन बारी-बारी से एक निर्यात ऋण एजेंसी द्वारा किया जाता है । पहली दो बैठकों के बाद पिछली वार्षिक बैठकें टोक्यो (1997), बीजिंग (1998),बाली (1999), बैंकाक (2000), सिओल (2001), कुआलालम्पूर (2002) तथा मनीला (2003) में आयोजित की गयी थीं।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया ने विशेषकर भारत कोरियाई व्यापार को सहायता देकर एशिया में अंतर क्षेत्रीय व्यापार को गति प्रदान करने के लिए अगस्त 2004 में नई दिल्ली में 10 मिलियन यू एस डॉलर के एक द्विपक्षीय साख पत्र पुष्टिकरण सुविधा करार पर हस्ताक्षर किये ।

कांगो में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय टेक्नोलॉजी तथा पूंजी आकर्षित करने के लिए कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के विदेश तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री माननीय श्री रेमंड रामाज़ानी बाया के नेतृत्व में मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा एक्ज़िम बैंक का दौरा ।

VI. संवर्धनात्मक कार्यक्रम

परामर्थी सहायता कार्यक्रम बैंक के पास अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आइ एफ सी), वांशिग्टन डी.सी. तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के लघु एवं मध्यम उद्यमों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय परामर्शदाताओं को प्रायोजित करने तथा उनके आंशिक वित्तपोषण की व्यवस्था है । ये सुविधाएं अफ्रीका, सी आइ एस, चीन तथा दक्षिण एशिया में लागू हैं ।

31 मार्च 2005 को बैंक ने कृषि प्रसंस्करण, स्टोन वाशिंग, चमड़े की वस्तुओं, वित्तीय लेखा, मोटर वाहन पुर्जे,

रत्न एवं आभूषण, औषधि, सॉफ्टवेयर, बिज़ली जैसे कई विशिष्ट क्षेत्रों को शामिल करते हुए 30 देशों में भारतीय परामर्शदाताओं द्वारा प्राप्त 79 परामर्शी नियत कार्यों में सहायता प्रदान की है । वर्ष के दौरान कृषि, बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में भारतीय परामर्शदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया गया ।

एक्ज़िमिअस ज्ञान केंद्र

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंगलोर, पुणे, तथा अहमदाबाद में स्थित बैंक के एक्ज़िमिअस ज्ञान केन्द्रों ने उन्नीस कार्यक्रम आयोजित किये । इनमें बहरीन तथा ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए दो देश विशिष्ट व्यवसाय अवसर सेमिनार शामिल थे । केन्द्रों ने नई दिल्ली, मुंबई तथा बैंगलोर में अफ्रीकी विकास बैंक निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये । एशियाई विकास बैंक तथा परामर्शी विकास केन्द्र, नई दिल्ली के सहयोग से नई दिल्ली, तथा मुंबई में देशी परामर्शी सेवाओं के विकास पर एक सेमिनार आयोजित किया गया । यूरोप में भारतीय फर्मों के लिए बाज़ार प्रवेश तथा बाज़ार पहुँच रणनीतियों पर एक कार्यशाला बैंगलोर में आयोजित की गई थी और यूरोपीय देशों में बाज़ार पहुँच तथा तकनीकी आवश्यकता पर अन्य कार्यशाला विकासशील देशों से आयात के संवर्धन हेतु केन्द्र (सी बी आइ), दी नीदरलैंड्स के साथ मुंबई में आयोजित की गयी ।

इसके अलावा केन्द्रों ने दस सेमिनार / कार्यशालाएं निम्नलिखित विषयों पर आयोजित की, अर्थात् अंतरराष्ट्रीय विपणन: बदलते परिप्रेक्ष्य; वैश्विक बाज़ारों में निरंतर सफलता प्राप्त करना - चुनौती भारत; सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए सिक्स सिगमा; सूचना प्रौद्योगिकी विपणन रणनीतियाँ एवं उभरते अवसर (हैदराबाद तथा बैंगलोर में); खाद्य सुरक्षा मानक एवं गुणवत्ता - खाद्य नियंत्रण प्रणालियों की भूमिका; विकसित देशों के बाज़ारों को इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एवं इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमाणन तथा मार्किंग आवश्यकता ; सॉफ्टवेयर प्रक्रमण सुधार - व्यवसाय उत्कृष्टता समर्थ कारक और निर्यात तथा प्रबंधन से संबंधित विधि पर उन्मुखता कार्यक्रम ।

ऐमटेक प्रीसीजन प्रॉडक्ट्स आइ एन सी, शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आटो पुर्जों के उत्पादन में लगी है, का अधिग्रहण यूकल फ्यूल सिस्टम्स लि., चेन्नै द्वारा किया गया । एक्ज़िम बैंक ने यूकल को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस इकाई के अधिग्रहण करने के लिए ऋण तथा ईक्विटी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की है ।

व्यवसाय उत्कृष्टता का पुरस्कार

एक्ज़िम बैंक ने भारतीय उद्योग महासंघ के सहयोग से किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टी क्यू एम) कार्यप्रणालियों के लिए व्यवसाय उत्कृष्टता का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करना प्रारंभ किया है । यह पुरस्कार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट अवार्ड के मॉडल पर आधारित है ।

पिछले दशक के दौरान सिर्फ चार कंपनियों अर्थात हेलेट पैकर्ड इंडिया लिमिटेड (1997), मारुति उद्योग लिमिटेड (1998), टाटा स्टील (2000) तथा इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2002) को यह अवार्ड मिला है । वर्ष 2004 में कई कंपनियों ने इस अवार्ड प्रक्रिया में भाग लिया । यद्यपि कोई विजेता नहीं रहा, सात कंपनियों की व्यवसाय उत्कृष्टता के प्रति उनकी यात्रा में महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के लिए जूरी द्वारा प्रशंसा की गई । इन कंपनियों में

अलेक्सज़ेंडरिया कार्बन ब्लैक कंपनी एस ए ई, मिस्र; बिड़ला सेल्यूलॉजिक, भरूच, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) भोपाल, भेल हरिद्वार, भेल तिरुचिरापल्ली, टाटा मोटर्स लिमिटेड (वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय इकाई) मुंबई तथा टाइटन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (घड़ी डिवीजन), होसुर शामिल हैं । जूरी ने 23 कंपनियों की पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के प्रति उनकी दृढ़ वचनबद्धता के लिए सराहना की है।

VII. सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक ने विभिन्न प्रोसेसों की पुन:इंजीनियरी करने और ऐसे परिवर्तनों में सहायता देने के लिए आइ टी सोल्यूशनों को कार्यान्वित करने में अपनी पहल को जारी रखा है । सूचना की बेहतर सहभागिता, यूज़र एमपॉवरमेंट तथा सिस्टम इंटेलिजेंस क्षमताओं में वृद्धि के लिए ज्ञान प्रबंधन, सहित विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाओं को उन्नत बनाया गया । भारतीय रिज़र्व बैंक, सी सी आइ एल, क्रेडिट इंफर्मेशन ब्यूरो (इंडिया लिमिटेड) और विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी के सिस्टमों से संबंधित ग्राहक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उन्नत बनाया गया ।

आयोजना एवं बजट; देश विश्लेषण; उद्योग विश्लेषण; जोखिम उपाय और विश्लेषण; बैंक व्यापी सिस्टम; व्यापार वित्त, राजकोष और आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विशेषीकृत पैकेजों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सिस्टम को सक्षम और समुन्नत किया गया है । इन क्षेत्रों के सिस्टम में रणनीतिक आयोजना, आंतरिक सेवा प्रदान करना, ग्राहक इंटरफेस और ऑनलाइन ट्रेकिंग शामिल हैं ।

बैंक के पोर्टल (www.eximbankindia.com) को विभिन्न अंशधारकों की असंख्य जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है और समृद्ध बनाया जाता है । अन्य बातों के साथ-साथ वेबसाइट बैंक में किये गये विभिन्न शोध कार्यकलापों, व्यावसायिक अवसरों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अग्रताओं पर सूचना का प्रचार-प्रसार करती है । इसके अलावा इसमें बैंक के विभिन्न उधार कार्यक्रमों तथा भारतीय निर्यातकों के लिए और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए सूचना तथा सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध होती है । इस पोर्टल का देशी तथा विदेशी ग्राहकों द्वारा लगातार उपयोग किया जा रहा है ।

एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन बायो टेक्नोलॉजी : इमर्जिंग अपॉर्च्युनिटी का औपचारिक रूप से विमोचन कर्नाटक के मुख्यमंत्री माननीय श्री धरम सिंह द्वारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय डॉ. ए. रामादास तथा राजस्थान की मुख्यमंत्री माननीया श्रीमती वसुंधरा राजे की उपस्थिति में बैंगलोर में आयोजित बायो 2005, इंटरनैशनल कांफ्रेस के अवसर पर किया गया । श्रीमती किरण मजूमदार शॉ, भारत में बायोटेक्नोलोजी की एक पॉयोनियर उद्यमी भी चित्र में दिखाई दे रही हैं ।

VIII. शोध एवं विश्लेषण

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास शोध वार्षिक पुरस्कार 1989 में बैंक द्वारा शुरू किया गया था । इसका उद्देश्य भारत तथा विदेशों में विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार तथा विकास और संबंद्ध वित्तपोषण में शोध को बढ़ावा देना है । इस पुरस्कार में एक लाख रुपये की राशि तथा प्रशस्तिपत्र प्रदान किया जाता है । डॉ. प्राची मिश्रा, अर्थशास्त्री, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वांशिग्टन डी.सी. यू एस ए को वर्ष 2004 के लिए यह पुरस्कार 'एसेज ऑन ग्लोबलाइजेशन एण्ड वेज़ेज इन डिवेलपिंग कंट्रीज़' पर उनके शोध प्रबंध के लिए प्रदान किया गया ।

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निम्नलिखित छह प्रासंगिक आलेख प्रकाशित किये गये : भारतीय उद्योग में उत्पादकता वृद्धि तथा व्यापार; भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अंतर उद्योग व्यापार; भारतीय बागान क्षेत्र की निर्यात संभाव्यता; संभावनाएं तथा

चुनौतियाँ; ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ तथा डेरी उत्पाद: अन्य एशियाई देशों को निर्यात में भारत की संभाव्यता; जैव प्रौद्योगिकी: भारत के लिए उभरते अवसर और एसियान देश: भारत की व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का एक अध्ययन ।

वर्ष के दौरान बैंक ने चार कार्यकारी आलेख भी प्रकाशित किये : सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन (साकु) : भारत की व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का एक अध्ययन; वस्त्र निर्यात : एम एफ ए पश्चात परिदृश्य - अवसर तथा चुनौतियाँ ; भारतीय सिरामिक उद्योग: परिप्रेक्ष्य तथा निर्यात संभाव्यता और मध्य एशियाई गणराज्य, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान : भारत की व्यापार तथा निवेश संभाव्यता।

बैंक ने वर्ष के दौरान '' बिज़नेस विथ लैटिन अमेरिका'' शीर्षक एक पुस्तक भी प्रकाशित की है ।

IX. मानव संसाधन प्रबंधन

31 मार्च 2005 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या 193 थी जिसमें ऐसे 139 व्यावसायिक कर्मचारी शामिल हैं जिनके अंतर्गत इंजीनियर, अर्थशास्त्री, बैंकर, सनदी लेखाकार, बिज़नेस स्कूल स्नातक, विधि और भाषा विशेषज्ञ, पुस्तकालय और प्रलेखन विशेषज्ञ, कार्मिक तथा कम्प्यूटर विशेषज्ञ आते हैं । इस व्यावसायिक दल की सहायता प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाती है । बैंक का यह उद्देश्य है कि वह अपने अधिकारियों के कौशलों का निरंतर उन्नयन करे । 2004-05 के दौरान 103 अधिकारियों ने बैंक के परिचालनों से संबंद्ध विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों में भाग लिया । इन कार्यक्रमों में औद्योगिक तथा परियोजना वित्त, अंतराष्ट्रीय व्यापार वित्त, विदेशी मुद्रा तथा वित्तीय व्युत्पन्न और जोखिम प्रबंधन, दस्तावेज़ी ऋण, कृषि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का वित्तपोषण, निर्यात विपणन, गैर-निष्पादित आस्ति प्रबंधन और वसूली रणनीतियां, ऋण-नीतियाँ, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन, कम्प्यूटर शिक्षण का उन्नयन, देश जोखिम विश्लेषण, बौद्धिक संपदा अधिकार बातचीत कौशल, संगठन में मानव कौशल का प्रबंध करना, गैर-वित्त अधिकारियों के लिए वित्त, संप्रेषण तथा नेतृत्व कौशल शामिल हैं।

X. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग की गति में तेज़ी लाने के बैंक के प्रयासों को विभिन्न प्राधिकरणों से मान्यता प्राप्त हुई है :

(i) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित राज्य स्तरीय बैंकर समिति (राजभाषा) पुणे ने वर्ष 2003-04 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से इस बैंक के क्षेत्र विशेष स्थित कार्यालयों के उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है।

(ii) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में गठित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुंबई ने वर्ष 2003-04 में समस्त वित्तीय संस्थाओं में से बैंक के क्षेत्र विशेष स्थित कार्यालयों के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है।

(iii) बैंक के कोलकाता कार्यालय को बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता की ओर से वर्ष 2003-04 के दौरान हिन्दी के कार्यान्वयन के सर्वोत्तम निष्पादन के लिए श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है ।

(iv) बैंक के नई दिल्ली कार्यालय को वर्ष 2003-04 में हिंदी में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन करने पर बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नई दिल्ली से प्रोत्साहन प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है ।

(v) राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्था, नई दिल्ली ने बैंक के प्रभारी राजभाषा अधिकारी को बैंक में हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष ट्रॉफी से सम्मानित किया है।

बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों को जारी रखा है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुपालन में परिपत्र प्रेस-विज्ञप्तियाँ और रिपोर्टें हिंदी में भी

जारी की गई हैं । ऋण करारों का हिंदी में अनुवाद किया गया है । हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं । बैंक के परिचालनों और क्रियाविधि संबंधी साहित्य के अतिरिक्त बैंक के स्थापना दिवस के वार्षिक व्याख्यान और प्रासंगिक आलेख हिंदी में प्रकाशित किये गये हैं ।

बैंक के अधिकारियों को हिंदी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से 24 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। बैंक के अधिकारियों को अपने दैनिक कार्य में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक में एक प्रोत्साहन योजना लागू है ।

सरकार के निदेशों के अनुसरण में, 01 सितम्बर, 2004 से हिंदी पखवाड़ा मनाया गया है । इस आयोजन के एक हिस्से के रूप में एक्ज़िमिअस का हिंदी विशेषांक प्रकाशित किया गया था ।

बैंक के त्रैमासिक प्रकाशन 'एक्ज़िमिअस : एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के सभी अंकों का हिंदी रूपांतर 'एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया । बैंक के द्विमासिक प्रकाशन 'एग्री एक्सपोर्ट एडवांटेज़' के सभी अंकों को भी हिंदी में 'कृषि निर्यात लाभ' शीर्षक के अधीन प्रकाशित किया गया ।

हिंदी के प्रगामी प्रयोग विषयक सरकार की नीति के अनुसरण में और वर्ष 2004-05 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक के पुस्तकालय को विदेश व्यापार, वाणिज्य, वित्त, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य विषयों के साथ-साथ शास्त्रीय विषयों तथा समसामयिक साहित्य से समृद्ध बनाया गया है । बैंक में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति किये जाने की प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें तिमाही आधार पर नियमित रूप से आयोजित की गई हैं।

XI. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च 2005 को बैंक की सेवा में कुल 193 कर्मचारियों में 25 अनुसूचित जाति, 18 अनुसूचित जनजाति और 20 अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी सदस्य हैं। बैंक ने इन स्टाफ़ सदस्यों को कम्प्यूटरों और अन्य क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया है । बैंक ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली और भारतीदासन प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना जारी रखा है ।

नादी, फिजी में आयोजित 28 वीं एडफिएप वार्षिक बैठक के दौरान फिजी के वित्त एवं राष्ट्रीय योजना मंत्री माननीय श्री जोन वाइ कुबुआबोला तथा राजदूत जेसस पी ताम्बुलिंग अध्यक्ष, एडफिएप निदेशक मंडल की उपस्थिति में फिजी के प्रधानमंत्री माननीय श्री लाइसेनिया क्वारासे द्वारा एक्ज़िम बैंक को एडफिएप व्यापार विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

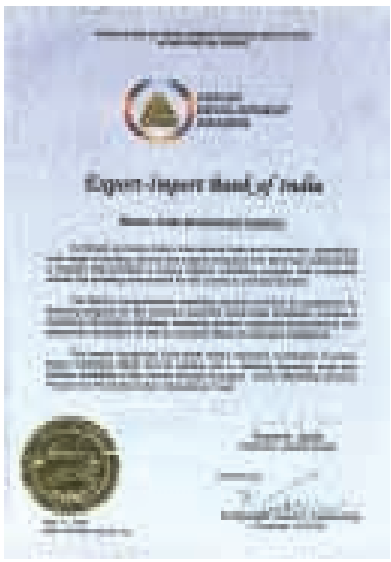

तुलन-पत्र
यथा 31 मार्च, 2005 को
एवं
2004-05 का
लाभ और हानि लेखा

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार को 654.4 मिलियन रुपये का लाभांश अदा किया। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम जी एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन जी से चेक प्राप्त करते हुए।

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2005 को

देयताएँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2004 को) रुपये
1.	पूँजी	I	8,499,918,881	6,499,918,881
2.	आरक्षित निधियाँ	II	16,624,988,097	14,933,014,180
3.	लाभ और हानि लेखा	III	654,400,000	470,000,000
4.	अपरक्राम्य वचन-पत्र, बाँड एवं डिबेंचर		98,972,004,153	76,700,580,430
5.	देय बिल		–	–
6.	जमा राशियाँ	IV	22,023,080,295	20,922,102,710
7.	उधार राशियाँ	V	21,063,644,411	21,582,667,243
8.	चालू देयताएँ एवं प्रावधान		13,884,120,980	13,397,276,241
9.	अन्य देयताएँ		2,551,230,502	685,973,868
10.	संभावित ऋण हानियों के लिए आरक्षित निधि		–	–
	योग		184,273,387,319	155,191,533,553

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	23,726,918,700	15,768,884,000
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर	24,012,294,600	10,556,152,000
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	45,508,500	13,115,250
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	3,318,800,000	3,318,800,000
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	953,401,700	628,113,000
	योग	52,056,923,500	30,285,064,250

सामान्य निधि

आस्तियाँ

		अनुसूचियाँ	इस वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2004 को) रुपये
1.	नकदी एवं बैंक शेष	VI	27,427,937,999	25,765,892,040
2.	निवेश	VII	13,564,858,290	14,573,307,311
3.	ऋण एवं अग्रिम	VIII	131,603,949,052	106,377,895,564
4.	खरीदे गये, भुनाये गये, पुनः भुनाये गये बिल	IX	2,500,000,000	1,373,200,000
5.	अचल आस्तियाँ	X	587,874,596	630,063,739
6.	अन्य आस्तियाँ	XI	8,588,767,382	6,471,174,899
7.	लाभ और हानि लेखा		–	–
	योग		184,273,387,319	155,191,533,553

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

एस. एन. मेनन **ए. के. झा** **डॉ. अशोक लाहिरी**
अमिताभ वर्मा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. पुलिन बी. नायक**
डॉ. एस. चन्द्रा **डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक**

निदेशकगण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर एस एम एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

विजय एन. भट्ट
साझेदार (एफ-36647)

मुम्बई
दिनांक : 23 अप्रैल, 2005

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	7,384,423,624	6,207,029,718
2.	ऋण बीमा (गारंटी फीस सहित)	36,623,683	40,860,747
3.	स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ	94,643,601	68,370,966
4.	निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फ़ीस तथा व्यय	218,500	788,256
5.	लेखा परीक्षा की फ़ीस	455,000	455,000
6.	भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमियम	48,643,757	45,698,324
7.	डाक व्यय, तार और टेलेक्स	19,699,586	14,905,754
8.	विधि विषयक व्यय	37,845,253	24,533,942
9.	अन्य व्यय	223,089,706	190,065,297
10.	मूल्यह्रास	60,147,468	87,361,078
11.	संभावित ऋण हानियों के लिए आरक्षित राशि में अंतरित	–	–
12.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	3,143,518,968	3,042,328,037
	योग	11,049,309,146	9,722,397,119
	आय कर के लिए प्रावधान	564,427,396	750,000,000
	[225,572,604 रुपये आस्थगित कर जमा को घटाकर (गत वर्ष - कुछ नहीं रुपये)]		
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	2,579,091,572	2,292,328,037
		3,143,518,968	3,042,328,037

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1. हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के संलग्न 31 मार्च 2005 के तुलन पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की सामान्य निधि के लाभ-हानि लेखे (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारी ज़िम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।
2. हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों का आकलन साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।
3. हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :
   - क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं।
   - ख. हमारी राय में तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं।
   - ग. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च 2005 को बैंक की सामान्य निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते **आर एस एम एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

विजय एन. भट्ट
साझेदार (एफ-36647)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 अप्रैल, 2005

सामान्य निधि

आय

	इस वर्ष	गत वर्ष
	रुपये	रुपये
(वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किये गये प्रावधानों तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधानों को घटाकर)		
1. ब्याज और बट्टा	10,264,606,770	8,642,148,342
2. विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	547,979,724	462,904,068
3. अन्य आय	236,722,652	617,344,709
4. तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
योग	11,049,309,146	9,722,397,119
लाभ, नीचे लाया गया	3,143,518,968	3,042,328,037
पुनरांकित पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज-कर का प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	3,143,518,968	3,042,328,037

टिप्पणी : 1. आय में निवेश आय, बैंक जमा राशियों पर ब्याज आदि के कारण प्राप्त 3.79 बिलियन रुपये (गत वर्ष 3.26 बिलियन रुपये) शामिल हैं।

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

एस. एन. मेनन **ए. के. झा** **डॉ. अशोक लाहिरी**
अमिताभ वर्मा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. पुलिन बी. नायक**
डॉ. एस. चन्द्रा **डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक**

निदेशकगण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर एस एम एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

विजय एन. भट्ट
साझेदार (एफ-36647)

मुम्बई
दिनांक : 23 अप्रैल, 2005

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

यथा 31 मार्च, 2005 को

		इस वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2004 को) रुपये
अनुसूची I :	**पूँजी :**		
	1. प्राधिकृत	10,000,000,000	10,000,000,000
	2. निर्गमित एवं प्रदत्त :		
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	8,499,918,881	6,499,918,881
अनुसूची II :	**आरक्षित :**		
	1. आरक्षित निधि	12,280,493,288	11,091,323,616
	2. सामान्य आरक्षित राशियाँ	–	–
	3. अन्य आरक्षित राशियाँ :		
	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि	564,175,745	561,371,500
	ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएँ)	720,319,064	620,319,064
	4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	3,060,000,000	2,660,000,000
		16,624,988,097	14,933,014,180
अनुसूची III :	**लाभ और हानि लेखा :**		
	1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखा के अनुसार शेष	2,579,091,572	2,292,328,037
	2. घटाकर : विनियोजन :		
	- आरक्षित निधि को अंतरित	1,189,169,672	902,109,287
	- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित	150,000,000	310,000,000
	- ऋण शोधन निधि को अंतरित	100,000,000	150,000,000
	- आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	400,000,000	400,000,000
	- लाभांश के जरिये वितरित लाभ पर कर के प्रावधान	85,521,900	60,218,750
	3. निवल लाभ का शेष (भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरणीय)	654,400,000	470,000,000
अनुसूची IV :	**जमा राशियाँ :**		
	(क) भारत में	22,023,080,295	20,922,102,710
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		22,023,080,295	20,922,102,710
अनुसूची V :	**उधार राशियाँ :**		
	1. भारतीय रिज़र्व बैंक से :		
	(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर	–	–
	(ख) विनिमय बिलों पर	–	–
	2. भारत सरकार से	80,000,003	93,333,336
	3. अन्य स्रोतों से		
	(क) भारत में	7,687,450,000	2,874,350,000
	(ख) भारत के बाहर	13,296,194,408	18,614,983,907
		21,063,644,411	21,582,667,243
अनुसूची VI :	**नकदी एवं बैंक में शेष :**		
	1. हाथ में नकदी	71,239	91,536
	2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	7,030,117	221,816
	3. अन्य बैंकों में शेष :		
	(क) भारत में	21,840,233,387	23,805,277,660
	(ख) भारत के बाहर	5,480,603,256	1,860,301,028
	4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धनराशि	100,000,000	100,000,000
		27,427,937,999	25,765,892,040

टिप्पणी : अन्य बैंकों में शेष में, बैंकों के पास सावधि जमा राशियाँ शामिल हैं।

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2005 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2004को)
अनुसूची VII :	**निवेश :**	**रुपये**	**रुपये**
	1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ	3,143,667,828	3,219,530,328
	2. ईक्विटी शेयर और स्टॉक	1,112,196,462	1,042,969,983
	3. अधिमान शेयर एवं स्टॉक	418,137,000	130,257,000
	4. अपरक्राम्य वचन-पत्र, डिबेंचर एवं बाँड	4,715,232,000	3,518,050,000
	5. अन्य	4,175,625,000	6,662,500,000
		13,564,858,290	14,573,307,311
अनुसूची VIII:	**ऋण एवं अग्रिम :**		
	1. विदेशी सरकारें	2,576,856,848	180,331,539
	2. बैंक :		
	(क) भारत में	22,643,831,318	19,576,946,720
	(ख) भारत के बाहर	1,498,530,663	1,403,947,063
	3. वित्तीय संस्थाएं :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	1,050,544,253	1,242,233,946
	4. अन्य	103,834,185,970	83,974,436,296
		131,603,949,052	106,377,895,564
अनुसूची IX :	**खरीदे गये, भुनाये गये तथा पुनः भुनाये गये बिल :**		
	(क) भारत में	2,500,000,000	1,373,200,000
	(ख) भारत के बाहर	–	–
		2,500,000,000	1,373,200,000
अनुसूची X :	**अचल आस्तियाँ :** (लागत पर मूल्यह्रास घटाकर)		
	1. परिसर	552,124,782	576,624,273
	2. अन्य	35,749,814	53,439,466
		587,874,596	630,063,739
अनुसूची XI :	**अन्य आस्तियाँ :**		
	1. निवेशों तथा ऋणों पर उपचित ब्याज़	2,359,715,359	1,403,885,507
	2. पूर्व प्रदत्त बीमा किस्त-भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. को प्रदत्त	673,339	3,714,666
	3. विविध पक्षों के पास जमाराशियां	21,346,779	21,554,010
	4. अन्य [225,572,604 रुपये (गत वर्ष-कुछ नहीं रुपये) के आस्थगित कर आस्ति सहित]	6,207,031,905	5,042,020,716
		8,588,767,382	6,471,174,899

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2005 को

देयताएँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2004 को) रुपये
1.	ऋण :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
2.	अनुदान :		
	(क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
3.	उपहार, दान, उपकृतियाँ :		
	(क) सरकार से	–	–
	(ख) अन्य स्रोतों से	–	–
4.	अन्य देयताएँ	47,006,318	40,756,318
5.	लाभ और हानि लेखा	170,999,818	160,173,785
	योग	346,313,923	329,237,890

आकस्मिक देयताएँ

(i)	स्वीकृतियाँ, गारंटियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	–	–
(ii)	वायदा विनिमय संविदाओं, ब्याज दरों की अदला-बदली की बकाया राशियों पर	–	–
(iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं पर	–	–
(iv)	अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएँ	–	–
(v)	बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	–	–
(vi)	संग्रहण के लिए बिल	–	–
(vii)	सहभागिता प्रमाणपत्रों पर	–	–
(viii)	भुनाये गये / पुनः भुनाये गये बिल	–	–
(ix)	अन्य राशियाँ जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से ज़िम्मेदार है	–	–

टिप्पणी : भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जो अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करती है कि निर्यात संवर्धन निधि की कोई भी आय, लाभ अथवा उसमें प्रोद्भूत होनेवाले अभिलाभ अथवा इस निधि में जमा किये जाने के लिए प्राप्त राशि पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा), का वित्त (संख्या 2) अधिनियम 1998 द्वारा 1 अप्रैल 1999 से लोप किया गया है। एक्ज़िम बैंक को यह सूचित किया गया है कि, उक्त धारा चूँकि 31 मार्च 1999 तक प्रभावी थी अतः यह छूट, लेखा वर्ष 1998-99 की समाप्ति तक निधि को प्रोद्भूत अथवा उद्भूत आय के संबंध में उपलब्ध रहेगी। आयकर प्राधिकारियों ने कर निर्धारण आदेश भी पास किया था और एक्ज़िम बैंक ने इस मामले में अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के लिए 66.18 लाख रुपये के कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के लिए अनुवर्तन कर रहा है।

Sp50K50

निर्यात संवर्धन निधि

आस्तियाँ

		इस वर्ष (यथा 31.03.2005 को) रुपये	गत वर्ष (यथा 31.03.2004 को) रुपये
1.	बैंक शेष	297,128,866	287,091,332
2.	निवेश	–	–
3.	ऋण एवं अग्रिम :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	8,505,318	8,505,318
4.	खरीदे गये / भुनाये गये बिल :		
	(क) भारत में	–	–
	(ख) भारत के बाहर	–	–
5.	अन्य आस्तियाँ	40,679,739	33,641,240
6.	लाभ और हानि लेखा	–	–
	योग	346,313,923	329,237,890

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

एस. एन. मेनन **ए. के. झा** **डॉ. अशोक लाहिरी**
अमिताभ वर्मा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. पुलिन बी. नायक**
डॉ. एस. चन्द्रा **डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक**

निदेशकगण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर एस एम एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

विजय एन. भट्ट
साझेदार (एफ-36647)

मुम्बई
दिनांक : 23 अप्रैल, 2005

लाभ और हानि लेखा

यथा 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
1.	ब्याज	–	–
2.	अन्य व्यय	–	–
3.	तुलन-पत्र को ले जाया गया लाभ	17,076,033	20,948,905
	योग	17,076,033	20,948,905
	आय कर के लिए प्रावधान	6,250,000	6,265,000
	तुलन-पत्र में अंतरित शेष लाभ	10,826,033	14,683,905
	योग	17,076,033	20,948,905

लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में, भारत के राष्ट्रपति

1. हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की निर्यात संवर्धन निधि के संलग्न 31 मार्च 2005 के तुलन-पत्र और साथ ही उक्त तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक की निर्यात संवर्धन निधि के लाभ-हानि लेखे (एक साथ 'वित्तीय विवरण पत्र' के रूप में निर्दिष्ट) की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है।
2. हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की है, इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार नियोजित और निष्पादित करें कि तर्कपूर्ण रूप से यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार की कोई महत्त्वपूर्ण जानकारी भ्रामक नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटीकरण को प्रमाणित करनेवाले साक्ष्यों की परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण अनुमानों का आकलन साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा की गयी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।
3. हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि :
   - क. लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं।
   - ख. हमारी राय में तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 तथा उसके अधीन विरचित विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये हैं।
   - ग. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर टिप्पणियों के साथ पठित, आवश्यक सभी विवरणों से युक्त एक पूर्ण तथा सही तुलन-पत्र है और इसे इस तरह से उचित रूप में तैयार किया गया है कि यह यथा 31 मार्च 2005 को बैंक के निर्यात संवर्धन निधि के कार्यों की स्थिति की, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची व सही स्थिति प्रदर्शित करे।

कृते **आर एस एम एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

विजय एन. भट्ट
साझेदार (एफ-36647)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 23 अप्रैल, 2005

Sp52K52

निर्यात संवर्धन निधि

आय

		इस वर्ष	गत वर्ष
		रुपये	रुपये
(वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किये गये प्रावधानों तथा अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधानों को घटाकर)			
1.	ब्याज और बट्टा	17,076,033	20,948,905
2.	विनिमय, कमीशन, दलाली और फीस	–	–
3.	अन्य आय	–	–
4.	तुलन-पत्र को ले जायी गयी हानि	–	–
	योग	17,076,033	20,948,905
	लाभ , नीचे लाया गया	17,076,033	20,948,905
	पुनरांकित पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय / ब्याज कर का प्रावधान का प्रतिलेखन	–	–
	योग	17,076,033	20,948,905

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

एस. एन. मेनन **ए. के. झा** **डॉ. अशोक लाहिरी**
अमिताभ वर्मा **डॉ. विनयशील गौतम** **डॉ. पुलिन बी. नायक**
डॉ. एस. चन्द्रा **डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक**

निदेशकगण

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर एस एम एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

मुम्बई
दिनांक : 23 अप्रैल, 2005

विजय एन. भट्ट
साझेदार (एफ-36647)

लेखों की टिप्पणियाँ - सामान्य निधि

1. एजेंसी लेखा

चूँकि एक्ज़िम बैंक भारतीय संविदाकारों से संबंधित कतिपय सौदों को इराक में सुगम बनाने के लिए केवल एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है अतएव भारत सरकार को समनुदेशित 27.11 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 27.15 बिलियन रुपये) की राशि सहित बैंक को सूचित की गई एजेंसी खाते में धारित 30.00 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 30.05 बिलियन रुपये) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियाँ उपर्युक्त तुलन-पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. आय-कर

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 37 (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित था कि एक्ज़िम बैंक द्वारा व्युत्पन्न किसी भी लाभ अथवा अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी राशि पर कर नहीं लगाया जाएगा), 1 अप्रैल, 1999 से वित्त (सं.2) अधिनियम, 1998 द्वारा निकाल दी गई है। एक्ज़िम बैंक को सूचित किया गया था कि चूँकि उक्त धारा 31 मार्च, 1999 तक लागू थी, अतएव लेखा वर्ष 1998-99 के अंत तक उपचित होनेवाली अथवा उत्पन्न होनेवाली आय के लिए छूट उपलब्ध होगी। तथापि एक्ज़िम बैंक ने कराधान के लिए प्रावधान किया था तथा आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि का निर्माण कर लिया था तथा उसने इस मामले में अपने अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त वर्ष के 0.79 बिलियन रुपये कर तथा 0.06 बिलियन रुपये ब्याज-कर की अदायगी भी कर दी थी। बैंक कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए अदा किये गये कर की वापसी के मामले का अनुवर्तन कर रहा है। बैंक ने निर्धारण वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग के प्रति आंशिक भुगतान भी किया है और अदा किये गये कर की वापसी के लिए कार्रवाई की जा रही है। निर्धारण वर्ष 1999-00 तथा 2000-01 के लिए भी ब्याज-कर की मांग अपील में है। कानूनी सलाहकार की सलाह के अनुसार कराधान के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है।

3. (क) आकस्मिक देयताएँ

गारंटियों में 6.62 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 5.17 बिलियन रुपये) की समाप्त हो गई गारंटियां शामिल हैं, उन्हें खातों में से निरस्त किया जाना है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत ''बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया'' के रूप में दिखाई गई 3.32 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष 3.32 बिलियन रुपये) की राशि बैंक के चूककर्ता द्वारा बैंक के विरुद्ध किये गये दावों/प्रति-दावों से संबंधित हैं जो बैंक द्वारा उनके विरुद्ध शुरू की गई विधिक कार्रवाई के कारण है। बैंक के सॉलिसिटरों की राय में कोई भी दावा/प्रति-दावा चलाने -योग्य नहीं है। कोई भी मामला अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है। व्यावसायिक सलाह के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।

(ग) वायदा विनियम संविदाएं, करेंसी / ब्याज दर अदला-बदली

यथा 31 मार्च 2005 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूरी तरह से बचाव व्यवस्था कर ली गई है। ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करारों को बचाव व्यवस्था लिखत के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इन लिखतों के धारणा विषयक सिद्धांत को तुलन पत्र में शामिल नहीं की गई मद के रूप में रिकार्ड किया गया है। ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करारों पर ब्याज, आय और व्यय उपचित आधार पर हिसाब में लिया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार - अतिरिक्त सूचना

4. पूंजी

(क)

	यथा 31 मार्च 2005 को	यथा 31 मार्च 2004 को
(i) जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सी आर ए आर)	21.58%	23.48%
(ii) जोखिम आस्तियों की तुलना में मूल पूंजी अनुपात	20.41%	22.19%
(iii) जोखिम आस्तियों की तुलना में अनुपूरक पूंजी अनुपात	1.17%	1.29%

(ख) 'अपरक्राम्य वचन-पत्र, बांड और डिबेंचर' में 8% 2022 बांड शामिल हैं जिसमें सरकार ने 5.59 बिलियन रुपये (पिछले वर्ष : 5.59 बिलियन रुपये) का अभिदान किया है। ये बांड अप्रतिभूत हैं और बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी उधार राशियों/जमाओं/गौण ऋणों के मुकाबले में गौण हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन ये बैंक की टीयर-I पूंजी के लिए पात्र हैं।

(ग) यथा 31 मार्च 2005 को टीयर - II पूँजी के रूप में जुटाये गये और बकाया गौण ऋण की राशि : कुछ नहीं रुपये (पिछले वर्ष : कुछ नहीं रुपये)

(घ) जोखिम भारित आस्तियाँ -

(ङ)

	यथा 31मार्च 2005 को	यथा 31 मार्च 2004 को
(i) तुलन-पत्र 'की' मदें	119.76	99.19
(ii) तुलन-पत्र में 'शामिल नहीं की गईं' मदें	17.41	11.99

(च) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप : भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त।

- *जोखिम आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात और अन्य मानदंडों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।*

5. यथा 31 मार्च 2005 को आस्ति-गुणवत्ता और ऋण-संकेन्द्रण

(क) निवल ऋणों और अग्रिमों की तुलना में गैर-निष्पादक आस्तियों की प्रतिशतता : 0.85 (गत वर्ष 1.26)

(ख) निर्धारित आस्ति वर्गीकरण श्रेणियों के अंतर्गत निवल गैर-निष्पादक-आस्तियों की राशि और प्रतिशतता :

(बिलियन रुपये)

	यथा 31 मार्च 2005 को		यथा 31 मार्च 2004 को	
	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता
अवमानक आस्तियाँ	0.47	0.37	0.76	0.74
संदिग्ध आस्तियाँ	0.62	0.48	0.53	0.52
हानि आस्तियाँ	–	–	–	–
योग	1.09	0.85	1.29	1.26

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित मदों के लिए किये गये प्रावधान :

(बिलियन रुपये)

	2004-05	2003-04
मानक आस्तियाँ	0.07	0.38
गैर-निष्पादक आस्तियाँ	0.83	0.43
निवेश (जो अग्रिम के स्वरूप को छोड़कर अन्य स्वरूप के हैं)	0.24	0.04
आय-कर	0.56	0.75

(घ) निवल गैर निष्पादक-आस्तियों में घट-बढ़ :

(बिलियन रुपये)

	2004-05	2003-04
वर्ष के आरंभ में निवल गैर-निष्पादक-आस्तियाँ	1.29	1.84
वर्ष के दौरान नई गैर-निष्पादक आस्तियाँ	0.47	0.20
वर्ष के दौरान वसूलियाँ/कोटि उन्नयन	0.67	0.75
वर्ष की समाप्ति पर निवल गैर-निष्पादक-आस्तियाँ	1.09	1.29

Sp55K55

(ङ) गैर-निष्पादक -आस्तियों (जिसमें ऋण, बांड और अग्रिम के रूप में डिबेंचर और अंतर - कंपनी जमा राशियाँ शामिल हैं) के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)

(बिलियन रुपये)

	2004-05	2003-04
वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	6.00	6.00
जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.83	0.43
घटाएं : अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते डालना/पुनरांकन	1.83	0.43
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	5.00	6.00

(च) प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई आस्तियां:

(i) लेखों की संख्या - 4

(ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी के बेचे गए लेखों का (प्रावधानों को घटाकर) कुल मूल्य - 0.91 बिलियन रुपये

(iii) कुल प्रतिफल - 1.05 बिलियन रुपये

(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में स्थानांतरित लेखों के विषय में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल - लागू नहीं होता

(v) निवल बुक मूल्य पर कुल लाभ/हानि - 0.14 बिलियन रुपये

- भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी सं. सी-2/01.02.00/2004-05 दिनांकित 2 अगस्त 2004 और उसके बाद में परिभाषित अनुसार ''पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई आस्तियां'' को हिसाब में लिया गया है।

(छ) गैर-निष्पादक निवेश

(बिलियन रुपये)

विवरण	2004-05	2003-04
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.14	0.10
वर्ष के दौरान जमा की गईं राशियां	0.14	0.04
वर्ष के दौरान घटाई गई राशियां	0.04	–
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.24	0.14
धारित कुल प्रावधान	0.13	0.10

(ज) निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान :

(बिलियन रुपये)

विवरण	2004-05	2003-04
वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक जमा शेष	0.18	0.14
जोड़ें :		
(i) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	0.12	0.04
(ii) वर्ष के दौरान निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे से विनियोग, यदि कोई है	0.15	–
घटाएं :		
(i) वर्ष के दौरान बट्टा खाता	–	–
(ii) निवेश घट-बढ़ आरक्षित लेखे में अंतरण, यदि कोई है	0.02	–
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष	0.43	0.18

(झ) यथा 31 मार्च, 2005 को पुनर्संरचित मानक आस्तियाँ : 0.53 बिलियन रुपये (गत वर्ष 1.41 बिलियन रुपये)।

(ञ) यथा 31 मार्च 2005 की पुनर्संरचित अवमानक आस्तियाँ : 0.12 बिलियन रुपये (गत वर्ष 0.16 बिलियन रुपये)।

(ट) यथा 31 मार्च, 2005 को पुनर्संरचित संदिग्ध आस्तियाँ : 0.04 बिलियन रुपये (गत वर्ष 0.09 बिलियन रुपये)।

(ठ) वर्ष के दौरान की गई कंपनी ऋण पुनर्संरचना : (बिलियन रुपये)

	2004-05	2003-04
(क) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित ऋण-आस्तियों की कुल राशि (क = ख + ग + घ)	1.44	2.81
(ख) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित मानक आस्तियों की राशि	1.39	2.43
(ग) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित अवमानक आस्तियों की राशि	—	—
(घ) कंपनी ऋण पुनर्संरचना के अधीन पुनर्संरचित संदिग्ध आस्तियों की राशि	0.05	0.38

(ड) ऋण सहायता :

	पूँजी निधियों* की तुलना में प्रतिशतता	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	17.64	1.95	2.50
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	20.74	2.30	2.94
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	109.19	12.10	15.47
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	137.65	15.26	19.50

* यथा 31 मार्च 2004 को पूँजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियां + उपयोग नहीं की गई मंजूरियां + बकाया गारंटियाँ।

गत वर्ष :

	पूँजी निधियों* की तुलना में प्रतिशतता	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता@	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	13.69	1.93	2.13
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	25.36	3.57	3.95
iii) 10 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	101.80	14.33	15.85
iv) 10 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	130.12	18.32	20.25

* यथा 31 मार्च 2003 को पूँजी निधियाँ

@ कुल ऋण सहायता : ऋण + अग्रिम राशियां + उपयोग नहीं की गई मंजूरियां + गारंटियाँ + व्युत्पन्नों के कारण ऋण सहायता।

1) बैंकों और समुद्रपारीय संस्थाओं को प्रदान किये गये ऐसे ऋण, जिनकी गारंटी सरकार ने दी है, उन पर एकल/समूह उधारकर्ता के रूप में विचार नहीं किया गया है।

2) यथा 31 मार्च 2005 को 2 उधारकर्ता थे जिनका पूँजी निधियों के 15% से अधिक निवेश था जिन्हें बोर्ड / प्रबंधन समिति के अनुमोदन के रूप में लिया गया था। यथा 31 मार्च 2005 को 2 उधारकर्ताओं को कुल निवेश, बैंक की पूंजी निधियों का क्रमशः 17.64% का 15.68% था।

(ढ) पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण सहायता :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र और परिधान	10.66	12.69
ii) इंजीनियरी सामान	9.31	11.08
iii) निर्माण	9.21	10.96
iv) धातु और धातु प्रसंस्करण	7.26	8.64
v) इलेक्ट्रॉनिक (दूरसंचार सहित)	7.11	8.47

गत वर्ष :

क्षेत्र	कुल ऋण सहायता की तुलना में प्रतिशतता	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
i) वस्त्र और परिधान	11.57	13.14
ii) निर्माण	8.58	9.75
iii) औषध और औषधियाँ	7.99	9.08
iv) इंजीनियरी माल	7.93	9.01
v) धातु और धातु प्रसंस्करण	7.50	8.51

- ''ऋण सहायता'' की गणना 28 जून 1997 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी ओ एस. एफ आइ डी. सं. 17/01.02.00/96-97 में और उसके बाद में परिभाषित अनुसार की गई है।

बैंकों को सहायता और समुद्रपारीय सत्ताओं को ऋण-व्यवस्थाएँ / क्रेता ऋण सहायता को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

(ण) गैर-सरकारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में निर्गमकर्ता वर्ग

(बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	निम्नलिखित की राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की	'निवेश कोटि से कम स्तर' की धारित प्रतिभूतियां की	दर-निर्धारित न की गई धारित 'प्रतिभूतियां' की	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3.48	3.43	—	3.48	*3.48
2	वित्तीय संस्थाएं	0.50	—	—	0.50	0.24
3	बैंक	0.13	—	—	0.08	0.08
4	निजी कंपनियाँ	1.95	0.06	—	1.95	**1.74
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	0.19	—	—	0.19	0.19
6	अन्य	4.18	—	—	4.18	0.18
7	# मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधान	0.21	—	—	—	—
	कुल	10.43	3.49	—	10.38	5.91

किए गए प्रावधान की केवल कुल राशि को कॉलम 3 में दिखाया गया है ।

* इसमें से 3.43 बिलियन रुपये, यू एस डॉलर / भारतीय रुपये की अदला-बदली के जरिए हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से किए गए थे ।

** इसमें से 1.05 बिलियन रुपये ए आर सी आइ एल द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद तथा 0.62 बिलियन रुपये ऋण के पुरर्संरचना के हिस्से के रूप में अर्जित शेयर / डिबेंचर में निवेश किए गए हैं ।

उक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं हैं।

पिछला वर्ष : (बिलियन रुपये)

क्रम संख्या	निर्गमकर्ता	राशि	निम्नलिखित की राशि			
			निजी नियोजन के माध्यम से किये गये निवेश की	'निवेश कोटि से कम स्तर' की धारित प्रतिभूतियां की	दर-निर्धारित न की गई धारित 'प्रतिभूतियां' की	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियां की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3.54	3.49	–	3.54	*3.54
2	वित्तीय संस्थाएं	0.49	–	–	0.49	0.24
3	बैंक	0.01	–	–	0.01	0.01
4	निजी कंपनियाँ	0.49	0.06	–	0.49	–
5	सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम	0.16	–	–	0.16	0.16
6	अन्य	6.66	–	–	6.66	0.21
7	# मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	0.17	–	–	–	–
	कुल	11.35	3.55	–	11.35	* 4.16

किए गए प्रावधान की केवल कुल राशि को कॉलम 3 में दिखाया गया है ।

* इसमें से 3.49 बिलियन रुपये यू एस डॉलर / भारतीय रुपये की अदला-बदली के जरिये भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से किए गए थे ।

उक्त कॉलम 4,5,6 और 7 में रिपोर्ट की गई राशियाँ परस्पर अनन्य (म्युचुअली एक्सक्लूसिव) नहीं है ।

6. चल निधि

(क) रुपया आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप; और

(ख) विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप ।

(बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	44.60	40.72	43.31	17.77	26.13	172.53
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	42.40	14.54	33.49	6.66	6.85	103.94
कुल आस्तियाँ	87.00	55.26	76.80	24.43	32.98	276.47
रुपया देयताएं	43.73	39.27	22.75	9.09	53.98	168.82
विदेशी मुद्रा देयताएं	37.70	6.82	34.69	8.28	15.43	102.92
कुल देयताएं	81.43	46.09	57.44	17.37	69.41	271.74

गत वर्ष :

(बिलियन रुपये)

मदें	1 वर्ष से कम या उसके समतुल्य	1 वर्ष से अधिक 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक 7 वर्षों तक	7 वर्षों से अधिक	योग
रुपया आस्तियाँ	41.99	32.65	38.12	16.68	23.34	152.78
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	29.24	13.82	13.10	5.66	4.45	66.27
कुल आस्तियाँ	71.23	46.47	51.22	22.34	27.79	219.05
रुपया देयताएं	39.66	22.11	25.57	11.60	52.88	151.82
विदेशी मुद्रा देयताएं	21.21	2.76	20.07	8.00	13.40	65.44
कुल देयताएं	60.87	24.87	45.64	19.60	66.28	217.26

- आस्तियों और देयताओं के परिपक्वता स्वरूप के लिए आस्तियों और देयताओं की विभिन्न मदों का समूहन आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली से संबंधित तारीख 31 दिसंबर 1999 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस.एफ आइ डी. सं.सी-11/01.02.00/1999-2000 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्दिष्ट समय-समूहों में किया गया है ।

(ग) रेपो लेन-देन :

(बिलियन रुपये)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च 2005 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
उलटे रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	—	2.92	0.21	—

7. भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जुलाई 1999 के दिशानिर्देश और उसके बाद के दिशानिर्देशों के अनुसार वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

1	बकाया सौदों की संख्या	61
2	कुल बकाया कल्पित मूलधन राशि	22.30 बिलियन रुपये
3	स्वैपों का स्वरूप	सौदे, बाज़ार बेंचमार्क जैसे भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ / लाइबोर/माइबोर पर आधारित ''नियत / अस्थिर'' या ''अस्थिर /नियत'' के स्वरूप में वचाव-व्यवस्था -प्रयोजन / देयता प्रबंधन के लिए किये गये हैं ।
4	अवधि	सौदे 2 से 15 वर्ष की अवधि के लिए हैं ।
5	प्रतिपक्ष के अपने दायित्वों को पूरा न कर पाने की स्थिति में वहन की जानेवाली हानि	0.03 बिलियन रुपये
6	अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य रुपये
7	स्वैप बही का उचित मूल्य	0.43 बिलियन रुपये (ऋणात्मक)
8	ऋण सहायता (वर्तमान सहायता पद्धति के अनुसार)	0.16 बिलियन रुपये
9	स्वैपों के उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	सभी सौदे सहायता सीमा के भीतर आते हैं ।

गत वर्ष :

1	बकाया सौदों की संख्या	24
2	कुल बकाया कल्पित मूलधन राशि	8.53 बिलियन रुपये
3	स्वैपों का स्वरूप	सभी सौदे, बाज़ार बेंचमार्क जैसे भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ / लाइबोर पर आधारित ''नियत / अस्थिर'' या ''अस्थिर / नियत'' स्वरूप में वचाव-व्यवस्था प्रयोजन / देयता प्रबंधन के लिए किये गये ।
4	अवधि	सौदे 3 से 15 वर्ष की अवधि के लिए हैं
5	प्रतिपक्ष के अपने दायित्वों के पूरा न कर पाने की स्थिति में वहन की जानेवाली हानि	0.04 बिलियन रुपये
6	अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य रुपये
7	स्वैप बही का उचित मूल्य	0.27 बिलियन रुपये
8	स्वैपों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	सभी सौदे सहायता सीमा के भीतर आते हैं

8. परिचालनगत परिणाम

(क) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय : 6.12 (गत वर्ष 6.41)

(ख) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशतता के रूप में ब्याजेत्तर आय : 0.46 (गत वर्ष 0.78)

(ग) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशतता के रूप में परिचालन लाभ : 1.95 (गत वर्ष 2.39)

(घ) औसत आस्तियों पर प्रतिफल : 1.51% (गत वर्ष 1.65%)

(ङ) प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ : 13.4 मिलियन रुपये (गत वर्ष 12.1 मिलियन रुपये)

- परिचालन परिणाम के लिए कार्यशील निधियों तथा कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत में, अनुवर्ती छमाही के अंत में तथा समीक्षाधीन वर्ष के अंत में, अनुवर्ती छमाही के अंत में तथा समीक्षाधीन लेखा वर्ष के अंत में आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है । (''कार्यशील निधियाँ'' कुल आस्तियों से संबंधित है),
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना करने के लिए सभी संवर्गों में सभी पूर्णकालिक कर्मचारियों को हिसाब में लिया गया है ।

9. नकदी प्रवाह विवरण

वार्षिक लेखे भारतीय -निर्यात आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) (अधिनियम) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा अनुमोदित भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में निर्धारित फार्मेट में तैयार किये गए हैं । चूकि नकदी प्रवाह विवरण फार्मेट में शामिल नहीं है, उसे इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइ सी ए आइ) द्वारा जारी लेखांकन मानक (ए एस) - 3 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में प्रकट नहीं किया गया है ।

10. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा समुद्रपारीय बैंकों / संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है ।

11. खंड रिपोर्टिंग

आइ सी ए आइ द्वारा जारी ए एस-17 खंड रिपोर्टिंग के अंतर्गत रिपोर्ट किये जाने योग्य खंड नहीं हैं क्योंकि बैंक के परिचालन में प्रमुखत: एक खंड अर्थात थोक वित्तीय कार्यकलाप शामिल हैं।

12. संबंधित पक्षकार प्रकटन

आइ सी ए आइ द्वारा जारी ए एस - 18, संबंधित पक्षकार प्रकटन के अनुसार बैंक के संबंधित पक्षकारों को नीचे प्रकट किया गया है :

- संबंध

  (I) संयुक्त उद्यम :

  - ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंट्स लि.
  - ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लि.

  (II) प्रमुख कार्यपालक कार्मिक :

  - श्री टी.सी.वेंकट सुब्रमणियन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

- बैंकों से संबंधित पक्षकार शेष राशियां तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है :

(मिलियन रुपये)

	संयुक्त उद्यम 2004-05	संयुक्त उद्यम 2003-04
मंजूर ऋण	804.97	-
निवेश	185.98	160.10
प्राप्त ब्याज	12.98	1.52
प्राप्त सेवाओं के प्रति भुगतान	0.17	1.03

वर्ष के अंत में बकाया राशि : 176.82 मिलियन रुपये (गत वर्ष शून्य रुपये)

वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि : 458.90 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 145.40 मिलियन रुपये)

- वाणिज्यिक बैंकों को जारी किये गये भारतीय रिज़र्व बैंक का 29 मार्च 2003 का परिपत्र डी बी ओ डी सं. बी पी.बीसी.89/ 21.04.018 / 2002-03 ऐसे लेन-देनों के प्रकटन को शामिल नहीं करता है जहां किसी भी श्रेणी में सिर्फ एक संबंधित पक्षकार (अर्थात प्रमुख प्रबंध कार्मिक) है।

13. आय पर कर का लेखांकन

बैंक ने चालू वर्ष से आइ सी ए आइ द्वारा जारी ए एस-22 के अंतर्गत आस्थगित कर के लिए लेखांकन शुरू कर दिया है । अधिनियम में अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत रिज़र्व में समायोजन नियत किया गया है । चूँकि कर आस्तियों / देयताओं के लिए समायोजन, जैसाकि लेखांकन मानकों के संक्रमणकालीन प्रावधानों में परिकल्पित है, अधिनियम में नियत रूप में आरक्षित राशियों के निर्माण के अनुरूप नहीं है, बैंक ने लाभ-हानि लेखे में वर्ष के अंत में आस्थगित कर समायोजन को माना है ।

यदि ए एस-22 के संक्रमण कालीन प्रावधानों का पालन किया गया होता तो 461.29 मिलियन रुपये की राशि यथा 1 अप्रैल 2004 को आरक्षित राशियों में जमा हुई होती और इसके समतुल्य राशि की आस्थगित कर आस्तियों का निर्माण हुआ होता तथा वर्ष के लिए आस्थगित कर व्यय 235.72 मिलियन रुपये होता । तथापि 31 मार्च 2005 को बैंक की सामान्य निधि के कार्यों की स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

आस्थगित कर आस्तियों का अलग - अलग विवरण	(रुपये मिलियन में) 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर आस्तियाँ :	
1) अनुमत न किया गया प्रावधान (निवल)	213.14
2) स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	28.50
3) अन्य	3.80
	245.44
घटायें : आस्थगित कर देयता	
बांड निर्गम खर्च का परिशोधन	19.87
	19.87
निवल आस्थगित कर आस्ति	225.57

14. संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं	देश	धारिता की प्रतिशतता	
			चालू वर्ष	गत वर्ष
क	ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कन्सल्टेंटस लि.	भारत	26%	26%
ख	ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	40%	35%

II. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हित से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय की कुल राशि निम्नलिखित हैं :

(मिलियन रुपये)

देयताएं	2004-05*	2003-04	आस्तियाँ	2004-05*	2003-04
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	219.07	169.51	अचल आस्तियाँ	45.19	38.55
ऋण	1606.60	1230.82	निवेश	52.45	532.95
अन्य देयताएं	557.70	335.84	अन्य आस्तियां	2285.73	1164.68
कुल	2383.37	1736.18	कुल	2283.37	1736.18

* आंकड़े अनंतिम हैं ।

(मिलियन रुपये)

व्यय	2004-05*	2003-04	आय	2004-05*	2003-04
ब्याज तथा वित्तपोषण व्यय	70.24	32.51	फैक्टरिंग कार्यकलाप से आय	127.76	52.21
अन्य व्यय	54.75	43.15	परामर्शी आय	3.94	3.90
प्रावधान	15.20	3.91	ब्याज आय तथा निवेश से आय	33.98	28.96
			अन्य आय	0.60	0.79
कुल	140.19	79.57	कुल	166.28	85.86

* आंकड़े अनंतिम हैं ।

15. जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित किया गया है । जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पहली बार प्रकटन किये गये हैं, वहाँ पिछले वर्ष के आंकडे नहीं दिये गये हैं ।

एस. श्रीधर
कार्यपालक निदेशक

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आर. एम. वी. रामन
कार्यपालक निदेशक

एस. एन. मेनन
अमिताभ वर्मा
डॉ. एस. चन्द्रा

ए. के. झा
डॉ. विनयशील गौतम

निदेशकगण

डॉ. अशोक लाहिरी
डॉ. पुलिन बी. नायक
डॉ. बुद्धाजीराव आर. मुलिक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **आर एस एम एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार

विजय एन. भट्ट
साझेदार (एफ-36647)

मुम्बई
दिनांक : 23 अप्रैल, 2005

महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

(i) **वित्तीय विवरण**

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारत में प्रचलित लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा ये सामान्यत: अंतरराष्ट्रीय लेखा मानकों के भी समनुरूप हैं। एक्ज़िम बैंक का तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 1982 में दिए गए रूप में तथा ढंग से तैयार किये गये हैं, जिसे भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का संख्यांक 28) की धारा 39(2) के अधीन भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र डी बी एस. एफ आइ डी सं. सी. 18/ 01.02.00/2000-01, दिनांकित 23 मार्च 2001 और उसके बाद में अपेक्षित अनुसार कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय अनुपात/आंकड़े ''लेखों की टिप्पणियाँ'' के खंड के रूप में दर्शायी गयी हैं।

(ii) **राजस्व निर्धारण**

(क) दंड स्वरूप ब्याज, वचनबद्धता प्रभार और ''भारग्रस्त आस्ति'' के रूप में पहचान किये गये ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज जिन्हें नकद आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय / व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। एक्ज़िम बैंक के बांडों पर दिया जानेवाला बट्टा / मोचन प्रीमियम को बांड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और उसे ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(ख) ब्याज और बट्टे का उल्लेख सकल ब्याज में गैर-निष्पादक आस्तियों पर ब्याज घटाकर किया गया है। गैर-निष्पादक आस्तियों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

(iii) **आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण**

तुलन-पत्र में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम राशियों में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. द्वारा निपटाये गये दावों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियाँ शामिल हैं। प्राप्त होनेवाले ब्याज को ''अन्य आस्तियों'' में समूहित किया गया है।

ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है : मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ। निधिक सुविधाओं के लिए किए गए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(iv) **निवेश**

संपूर्ण निवेश-संविभाग को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(क) ''परिपक्वता तक धारित'' (परिपक्वता तक धारित करने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियाँ),

(ख) ''क्रय-विक्रय के लिए धारित'' (प्रतिभूतियाँ इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य / ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए और)

(ग) ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' (शेष निवेश)।

निवेशों का निम्नलिखित रूप में और अधिक वर्गीकरण किया गया है :

(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
(iii) शेयर
(iv) डिबेंचर और बांड
(v) सहायक कंपनियों / संयुक्त उपक्रमों में निवेश
(vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्र, पारस्परिक निधियों की यूनिट आदि)

निवेशों की विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन और निवेशों का मूल्य निर्धारण, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को जारी किये गये 9 नवम्बर, 2000 के उसके परिपत्र के तथा उसके बाद में अपेक्षित अनुसार निर्धारित किये गये मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

Sp64K64

(v) **अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास**

(क) अचल आस्तियों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर मूल लागत पर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर स्वामित्व वाली इमारतों के लिए बीस वर्षों की अवधि में तथा अन्य आस्तियों के लिए चार वर्षों की अवधि में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के बारे में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

(घ) जहाँ किसी अवक्षयी आस्ति को निपटा दिया गया है, त्याग दिया गया है, गिरा दिया गया या नष्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित कर लिया गया है।

(vi) **विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन**

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दर पर नियत किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर नियत किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है, और इससे उत्पन्न होने वाले लाभ / हानियों को लाभ तथा हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर उल्लेखित किया गया है।

(vii) **गारंटियाँ**

(क) अवधि समाप्त गारंटियों को मूल दस्तावेज़ों की वापसी और निरसन तक आकस्मिक देयताओं के रूप में शामिल किया गया है।

(ख) ई सी जी सी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(viii) **कर्मचारियों के सेवांत लाभ हेतु प्रावधान**

बैंक ने पृथक रूप से भविष्य निधि, उपदान निधि और पेंशन निधि की स्थापना की है, जो आयकर आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। उपदान और पेंशन संबंधी देयताओं का अनुमान बीमांकिक आधार पर लगाया गया है और देय राशियाँ यदि कोई हैं, उनका अंतरण प्रत्येक वर्ष उपदान निधि और पेंशन निधि में कर दिया जाता है। छुट्टी के नकदीकरण के प्रति देयता के लिए वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

(ix) **आय पर करों का लेखांकन**

(क) संबंधित संविधि के अधीन अदायगी योग्य कर पर आधारित चालू कर के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय निर्धारण पर आस्थगित कर की गणना कर दरों पर तथा अधिनियम विधि अथवा तुलनपत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियाँ को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी गई है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

Sp65K65

संगठन संरचना

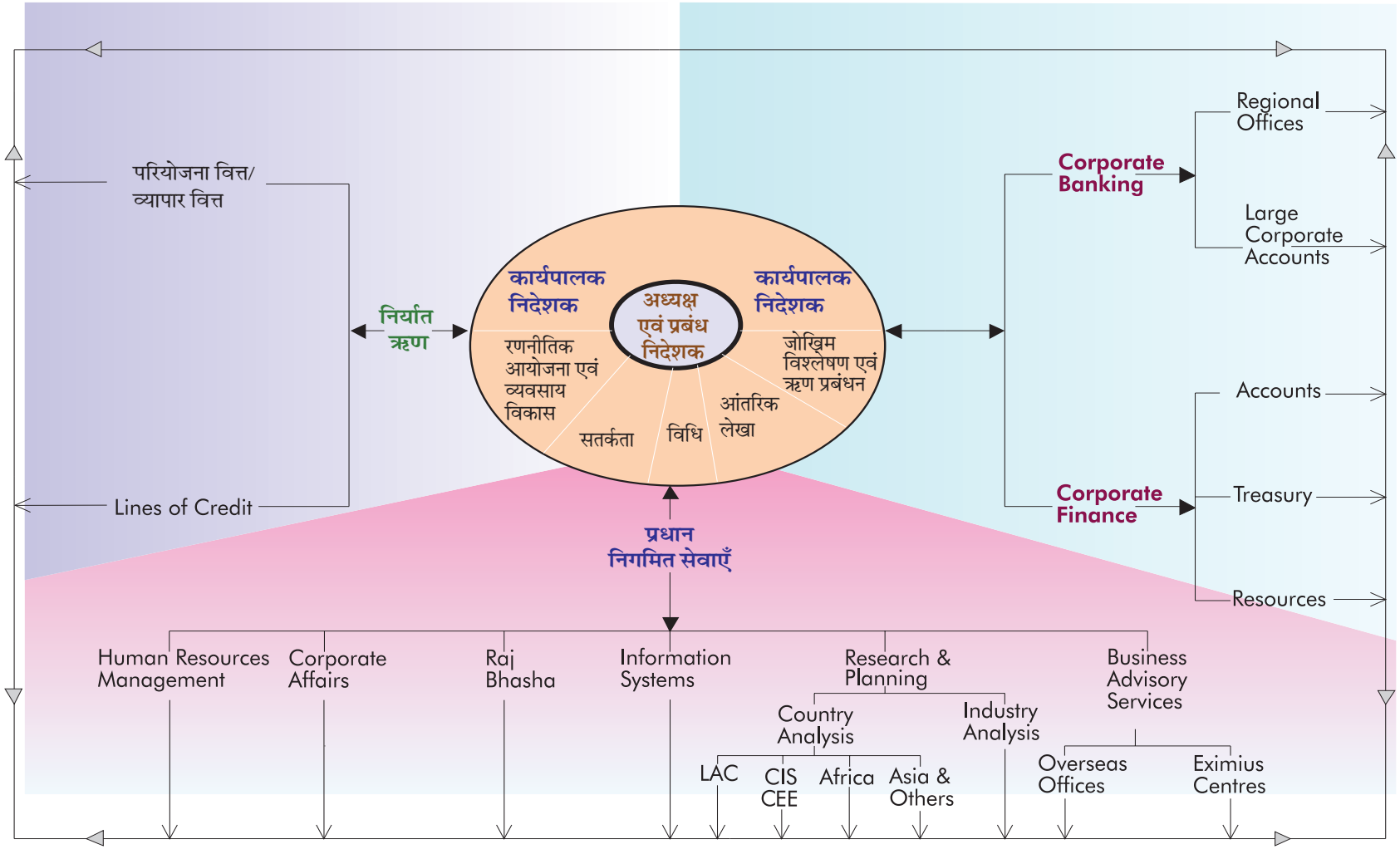
परियोजना वित्त/
व्यापार वित्त
Lines of Credit
निर्यात
ऋण
कार्यपालक
निदेशक
अध्यक्ष
एवं प्रबंध
निदेशक
कार्यपालक
निदेशक
रणनीतिक
आयोजना एवं
व्यवसाय
विकास
सतर्कता
विधि
आंतरिक
लेखा
जोखिम
विश्लेषण एवं
ऋण प्रबंधन
प्रधान
निगमित सेवाएँ
Corporate
Banking
Regional
Offices
Large
Corporate
Accounts
Corporate
Finance
Accounts
Treasury
Resources
Human Resources
Management
Corporate
Affairs
Raj
Bhasha
Information
Systems
Research &
Planning
Country
Analysis
LAC
CIS
CEE
Africa
Asia &
Others
Industry
Analysis
Business
Advisory
Services
Overseas
Offices
Eximius
Centres

एक्ज़िम बैंक का प्रमुख संसाधन : इसकी मानव पूँजी
Exim Bank's Key Resource: Its Human Capital

प्रबंधन दल

Management Team

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
T. C. Venkat Subramanian

कार्यपालक निदेशकगण
Executive Directors

एस. श्रीधर
S. Sridhar

आर. एम. वी. रामन
R. M. V. Raman

समूह प्रमुख
Group Heads

एस. आर. राव
निगमित सेवाएँ
S. R. Rao
Corporate Services

पी. ए. मकवाना
परियोजना वित्त/व्यापार वित्त
P. A. Makwana
Project Finance/Trade Finance

एस. भट्टाचार्य
कृषि व्यापार एवं ल. म. उ.
S. Bhattacharyya
Agri Business & SME

डी. जी. प्रसाद
निगमित बैंकिंग
D. G. Prasad
Corporate Banking

एन. शंकर
निगमित वित्त
N. Shankar
Corporate Finance

पी. आर. दलाल
ऋण-व्यवस्थाएँ
P. R. Dalal
Lines of Credit

सी. पी. रवींद्रनाथ
विधिक
C. P. Ravindranath
Legal

जॉन मैथ्यू
निगमित बैंकिंग
John Mathew
Corporate Banking

डेविड रस्किन्हा
मुख्य जोखिम अधिकारी
David Rasquinha
Chief Risk Officer

क्षेत्रीय प्रमुख

Regional Heads

भारत स्थित कार्यालय

Indian Offices

अहमदाबाद
देवानंद रजक
Ahmedabad
Devanand Rajak

बैंगलोर
मोती साईराम
Bangalore
Mothi Sayeeram

चेन्नै
के. मुत्थुकुमारन
Chennai
K. Muthukumaran

गुवाहाटी
सौमार सोनोवाल
Guwahati
Saumar Sonowal

हैदराबाद
विजय कृष्णा रेड्डी
Hyderabad
Vijay Krishna Reddy

कोलकाता
हितेन्द्र रावल
Kolkata
Hitendera Rawal

मुंबई
दीपाली अग्रवाल
Mumbai
Deepali Agrawal

नई दिल्ली
सुनील त्रिखा
New Delhi
Sunil Trikha

पुणे
आर. डब्ल्यू. खन्ना
Pune
R. W. Khanna

विदेश स्थित कार्यालय

Overseas Offices

बुडापेस्ट
निर्मित वेद
Budapest
Nirmit Ved

ज़ोहॉनिस्बर्ग
संजीव कुमार पवार
Johannesburg
Sanjeev Kumar Pawar

मिलान
जे. सॅम्युअल जोसेफ
Milan
J. Samuel Joseph

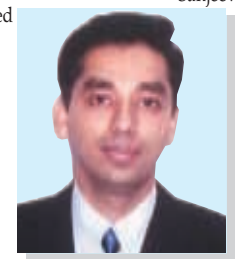

सिंगापोर
भानु अभिलाषी
Singapore
Bhanu Abhilashi

वाशिंग्टन डी. सी.
तरुण शर्मा
Washington D. C.
Tarun Sharma

एक्ज़िम बैंक का उद्देश्य भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करना है। यह प्रतीक चिह्न इस उद्देश्य को प्रकट करता है। इस प्रतीक चिह्न का दोतरफा वैशिष्ट्य है। आयात से संबधित भुजा निर्यात वाली भुजा से पतली है। यह चिह्न निर्यातों में मूल्य योजन के उद्देश्य को भी प्रकट करता है।

The Exim Bank aims to promote India's international trade. The Logo reflects this. The Logo has a two-way significance. The import arrow is thinner than the export arrow. It also reflects the aim of value addition to exports.

उद्देश्य

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना " देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई है..."

: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981.

Objectives

The Export-Import Bank of India was established "for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade ..."

: The Export-Import Bank of India Act, 1981.

प्रधान कार्यालय

केंन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई-400 005.
दूरभाष : (022) 2218 5272 फैक्स : (022) 2218 2572
वैब साइट : www.eximbankindia.com ई-मेल : eximcord@vsnl.com

HEADQUARTERS

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005.
Phone: (022) 22185272 Fax: (022) 22182572
Website : www.eximbankindia.com E-Mail : eximcord@vsnl.com

कार्यालय OFFICES

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद
साकार II, पहली मंज़िल,
एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के आगे,
एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद 380 006.
दूरभाष : (079) 26576852/43
फैक्स : (079) 26578271
ई-मेल : eximindad1@sancharnet.in

बैंगलोर
रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल,
18, एम. जी. रोड, बैंगलोर 560 001.
दूरभाष : (080) 25585755/25589101-04
फैक्स : (080) 25589107
ई-मेल : eximbro@blr.vsnl.net.in

चेन्नई
यू टी आइ हाउस, पहली मंज़िल,
29, राजाजी सालै, चेन्नई 600 001.
दूरभाष : (044) 25224714/49
फैक्स : (044) 25224082
ई-मेल : chenexim@vsnl.net

गुवाहाटी
चौथी मंज़िल, सम्मति प्लाज़ा
सेंटिनेल बिल्डिंग के पास, जी. एस. रोड,
गुवाहाटी 781 005.
दूरभाष : (0361) 2340 893/2599135
फैक्स : (0361) 2340 892
ई-मेल: saumar@eximbankindia.com

हैदराबाद
गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल,
6-3-639/640, राज भवन रोड,
खैरताबाद, हैदराबाद 500 004.
दूरभाष : (040) 23307816-21
फैक्स : (040) 23317843
ई-मेल : eximhyd@vsnl.net

कोलकाता
वाणिज्य भवन, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार
सुगमीकरण केंद्र) चौथी मंज़िल
1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
दूरभाष : (033) 22833419/22833420
फैक्स : (033) 22891727
ई-मेल : eximca@vsnl.com

मुंबई
मेकर चेंबर्स IV, आठवीं मंज़िल,
222, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.
दूरभाष : (022) 22830761/22823320
फैक्स : (022) 22022132
ई-मेल : eximwrro@vsnl.com

नई दिल्ली
तल मंज़िल, स्टेट्समैन हाउस,
148, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110 001.
दूरभाष : (011) 23326254/6625
फैक्स : (011) 23322758/1719
ई-मेल : eximnd@vsnl.com

संयुक्त उद्यम:

- ग्लोबल प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट्स लि., मुंबई
  वेबसाइट: www.gpcl-e.com

पुणे
44, शंकरशेठ रोड, पुणे 411 037.
दूरभाष : (020) 26458599
फैक्स : (020) 26458846
ई-मेल : eximpune@vsnl.com

विदेश स्थित कार्यालय

बुडापेस्ट
तीसरी मंज़िल, यूनिट 308, ई सी ई सिटी सेंटर,
बॉयची-ज़िलिंस्की उट, 12,
1051 बुडापेस्ट, हंगरी
दूरभाष : (00361) 3382833/3176699
फैक्स : (00361) 3178354
ई-मेल : eximindia@axelero.hu

जोहॉनिस्बर्ग
158, जन स्मट्स, तल मंज़िल 9,
वाल्टर्स एवेन्यू, रोज़बैंक,
जोहॉनिस्बर्ग 2196,
पी. ओ. बॉक्स 2018, सेक्सनवॉल्ड 2132
जोहॉनिस्बर्ग, दक्षिण अफ़्रीका
दूरभाष : (002711) 4428010/4422053
फैक्स : (002711) 4428022
ई-मेल : eximindia@icon.co.za

मिलान
वाया डिस्पिलिनी 7,
20123 मिलान, इटली
दूरभाष : (003902) 58430546
फैक्स : (003902) 58302124
ई-मेल : exim.india@tin.it

सिंगापोर
20, कोलियर की, # 10-02, तुंग सेंटर,
सिंगापोर 049319.
दूरभाष : (0065) 65326464
फैक्स : (0065) 65352131
ई-मेल : eximbank@singnet.com.sg

वाशिंग्टन डी.सी.
1750 पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एन.डब्ल्यू.,
सूट 1202, वाशिंग्टन डी.सी. 20006
संयुक्त राज्य अमेरिका
दूरभाष : (001) - 202 - 223-3238/3239
फैक्स : (001) - 202 - 785-8487
ई-मेल : indexim@worldnet.att.net

- ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रा. लि., मुंबई
  वेबसाइट: www.gtfindia.com

DOMESTIC OFFICES

Ahmedabad
Sakar II, Floor 1,
Next to Ellisbridge Shopping Centre,
Ellisbridge P.O., Ahmedabad 380 006.
Phone : (079) 26576852/43
Fax : (079) 26578271
E-Mail : eximindad1@sancharnet.in

Bangalore
Ramanashree Arcade, Floor 4,
18, M.G. Road, Bangalore 560 001.
Phone : (080) 25585755/25589101-04
Fax : (080) 25589107
E-Mail : eximbro@blr.vsnl.net.in

Chennai
UTI House, Floor 1,
29, Rajaji Salai, Chennai 600 001.
Phone: (044) 25224714/49
Fax: (044) 25224082
E-Mail: chenexim@vsnl.net

Guwahati
4th Floor, Sanmati Plaza,
Near Sentinel Building,
G. S. Road,
Guwahati 781 005.
Phone : (0361) 2340893/2599135
Fax: (0361) 2340892
E-Mail: saumar@eximbankindia.com

Hyderabad
Golden Edifice, 2nd Floor,
6-3-639/640, Raj Bhavan Road,
Khairatabad, Hyderabad 500 004.
Phone: (040) 23307816-21
Fax : (040) 23317843
E-mail : eximhyd@vsnl.net

Kolkata
Vanijya Bhawan (International
Trade Facilitation Centre), 4th Floor,
1/1 Wood Street, Kolkata - 700 016.
Phone: (033) 2283 3419 / 2283 3420
Fax: (033) 2289 1727
E-Mail: eximca@vsnl.com

Mumbai
Maker Chambers IV, Floor 8,
222, Nariman Point, Mumbai 400 021.
Phone : (022) 22830761/22823320
Fax : (022) 22022132
E-Mail: eximwrro@vsnl.com

Joint Ventures:

- Global Procurement Consultants Ltd., Mumbai
  Website: www.gpcl-e.com

New Delhi
Ground Floor, Statesman House,
148, Barakhamba Road,
New Delhi 110 001.
Phone : (011) 23326254/6625
Fax: (011) 23322758/1719
E-Mail : eximnd@vsnl.com

Pune
44, Shankarseth Road, Pune 411 037
Phone : (020) 26458599
Fax : (020) 26458846
E-Mail : eximpune@vsnl.com

OVERSEAS OFFICES

Budapest
Floor 3, Unit 308, ECE City Centre,
Bajcsy-Zsilinszky UT. 12,
1051 Budapest, Hungary
Phone : (00361) 3382833/3176699
Fax : (00361) 3178354
E-Mail : eximindia@axelero.hu

Johannesburg
158, Jan Smuts, Ground Floor,
9, Walters Avenue, Rosebank,
Johannesburg 2196,
P.O. Box 2018, Saxonwold 2132,
South Africa
Phone: (002711) 4428010/4422053
Fax: (002711) 4428022
E-Mail : eximindia@icon.co.za

Milan
Via Disciplini, 7, 20123 Milan, Italy
Phone : (003902) 58430546
Fax : (003902) 58302124
E-Mail : exim.india@tin.it

Singapore
20, Collyer Quay, # 10-02 Tung Centre,
Singapore 049319
Phone: (0065) 65326464
Fax: (0065) 65352131
E-Mail : eximbank@singnet.com.sg

Washington D.C.
1750 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1202,
Washington D.C. 20006 U.S.A.
Phone: (001) 202-223-3238/3239
Fax: (001) 202-785-8487
E-Mail : indexim@worldnet.att.net

- Global Trade Finance Pvt. Ltd., Mumbai
  Website: www.gtfindia.com

Sp Inside

दक्षिण-दक्षिण व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना

हाल के वर्षों में वैश्विक व्यापार और निवेश प्रवाह में संवृद्धि के महत्त्वपूर्ण संवाहक के रूप में विकासशील देशों (दक्षिण) का बढ़ता उभार दिखाई दिया है । इस उभरती प्रवृत्ति की एक महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति वैश्विक बाज़ार में दक्षिण के हिस्से में अस्सी के दशक के मध्य में लगभग 20 प्रतिशत से वर्तमान में लगभग 37 प्रतिशत की वृद्धि रही है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 में तीव्र गिरावट के बाद वर्ष 2002 में वैश्विक व्यापार में सुधार और उसके बाद उछाल काफी सीमा तक विकासशील देशों के व्यापार में लगातार प्रभावशाली वृद्धि के कारण आया है जो वैश्विक औसत स्तर से काफी अधिक था ।

दक्षिण, वैश्विक बाज़ारों में एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में लगातार उभर रहा है । वर्ष 2003 में संयुक्त राज्य ने विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों से माल का अधिक आयात किया जबकि इसका 40 प्रतिशत से अधिक निर्यात विकासशील देशों को किया गया ।

इसके अतिरिक्त दक्षिण अब जापान के निर्यात के आधे से अधिक के लिए गंतव्य और उसके लगभग दो -तिहाई आयात के लिए स्रोत तथा यूरोपीय संघ के व्यापार के लिए भी एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है । सहवर्ती रूप से, दक्षिण-दक्षिण व्यापार में भी प्रभावशाली वृद्धि हुई है । वर्तमान में विकासशील देशों का 40 प्रतिशत से अधिक निर्यात अन्य विकासशील देशों को हो रहा है । विकासशील देशों के व्यापार के संघटन में भी प्राथमिक पण्यों की तुलना में विनिर्मित वस्तुओं का बढ़ता हिस्सा दिखाई देता है ।

अंतरराष्ट्रीय निवेश प्रवाहों में भी इसी प्रकार की प्रवृत्तियां उभर रही हैं । 2003 में, विकासशील देशों से विदेशी निवेशकों का बहिर्वाह कुल विश्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बहिर्वाह का 10.5 प्रतिशत और प्रत्यक्ष विदेश निवेश के विश्व प्रवाह का लगभग 5.8 प्रतिशत रहा है।

अनेक विकासशील देशों में रणनीतिक व्यापार संबंद्ध नीतिगत उपाय, उत्पादन प्रणाली का भूमंडलीकरण, उत्पादन तथा व्यवसाय के कारकों की गतिशीलता, मांग के स्वरूप तथा बाज़ार पहुँच स्थितियों में परिवर्तन, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और प्रौद्योगिकी परिवर्तन इन सभी ने दक्षिण को वैश्विक तथा क्षेत्रीय वृद्धि के गतिशील केंद्रों के रूप में उभरने में योगदान दिया है । विकासशील देश इन परिवर्तनों तथा श्रम के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण में परिणामी बदलाव, जो विनिर्माण और हाल ही में सेवाओं की बढ़ती आउटसोर्सिंग में दिखाई देती है, का लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में हैं ।

इन सकारात्मक गतिविधियों का लाभ उठाते हुए दक्षिण-दक्षिण व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने का उत्तरदायित्व स्वयं विकासशील देशों के कंधों पर है । विकासशील देशों की सरकारों को परामर्श तथा सहयोग के रास्तों को खुला रखना चाहिए और प्रमुख क्षेत्रों की ओर संयुक्त पहलें तथा कार्यकलाप शुरू करने चाहिए जो दक्षिण-दक्षिण व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग में हो रहे परिवर्तनों को सुदृढ़ तथा विस्तारित करेंगे ।

विषय सूची

निदेशक मंडल	1
गत दशक	2
अध्यक्ष का वक्तव्य	3
आर्थिक परिवेश	7
निदेशकों की रिपोर्ट	20
तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखा	43

Enhancing South-South Trade and Economic Cooperation

Global trade and investment flows, in recent years, have witnessed the increasing emergence of developing countries (South) as important drivers of growth. An important manifestation of this emerging trend has been the rise in the South's share in global trade from around 20 per cent in the mid-1980s to around 37 per cent at present. Further, the rebound in global trade in 2002, after a sharp decline in 2001, and the subsequent upturn thereafter, has, to a large extent, been due to the sustained robust trade growth of the developing countries, well above the global average.

The South is increasingly emerging as an important producer and consumer in global markets. In 2003, the US imported more goods from developing countries than from developed countries, while more than 40 per cent of its exports were to developing countries.

Further, the South is now destination for more than half of Japan's exports, the source for almost two-thirds of its imports, and also accounts for a significant share of the EU's trade. Simultaneously, South-South trade has also witnessed dramatic rise, with over 40 per cent of developing countries' exports currently being directed to other developing countries. Composition of developing countries' trade has also witnessed the increasing share of manufactured goods as compared to that of primary commodities.

Similar patterns are also emerging in international investment flows. In 2003, FDI outward stock and FDI outflows from developing countries accounted for 10.5 per cent of total world FDI outward stock and around 5.8 per cent of world FDI outflows, respectively.

Strategic trade-related policy measures in many developing countries, globalisation of production systems, mobility of factors of production and business, changes in demand patterns and market access conditions, cost competitiveness and technological changes, among others, have contributed to the South emerging as a dynamic centre of global and regional growth. Developing countries, today, are better placed to leverage on these changes and the resulting shifts in the international division of labour, which is reflected in the increasing outsourcing of manufacturing, and more recently of services, to developing countries.

To build upon these developments, the responsibility of enhancing South-South trade and economic cooperation lies with developing countries themselves. Governments in developing countries need to keep channels of consultation and cooperation open, and direct joint initiatives and activities towards key areas which would consolidate and expand the transformation taking place in South-South trade, investment and economic cooperation.

CONTENTS

Board of Directors	1
The Past Decade	2
Chairman's Statement	3
Economic Environment	7
Directors' Report	20
Balance Sheet and Profit & Loss Account	43

इंटरनेट पर इस रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए कृपया आप हमें **www.eximbankindia.com** पर देखिए
To access this Annual Report on Internet, visit us at **www.eximbankindia.com**